



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29102020-222835
CG-DL-E-29102020-222835

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 318] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 29, 2020/कार्तिक 7, 1942
No. 318] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 29, 2020/KARTIKA 7, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2020

अंतिम जांच परिणाम

मामला सं. (एसएसआर)-01/2020

विषय : चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “कास्टिक सोडा” के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा।

क. मामले की पृष्ठभूमि

फा. सं. 7/1/2020-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे बाद में “अधिनियम” भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संकलन तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां “नियमावली” भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए:

- निर्दिष्ट प्राधिकारी(जिसे आगे “प्राधिकारी” कहा गया है) को चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य (जिसे आगे “संबद्ध देश” कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “कास्टिक सोडा” (जिसे आगे “संबद्ध वस्तु” अथवा “विचाराधीन उत्पाद” भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच (एसएसआर) की शुरुआत करने का अनुरोध करते हुए अलकाली मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (एएमएआई) (जिसे आगे “आवेदक” भी कहा गया है) से टीपीएम कन्सलटेंट्स के माध्यम से दिनांक 4 जनवरी, 2020 को एक आवेदन प्राप्त हुआ।

2. मूल जांच की शुरुआत चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कास्टिक सोडा के संबंध में घरेलू उद्योग पर पाटन और इसके क्षतिकारक प्रभाव की प्रकृति और सीमा की जांच करने के लिए 14 मई, 2002 को की गई थी। प्राधिकारी ने दिनांक 21 सितंबर, 2002 की अपनी प्रारंभिक जांच परिणाम सं. 14/10/2002-डीजीएडी के माध्यम से संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटन आयातों के विरुद्ध अनंतिम शुल्क जिसे दिनांक 26 दिसंबर, 2002 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 142/2002-सीमा शुल्क के माध्यम से लगाया गया था, को लगाने की सिफारिश की। उसके बाद प्राधिकारी ने दिनांक 4 अगस्त, 2003 को अपनी अंतिम जांच परिणाम संख्या 14/10/2002-डीजीएडी के माध्यम से पाटनरोधी शुल्कों को लगाए जाने की सिफारिश की जिन्हें पांच वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 23 सितंबर, 2003 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 142/2003-सीमा शुल्क के माध्यम से लागू किया गया था।
3. प्राधिकारी ने 22 नवंबर, 2007 को निर्णायक समीक्षा की शुरुआत की। प्राधिकारी ने दिनांक 21 नवंबर, 2008 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 15/11/2007-डीजीएडी के माध्यम से संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के विरुद्ध निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को लगातार लगाए रखने की सिफारिश की। प्राधिकारी के जांच परिणामों को दिनांक 26 दिसंबर, 2008 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 137/2008-सीमा शुल्क के माध्यम से लागू किया गया था और उन शुल्कों को आगे पांच वर्षों की अवधि के लिए जारी रखा गया था।
4. आवेदक के अनुरोध पर, प्राधिकारी ने दिनांक 8 जून, 2010 की अधिसूचना सं. 15/2/2010 -डीजीएडी के माध्यम से कोरिया गणराज्य से आयातों के विरुद्ध एक मध्यावधि समीक्षा जांच की शुरुआत की। प्राधिकारी ने दिनांक 7 जुलाई, 2011 की अधिसूचना सं. 15/2/2010-डीजीएडी के माध्यम से पाटनरोधी शुल्कों में संशोधन करने की सिफारिश की जिन्हें दिनांक 3 अक्तूबर, 2011 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 95/2011-सीमा शुल्क के माध्यम से लागू किया गया था।
5. प्राधिकारी ने 19 दिसंबर, 2013 को एक दूसरी निर्णायक समीक्षा की शुरुआत की। प्राधिकारी ने दिनांक 18 जून, 2015 की अधिसूचना सं. 15/23/2013-डीजीएडी के माध्यम से संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के विरुद्ध निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को लगातार लगाए रखने की सिफारिश की। प्राधिकारी के जांच परिणामों को दिनांक 18 अगस्त, 2015 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 42/2015-सीमा शुल्क(एडीडी) के माध्यम से लागू किया गया था।
6. इस अधिनियम की धारा 9क(5) के संदर्भ में, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क यदि उसे पूर्व में समाप्त नहीं किया गया हो, इस प्रकार के अधिरोपण की तिथि से पांच वर्षों के समाप्त होने पर प्रभावी नहीं रहेगा और प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य की समीक्षा करें कि क्या पाटनरोधी शुल्कों के समाप्त होने के फलस्वरूप पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है। इसके अलावा, इस नियमावली के नियम 23(1ख) में निम्नलिखित प्रावधान है:
"इस अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क उसके लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा, यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त अवधि से पूर्व अपनी खुद की पहल पर या घरेलू उद्योग की ओर से किए गए विधिवत पुष्टिकृत अनुरोध के आधार पर उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व उचित अवधि के भीतर इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं कि उक्त पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।"
7. उपर्युक्त के अनुसार, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से विधिवत् रूप से प्रमाणित अनुरोध के आधार पर इस तथ्य की समीक्षा करें कि क्या पाटनरोधी शुल्कों की समाप्ति के फलस्वरूप पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है।
8. आवेदक ने पूर्व में लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत का अनुरोध करते हुए और चीन जन.गण. तथा कोरिया गणराज्य से कास्टिक सोडा के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखने की मांग करते हुए दिनांक 4 जनवरी, 2020 को आवेदन दायर किया। यह अनुरोध उन आधारों के आधार पर किया गया था कि शुल्क की समाप्ति के फलस्वरूप संबद्ध वस्तुओं के पाटन के जारी रहने अथवा इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना थी।

9. घरेलू उद्योग की ओर से दायर किए गए पाटन और क्षति की संभावना के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के साथ विधिवत् रूप से प्रमाणित आवेदन को देखते हुए तथा इस नियमावली के नियम 23 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, प्राधिकारी ने संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में पाटनरोधी शुल्कों को लगातार लगाए रखने के लिए आवश्यकता की समीक्षा करने तथा इस तथ्य की जांच करने कि क्या उक्त पाटनरोधी शुल्कों की समाप्ति के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है, दिनांक 7 फरवरी, 2020 की अधिसूचना सं. 7/1/2020-डीजीटीआर के माध्यम से निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत की।
10. जांच की समाप्ति के लंबित रहने तक, पाटनरोधी शुल्कों का समय विस्तार दिनांक 17 अगस्त, 2020 की अधिसूचना सं. 25/2020-सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से किया गया था।

ख. प्रक्रिया

11. वर्तमान समीक्षा के दायरे में दिनांक 4 अगस्त, 2003 की अंतिम जांच परिणाम सं. 14/10/2002-डीजीएडी, अंतिम जांच परिणाम सं. 15/11/2007-डीजीएडी दिनांक 21 जून, 2008 और अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 15/23/2023-डीजीएडी दिनांक 18 जून, 2015 के सभी पहलू शामिल हैं जिसके द्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्कों को क्रमशः लगाए जाने अथवा जारी रखने की सिफारिश की गई थी।
12. इसमें नीचे वर्णित प्रक्रिया पालन किया गया है:
 - i. प्राधिकारी ने दिनांक 7 फरवरी, 2020 की अधिसूचना सं. 7/1/2020-डीजीटीआर के माध्यम से संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के विरुद्ध निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में एक आम नोटिस प्रकाशित किया।
 - ii. आम नोटिस की एक प्रति प्राधिकारी द्वारा भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अग्रेषित की गई थी ताकि इस नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार संबद्ध जांच की शुरुआत के बारे में उन्हें सूचित किया जा सके।
 - iii. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा सरकारों को उनके दूतावासों के माध्यम से तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों जिन्होंने लिखित रूप में उसके लिए अनुरोध किया, को आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति उपलब्ध कराई। आवेदन के अगोपनीय पाठ की प्रति सार्वजनिक फाइल में भी उपलब्ध कराई गई थी और जहां भी अनुरोध किया गया, अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई थी।
 - iv. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हुए आम सूचना की एक प्रति अग्रेषित की और उन्हें जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में यथा-निर्धारित समय सीमा के भीतर अथवा बढ़ाई गई समय-सीमा तक निर्धारित रूप में और तरीके से प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने के लिए तथा इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार लिखित रूप में अपने दृष्टिकोणों से अवगत कराने का अवसर दिया।
 - v. प्राधिकारी ने निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को अधिसूचना की प्रतियां अग्रेषित की:
 - क. बुम चांग इन्ड.लिमिटेड
 - ख. डीसी केमिकल्स लिमिटेड
 - ग. डोंगयिंग सिटी लोंगक्सिन केमिकल क.
 - घ. इन्वा साल्यूशंस कारपोरेशन
 - ड. हांग इन केमिकल कं. लिमिटेड
 - च. हुआंगुआ तियाक्सिन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

- छ. जिंगहुआ तियाक्सिन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- ज. एलजी केम लिमिटेड
- झ. लोटे पुइन केमिकल कं. लि.
- ञ. मुदनजियान जियांगडा केमिकल्स कार्पो.
- ट. एन.के.एग्रो केमिकल कं. लि.
- ठ. ओसीआई कंपनी लिमिटेड
- ड. क्विनडाओ हिसिया केम कं. लि.
- ढ. सैमसंग पुइन केमिकल्स कं.
- ण. संघाई क्लोर एल्काली केमिकल्स
- त. एसएस फार्म कं., लिमिटेड
- थ. तियांगजिन बोहाई केमिकल इंडस्ट्रीज इम्पोर्ट ऐंड एक्सपोर्ट कार्पो.
- द. तियांगजिन डागु इन्टरनेशनल कार्पो.
- ध. तियांगजिन तियानकई केमिकल इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट ऐंड एक्सपोर्ट कारपोरेशन
- न. जियान केमिकल कं., लिमिटेड
- प. यंगजिन जिन केमिकल कं. लिमिटेड
- vi. संबद्ध देशों की सरकारों से भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें। ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को पत्र और प्रश्नावली की भेजी गई प्रति भी संबंधित संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पते के साथ संबद्ध देशों के दूतावासों को भेजी गई थी।
- vii. चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया:
- क. बोहाई केमिकल (एचके) लिमिटेड
- ख. हन्वा साल्यूशन कारपोरेशन
- ग. मित्सुबिशि कारपोरेशन
- घ. तायनजिन बोहाई केमिकल इंडस्ट्रीज इम्पोर्ट ऐंड एक्सपोर्ट कारपो.
- ड. तायनजिन डागु केमिकल्स कं., लि.
- च. ट्राइकॉन एनर्जी लि.
- viii. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना की मांग करते हुए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को अधिसूचना की प्रति अग्रेषित की:
- क. अभय केमिकल्स लिमिटेड
- ख. अदानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
- ग. अदानी विलमार लिमिटेड
- घ. अल्ब्राइट विल्सन केमिकल्स लिमिटेड
- ड. अरविंद मिल्स लिमिटेड
- च. बिलाग इंडस्ट्रीज प्रा. लिमि.

- छ. बिरला सेल्युलॉस लिमिटेड
- ज. सी जे शाह एंड कं.
- झ. सेन्ट्रल पल्स मिल्स लिमिटेड
- ञ. सायनाइड्स एंड कमिकल्स कं. प्रोप. हिंदुस्तान डवलपमेंट कार्पो. लिमिटेड
- ट. दौराला आर्गेनिक्स लिमिटेड
- ठ. दीपक नाइट्राइट लिमिटेड
- ड. गोदरेज शॉपस लिमिटेड
- ढ. गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड
- ण. गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड
- त. हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड
- थ. हिंदुस्तान लिंक एंड रेजिन लिमिटेड
- द. हितसु इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- ध. इंडियन फारमर फर्टिलाइजर काओ. लिमिटेड
- न. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड
- प. जयसाईनाथ डायकेम लिमिटेड
- फ. लिबरा फोम्स
- ब. लिंक फार्मा लिमिटेड
- भ. मेघमानी आर्गेनिक्स लिमिटेड
- म. नर्मदा केम्चर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
- य. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
- कक. निरमा लिमिटेड
- खख. पब केमिकल्स (प्रा) लिमिटेड
- गग. प्रोडक्ट्स लिमिटेड
- घघ. रामा न्यूज प्रिंट्स एंड पेपर्स लिमिटेड
- ड.ड. रुबामिन लिमिटेड
- चच. सबैरो आर्गेनिक्स लिमिटेड
- छछ. श्री रामाचन्द्रा स्ट्रा
- जज. टोरेट गुजरात बायोटेक लिमिटेड
- झझ. ट्रांसपेक सिलॉक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- ञञ. वेदांता लिमिटेड (एल्युमिनियम डिविजन)

ix. निम्नलिखित आयातक/प्रयोक्ता/ संस्था ने वर्तमान जांच में प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:

क. वेदांता लिमिटेड

ख. एलुमिनियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया

- x. पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने के लिए अनुरोध का समर्थन केमफैब अल्कालीस लिमिटेड, केमप्लास्ट सनमार लिमिटेड, डीसीएम श्रीराम लिमिटेड, दुर्गापुर केमिकल्स लिमिटेड, गुजरात फ्लूरोकेमिकल्स लिमिटेड, लाइर्स क्लोरो अल्काली लिमिटेड, मेघमणिफिनकेम लिमिटेड, निरमा लिमिटेड, ओरिएंट पेपर मिल्स, पंजाब अल्कालीस एंड केमिकल्स लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लिमिटेड, टाटा केमिकल्स लिमिटेड, टीजीवी सराक लिमिटेड, दि आंध्रा शुगरस लिमिटेड और दि त्रावणकोर-कोचित केमिकल्स लिमिटेड द्वारा किया गया है।
- xi. वर्तमान जांच के उद्देश्य से जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल 2019-दिसंबर, 2019(नौ महीने) है। क्षति के विश्लेषण की अवधि में अप्रैल 2016-मार्च, 2017, अप्रैल 2017-मार्च 2018, अप्रैल 2018-मार्च, 2019 और जांच की अवधि शामिल है।
- xii. जांच की अवधि और पिछले तीन वर्षों के लिए लेन-देनवार आयात संबंधी आंकड़े वाणिज्यिक सूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) और प्रणाली महानिदेशालय (डीजीएस) से लिए गए थे। प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा और मूल्य की गणना करने के लिए डीजीसीआईएंडएस और डीजीएस के आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- xiii. आवेदक से उस सीमा तक अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी, जिस सीमा तक उसे आवश्यक माना गया। घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का सत्यापन उस सीमा तक किया गया था जिस सीमा तक वर्तमान जांच के उद्देश्य से उसे आवश्यक माना गया।
- xiv. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।
- xv. घरेलू उद्योग ने उनके चार्टर्ड/लागत लेखाकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित वित्तीय आंकड़ों को प्रस्तुत किया है। उत्पादन की आदर्शतम लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत(एनआईपी) तथा सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों(जीएएपी) और इस नियमावली के अनुबंध III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं का निर्माण करने और उसकी बिक्री करने की लागत इस प्रकार से तय की गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xvi. इस नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 8 अक्तूबर, 2020 को विडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए हुई आम सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए अवसर भी दिया। सभी पक्षकारों जिन्होंने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए थे, से मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित अनुरोधों के रूप में प्रस्तुत करने तथा उसके बाद प्रति उत्तर अनुरोधों को प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया था।
- xvii. जांच की प्रक्रिया के दौरान इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों और उपलब्ध कराई गई सूचना का समर्थन उस सीमा तक किया गया है, जिस सीमा उन्हें वर्तमान जांच से संगत माना गया है और उस पर इस प्रकटन विवरण में प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त रूप से विचार किया गया है।
- xviii. जांच की प्रक्रिया के दौरान, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की सटीकता के संबंध में अपने आप को संतुष्ट किया जो यथा संभव इस प्रकटन विवरण का आधार बनता है और उस सीमा तक घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों/दस्तावेजों को सत्यापित किया जिस सीमा तक उसे संगत, व्यवहार्य और आवश्यक माना गया।
- xix. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय के रूप में तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न की गई सूचना के रूप में माना गया है। जहां भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।

- xx. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना की जानकारी देने से इंकार किया है अथवा अन्य प्रकार से उपलब्ध नहीं कराई है या जांच में पर्याप्त रूप से बाधा पहुंचाई है, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ऐसे हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी के रूप में माना है और इस प्रकटन विवरण में रिकॉर्ड किया है।
- xxi. उपर्युक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार, जांच के आवश्यक तथ्यों को दिनांक 26 अक्तूबर, 2020 के प्रकटन विवरण के माध्यम से ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किया गया था और उसके संबंध में प्राप्त टिप्पणियों को प्राधिकारी द्वारा संगत माने जाने पर इस अंतिम जांच परिणामों में समाधान किया गया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकांश प्रकटन पश्चात अनुरोध उनके पूर्व के अनुरोधों की पुनरावृत्ति मात्र है। हालांकि, जिस सीमा तक उन्हें संगत माना गया है उस सीमा तक प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच इन अंतिम जांच परिणामों की जा रही है।
- xxii. इन अंतिम जांच परिणामों में *** गोपनीय आधार पर किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और इस नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा वैसी मानी गई सूचना का द्योतक है।
- xxiii. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा ली गई विनिमय दर यूएसडालर=71.24 है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु का दायरा

13. जांच की शुरुआत के चरण में, विचाराधीन उत्पाद को नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित किया गया था:
- “वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद सोडियम हाइड्रोक्साइड (रासायनिक नाम एनएओएच) जिसे कास्टिक सोडा के रूप में सामान्य तौर पर जाना जाता है और जो कोरिया आरओके तथा चीन जन.गण. के मूल का है अथवा वहां से निर्यात किया गया है। कास्टिक सोडा एक इनऑर्गेनिक, साबुन जैसा, काफी हद तक खारापन वाला और गंध रहित रासायनिक पदार्थ है।*
- कास्टिक सोडा का वर्गीकरण सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के अंतर्गत सीमा शुल्क शीर्ष 2815.11 और 2815.12 के अंतर्गत किया जाता है। आईटीसी 8-अंक वर्गीकरण के अनुसार, इस उत्पाद का वर्गीकरण सीमा शुल्क शीर्ष 2815.1101, 2815.1102 और 2815.1200 के अंतर्गत किया जाता है”*

ग.1 घरेलू उद्योग का अनुरोध

14. घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद अथवा समान वस्तु के दायरे के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किया गया है:
- चूंकि वर्तमान जांच पाटनरोधी शुल्क को लगातार लगाए रखने के लिए एक निर्णायक समीक्षा जांच है अतः विचाराधीन उत्पाद वही है जो मूल जांच और पूर्व में किए गए निर्णायक समीक्षा जांच में है।
 - घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा वे वस्तु जिनका भारत में आयात किया गया है, समान वस्तु हैं।

ग.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों का अनुरोध

15. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु के दायरे के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

16. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद सभी प्रकारों का कास्टिक सोडा है। कास्टिक सोडा को रासायनिक रूप से एनएओएच अथवा सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में जाना जाता है। यह एक इनऑर्गेनिक, साबुन जैसा, काफी हद तक खारापन और गंध रहित रासायनिक पदार्थ है।
17. चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, अतः विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही है जो मूल जांच में और उसके बाद की समीक्षा जांच में है। पूर्व की जांच में विचाराधीन उत्पाद को नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित किया गया था।

“वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद सोडियम हाइड्रोक्साइड (रासायनिक नाम एनएओएच) जिसे कास्टिक सोडा के रूप में सामान्य तौर पर जाना जाता है और जो कोरिया आरओके तथा चीन जन.गण. के मूल का है अथवा वहां से निर्यात किया गया है। कास्टिक सोडा एक इनऑर्गेनिक, साबुन जैसा, काफी हद तक खारापन वाला और गंध रहित रासायनिक पदार्थ है और इसका उपयोग पल्प और पेपर के निर्माण, न्यूजप्रिंट, विस्कोस यार्न, स्टेपल फाइबर, एल्युमिनियम, कॉटन, टेक्सटाइल्स, टॉयलेट और लान्डी शाप्स, डिटेरजेंट, डाइस्टफ, ड्रग्स और फार्मास्युटिकल्स, पेट्रोलियम रिफाइनिंग आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में होता है।”

18. विचाराधीन उत्पाद का वर्गीकरण प्रशुल्क कोड 28151110, 28151190 और 28151200 के अंतर्गत अध्याय शीर्ष 28 के अंतर्गत किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण सांकेतिक मात्र है और यह विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
19. कास्टिक सोडा का उत्पादन दो रूपों में अर्थात् लाई और सॉलिड में किया जाता है। तरल रूप को ठोस रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और ठोस रूप को इस उत्पाद की रासायनिक गुणों में बिना किसी परिवर्तन के और आसानी से तरल में फिर से परिवर्तित किया जा सकता है। ठोस रूप में आसानी से भंडारण किया जा सकता है और आसानी से उसकी धुलाई की जा सकती है जबकि तरल रूप आसानी से घुलनशील हैं। अंतिम उपयोग के लिए दोनों रूप प्रतिस्थापनीय और एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाने योग्य हैं।
20. कास्टिक सोडा का औद्योगिक रूप से उत्पादन इलैक्ट्रोलेटिक क्लोरलकली प्रक्रिया के अंतर्गत के द्वारा 50 प्रतिशत घुलनशीलता के रूप में किया जाता है। यह सोडियम क्लोराइड की जलीय घुलनशीलता के इलैक्ट्रोलिसिस को शामिल करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कथोट पर बनता है जहां पानी घटकर हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्साइड इयन बन जाता है। संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए, यह आवश्यक है कि क्लोरीन के साथ एनएओएच की प्रतिक्रिया को रोका जाए। यह तीन में से एक तरीकों में प्रकार के तौर पर किया जाता है जिसमें मरकरी सैल की प्रक्रिया, डायफ्रैगम प्रक्रिया अथवा मेम्ब्रेन सैल प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है।
21. रिकॉर्ड पर सूचना के आधार पर, प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देश से आयात किए गए संबद्ध वस्तुओं में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। ये दोनों भौतिक विशेषताओं, निर्माण प्रक्रिया, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देश, वितरण और विपणन तथा इन वस्तुओं के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ताओं ने इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया है और उपयोग कर रहे हैं। प्राधिकारी यह मानते हैं कि आवेदकों द्वारा निर्मित उत्पाद इस नियमावली के नियम 2(घ) के संदर्भ में संबद्ध देश से भारत में आयात किए जा रहे संबद्ध वस्तुओं की समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग और स्थिति

घ.1 घरेलू उद्योग का अनुरोध

22. आवेदक द्वारा घरेलू उद्योग और स्थिति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. यह आवेदन एलकाली मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया(एएमएआई) द्वारा अपने सदस्यों की ओर से दायर किया गया है। इस एसोसिएशन में इसके सदस्यों के रूप में संबद्ध वस्तुओं के 23 घरेलू उत्पादक हैं जो भारतीय उद्योग की संपूर्णता का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- ii. इस एसोसिएशन के निम्नलिखित सदस्यों ने वर्तमान जांच में भाग लिया है:
 - क. डीसीडब्ल्यू लिमिटेड
 - ख. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - ग. गुजरात एलकालिज एंड केमिकल्स लिमिटेड
 - घ. एसआईईएल केमिकल कॉम्पलेक्स
- iii. आवेदक घरेलू उत्पादकों का कुल घरेलू उत्पादन का 44.61 प्रतिशत है।

- iv. आवेदक घरेलू उत्पादकों ने न तो आयात किया है और न ही वे भारत में संबद्ध वस्तुओं के निर्यातक अथवा आयातक से संबंधित हैं।
- v. शेष उत्पादकों में से 16 उत्पादकों ने पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने का समर्थन किया है।
- vi. घरेलू उद्योग के दायरे में परिवर्तन के संबंध में तर्कों का उत्तर देते हुए यह अनुरोध किया गया था कि कुछ उत्पादकों जिन्होंने पूर्व की जांचों में भाग लिया, का अधिग्रहण ग्रासिम इंडस्ट्रीज द्वारा किया गया है और उन्होंने ग्रासिम की इकाई के रूप में वर्तमान जांच में आंकड़े उपलब्ध कराए हैं।
- vii. घरेलू उद्योग का दायरा पिछले चार वर्षों से प्रत्येक जांच में एक जैसा रहा है।
- viii. इस अनुरोध के उत्तर में कि समर्थन पत्र निर्धारित प्रपत्र के अनुसार नहीं है, यह अनुरोध किया जाता है कि व्यापार नोटिस 11/2018 उन पक्षकारों को इस जांच में भाग लेने की अनुमति देता है जिन्होंने उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। किसी भी स्थिति में नियम 5 के प्रावधान निर्णायक समीक्षाओं में लागू नहीं हैं।
- ix. पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने के लिए अनुरोध का समर्थन केमफैब अल्कालीस लिमिटेड, केमप्लास्ट सनमार लिमिटेड, डीसीएम श्रीराम लिमिटेड, दुर्गापुर केमिकल्स लिमिटेड, गुजरात फ्लूरोकेमिकल्स लिमिटेड, लाइर्स क्लोरो अलकाली लिमिटेड, मेघमणिफिनकेम लिमिटेड, निरमा लिमिटेड, ओरिएंट पेपर मिल्स, पंजाब अल्कालिस एंड केमिकल्स लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लिमिटेड, टाटा केमिकल्स लिमिटेड, टीजीवी सराक लिमिटेड, दि आंध्रा शुगरस लिमिटेड और दि त्रावणकोर-कोचित केमिकल्स लिमिटेड द्वारा किया गया है।

घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों का अनुरोध

23. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा घरेलू उद्योग और स्थिति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. आवेदक एसोसिएशन परिस्थिति, क्षति संबंधी आंकड़ों और जांच के समय के आधार पर सदस्य उत्पादकों के समुच्चय का चयनित रूप से उपयोग करता आया है। जबकि, 13 उत्पादकों ने पहली जांच में और 8 उत्पादकों ने मूल जांच में भाग लिया था, केवल 4 उत्पादक वर्तमान जांच में भाग ले रहे हैं।
- ii. आवेदक एसोसिएशन को केवल उन्हीं उत्पादकों जो क्षति दर्शाते हैं, का चयन करने के लिए अपने विवेकाधिकार का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- iii. घरेलू उद्योग के रूप में शामिल किए गए उत्पादक सब उत्पाद अथवा उप उत्पाद के रूप में क्लोरीन की अपने विवेचना के आधार पर नहीं होनी चाहिए जो इस प्रकार के उत्पादकों की लागत से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है।
- iv. एएमएआई के सदस्यों द्वारा दायर किया गया समर्थन-पत्र उनके कार्य-निष्पादन के बारे में सूचना नहीं देता है जो व्यापार नोटिस संख्या 13/2018 का उल्लंघन है।
- v. याचिकाकर्ता ने यह दावा करते हुए व्यापार नोटिस सं. 13/2018 की आवश्यकताओं का पालन करने से इंकार किया है कि इस प्रकार के व्यापार नोटिस कानून का अधिक्रमण नहीं करते हैं। हालांकि, इस प्रकार का व्यापार नोटिस कानून के विरुद्ध नहीं होने के कारण नियम 6(4) के अनुसार संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए पालन किए जाने की आवश्यकता है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

24. इस नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।”

25. वर्तमान निर्णायक समीक्षा आवेदन एलकाली मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया(एएमएआई) द्वारा अपने सदस्यों की ओर से दायर किया गया है। इस एसोसिएशन में इसके सदस्यों के रूप में संबद्ध वस्तुओं के 23 घरेलू उत्पादक हैं जो भारतीय उद्योग की संपूर्णता का प्रतिनिधित्व करते हैं।
26. एसोसिएशन के निम्नलिखित सदस्यों ने वर्तमान जांच में भाग लिया:
- क. डीसीडब्ल्यू लिमिटेड
ख. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
ग. गुजरात एलकालिज एंड केमिकल्स लिमिटेड
घ. एसआईईएल केमिकल कॉम्पलेक्स
27. ग्रासिम इंडस्ट्रीज के निम्नलिखित सदस्यों ने संगत सूचना उपलब्ध कराई है:
- क. गंजियम
ख. कारवार
ग. नागदा
घ. वेनुकूट
ड. वेरावल
च. विलायत
28. उत्पादकों/निर्यातकों के इस दावे के संबंध में कि आवेदक एसोसिएशन परिस्थिति, क्षति संबंधी आंकड़ों और जांच के समय, के आधार पर उत्पादकों के समुच्चय का चयनित रूप से उपयोग करता रहा है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह आवेदन आवेदक एसोसिएशन द्वारा इसके सदस्यों की ओर से दायर किया गया है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इसके कुछ उत्पादकों जैसे बिहार कास्टिक एंड केमिकल लिमिटेड, जयश्री केमिकल्स लिमिटेड और इंडियन रेयन एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के संयंत्रों का अधिग्रहण किया है। अब इन संयंत्रों ने ग्रासिम के एक भाग के रूप में हिस्सा लिया है। इसके अलावा, प्राधिकारी अथवा आवेदक पर घरेलू उद्योग के उसी दायरे को बनाए रखने के लिए कोई कानूनी दायित्व नहीं है। प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस बात का पता लगाए कि क्या आवेदक कंपनियों का उत्पादन कानून के अंतर्गत घरेलू उद्योग की आवश्यकता को पूरा करता है।
29. आवेदक उत्पादक सामूहिक रूप से कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़े हिस्से तथा 44.91 प्रतिशत उत्पादन करता है। यह भी नोट किया जाता है कि आवेदक उत्पादकों का संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा आयातक से संबंध नहीं है और उन्होंने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। इस कारण से, प्राधिकारी यह मानते हैं कि आवेदक इस नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग है।

ड. गोपनीयता

ड.1 घरेलू उद्योग का अनुरोध

30. आवेदक द्वारा गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए:
- निर्यातकों ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और प्रस्तुत किए गए उत्तरों का अगोपनीय रूपांतर दी गई सूचना को तर्क संगत तरीके से समझने नहीं देता है।
 - निर्यातकों ने निर्यातकों के नामों सहित सभी संगत सूचना जिन्हें मौखिक सुनवाई के समय प्रकट किया गया था, के संबंध में गोपनीयता का दावा कर नियम 7 का दुरुपयोग किया है। निर्यातकों के गोपनीयता के दावे प्रोपराइटरी अथवा संवेदनशील सूचना तक सीमित नहीं है।
 - उत्तरों का 70-80 प्रतिशत को संशोधित किया गया है और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना को भी गोपनीयता के रूप में दावा किया गया है।

- iv. प्राधिकारी को सूचना की गोपनीयता बिल्कुल नहीं मानना चाहिए और उन्हें इस बात की अवश्य जांच करनी चाहिए कि क्या पक्षकार द्वारा दावा पक्षकार के अधिकारों और कानूनी हितों के लिए अधिकारिक है अथवा नहीं।
- v. निर्यातकों को इस बात पर जोर देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि घरेलू उद्योग ओर निर्यातकों द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के लिए अलग-अलग मानदंड अपनाए जाने चाहिए।
- vi. निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तरों के भाग II के लगभग पूरे हिस्से को गोपनीय के रूप में दावा किया है जो संभावना के विश्लेषण के लिए आवश्यक है।
- vii. निर्यातकों ने व्यापक चरण-वार निर्माण प्रक्रिया, उपयोग किए गए कच्चे माल और विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री में लगे संबंधित पक्षकारों के नामों के संबंध में गोपनीयता का दावा कर व्यापार नोटिस 10/2018 का उल्लंघन किया है।
- viii. प्रश्नावली का उत्तर निर्यातकों द्वारा अपनाए गए वितरण के माध्यम को प्रकट नहीं करते हैं जो इस बात का पता लगाने के लिए आवश्यक है कि क्या सभी प्रतिष्ठान जो इस प्रकार के माध्यमों का हिस्सा हैं, ने इस जांच में भाग लिया है अथवा नहीं।
- ix. घरेलू उद्योग ने इसके द्वारा दावा की गई गोपनीयता को न्यायोचित ठहराया है।
- x. चूंकि आईसीआईएस रिपोर्ट घरेलू उद्योग की प्रोपराइटी सूचना नहीं है बल्कि बाजार अनुसंधान एजेंसी की प्रोपराइटी सूचना है और वह प्रकटन किए जाने योग्य नहीं है। इसके अलावा, इस प्रकार की रिपोर्टों से सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त कीमतें पहले ही याचिका में प्रकट की गई हैं।
- xi. निर्यात कीमतों की प्रवृत्ति के संबंध में सूचना पहले ही घरेलू उद्योग द्वारा दिनांक 30 मई, 2020 के पत्र के माध्यम से प्रकट की जा चुकी है।
- xii. वास्तविक लागतों, कीमतों, क्षति रहित कीमत, ब्याज और लाभ के प्रकटन से आपसी प्रतिस्पर्धा, अन्य उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा और अपने ग्राहकों के साथ कीमतों का मोलभाव करने की अपनी क्षमता में याचिकाकर्ता घरेलू उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, प्राधिकारी ने अपनी हाल के जांच परिणामों में गोपनीयता के रूप में इस प्रकार की सूचना को माना भी है।
- xiii. याचिकाकर्ता ने यह प्रकट किया है कि इसे उत्पादकता के लिए औसत मानदंड, मालसूची और निवेश पर लाभ के बारे में पता नहीं है।
- xiv. आरएंडडी खर्च के संबंध में सूचना और संपूर्ण रूप में कंपनी के लिए जुटाई जा रही निधि और वह सूचना जिसका कारण विचाराधीन उत्पाद को नहीं ठहराया जा सकता है, याचिकाकर्ता के तुलन-पत्र के अनुसार है।
- xv. विभिन्न क्षेत्रों में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत गोपनीय है और उसे प्रकट नहीं किया जा सकता है। हालांकि, कीमत में कटौती को रेंज में प्रकट नहीं किया गया है।
- xvi. लेन-देनवार आयात आंकड़े तभी उपलब्ध कराए जाने हैं जब एक्सोटिक डेकोर बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में सेसटेट द्वारा नोट किए गए अनुसार गोपनीय होने का दावा नहीं किया जाता है। चूंकि घरेलू उद्योग ने गोपनीयता का दावा किया है और व्यापार नोटिस 7/2018 के अंतर्गत एक शपथ भी प्रस्तुत की है, इस प्रकार के आंकड़ों को प्रकट किया जाना अपेक्षित नहीं है।

ड.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

31. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित किए हैं:

- i. याचिकाकर्ता ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और (i) अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादन का मूल्य (ii) वास्तविक बिक्री मूल्य, पीबीआईटी, ब्याज और ह्रास (iii) उत्पादकता के लिए औसत उद्योग मानदंड, मालसूची और निवेश पर लाभ (iv) आरएंडडी खर्च, जुटाई गई निधियां (v) निर्यात कीमत की प्रवृत्ति (vi) रेंज के रूप में क्षति रहित कीमत और (vii) विचाराधीन उत्पाद की खरीद मात्रा को प्रकट करने में असफल रहा। यह व्यापार नोटिस 10/2018 के अंतर्गत निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं है।

- ii. याचिकाकर्ता ने आईसीआईएस रिपोर्ट प्रकट नहीं की है जिसका उपयोग सामान्य मूल्य को तय करने के लिए किया गया है।
- iii. याचिकाकर्ता ने प्रारंभिक अनुरोधों, मौखिक सुनवाई और दिनांक 8 अक्तूबर, 2020 के पत्र में बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद लेन-देनवार आयात संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं कराया पाया है। जैसाकि एक्सोटिक डेकोर बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सेसटेट द्वारा नोट किया गया है, उसे एक्सल फार्मेट में उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित था।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

32. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार निरीक्षण के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का अगोपनीय रूपांतर वाले सार्वजनिक फाइल के माध्यम से सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।
33. सूचना की गोपनीयता के संबंध में इस नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:
 - (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।
 - (2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।
 - (3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।
34. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय के रूप में तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न की गई सूचना के रूप में माना गया है। जहां भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं। प्राधिकारी ने सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। घरेलू उद्योग के आयातों, कार्य-निष्पादन संबंधी मानदंडों और क्षति संबंधी मानदंडों से संबंधित सूचना सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध कराई गई है। कार्य-पद्धति के अनुसार व्यापार संवेदनशील सूचना गोपनीय रखी गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोई भी सूचना जो सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध हैं, अगोपनीय के रूप में नहीं माना जा सकता है।
35. प्राधिकारी ने आवेदकों और विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों पर विचार किया है और उसके बारे में संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के संबंध में दावे की अनुमति दी है। प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को नियम 6(7) के अनुसार अनुरोध पर निरीक्षण के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का अगोपनीय रूपांतर वाली सार्वजनिक फाइल उपलब्ध कराई।
36. आईसीआईएस रिपोर्टों (जो अपनाए गए सामान्य मूल्य के आंकड़ों का समर्थन करने के लिए प्रयुक्त अंडरलाइन साक्ष्य होता है) को प्रकट न करने के दावे के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि आवेदक ने इन आधारों पर उसे प्रकट नहीं किया है कि यह तृतीय पक्षकार की सूचना है और सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए उपयोग की गई

कीमतें (जो सूचना होती है) पहले ही हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किया गया है। अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि आईसीआईएस-एलओआर की प्रतिलिपि को प्रकट न करना न्यायोचित है। जहां तक डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों का प्रश्न है, प्राधिकारी यह मानते हैं कि जहां तक भारत को निर्यात करने वाले प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा और मूल्य का प्रश्न है, उसे हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट भी नहीं किया गया है। इसके अलावा, आवेदक ने अलग-अलग देशों से आयातों की मात्रा और मूल्य का परिमाण बताने के लिए आवेदक द्वारा विश्वास किए गए लेन-देनवार आयात आंकड़ों की एक पूर्ण सूची उपलब्ध कराई है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह सिद्ध नहीं किया है कि किस प्रकार से ये प्रकटन वर्तमान मामले में अपने हितों की रक्षा करने के लिए उनके लिए पर्याप्त नहीं है। यह भी नोट किया जाता है कि वर्तमान जांच में भाग लेने वाले कोरिया के उत्पादक ने व्यापक रूप से डीजीसीआईएंडएस में सूचित किए गए आयातों की मात्रा का समर्थन करते हुए आयातों की मात्रा सूचित की है। यह भी नोट किया जाता है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए आयातों का लेन-देनवार ब्यौरा नहीं मांगा है। इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि कोई भी हितबद्ध पक्षकार डीजीसीआईएंडएस से स्वतंत्र रूप से आंकड़ा प्राप्त कर सकता है और आयातों की मात्रा और मूल्य के संबंध में अपना प्रति-दावा कर सकता है। उससे भी बढ़कर प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना को नहीं अपनाया है। प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस और डीजी प्रणाली से स्वतंत्र रूप से सूचना मंगाई है जिसकी पुष्टि विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न सूचनाओं से की गई है और उसके बाद वर्तमान अंतिम जांच परिणाम में अपनी सूचना दी है।

च. विविध मुद्दे

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

37. निम्नलिखित अनुरोध अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए हैं:

- i. प्राधिकारी ने विभिन्न देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर 19 अलग-अलग जांच की है जो व्यापार उपचारात्मक तंत्रों का दुरुपयोग किए जाने को दर्शाता है।
- ii. घरेलू उद्योग को लगातार संरक्षण देना प्रयोक्ता उद्योग के लिए हानिकारक रहा है, वह स्थिति उत्पादों की लागतों में वृद्धि तथा खुद घरेलू उद्योग के लिए बढ़ गया है जो अपनी क्षमताओं, कार्य-क्षमताओं अथवा प्रौद्योगिकियों में सुधार करने में असफल रहा है।
- iii. कास्टिक सोडा एल्युमिना की लागत का 20 प्रतिशत योगदान करता है और इस प्रकार से, शुल्कों के जारी रहने का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, एल्युमिना जैसे डाउनस्ट्रीम उद्योग कच्चे माल पर इन्वर्टेड शुल्क ढांचा के कारण पहले से ही नुकसान में है।
- iv. प्रयोक्ता उद्योग ने घरेलू उद्योग से संबद्ध वस्तुओं की अत्यधिक मात्रा की आपूर्ति करने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए हैं। हालांकि, घरेलू उद्योग उचित कीमतों जिसे विदेशी उत्पादकों द्वारा उन्हें दिया जा रहा है, पर प्रयोक्ताओं के साथ दीर्घ अवधि करार करने के लिए इच्छुक नहीं है और उसकी बजाय इस प्रकार की प्रतिबद्धताओं के लिए अत्यधिक प्रीमियम की मांग की है।
- v. डाउनस्ट्रीम एल्युमिना उद्योग 2018 से पहले ही कीमत अभाव के कारण हानि उठा रहा है और शुल्कों को जारी रखने के साथ यह उद्योग बाजार में संभवतः प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा।
- vi. आयात पर प्रतिबंध के परिणामस्वरूप घरेलू उत्पादकों द्वारा एकाधिकार मूल्य निर्धारण किया जाएगा, जैसा कि 2018-19 में हुआ था।

अन्य मुद्दे

- vi. हन्वा साल्यूशंस कारपोरेशन ने एक अलग नाम परिवर्तन संबंधी आवेदन के माध्यम से माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह सूचित किया था कि दिनांक 6 जनवरी, 2020 से नाम में परिवर्तन लागू हुआ था जिसके द्वारा इसे पूर्व में हन्वा केमिकल कारपोरेशन के रूप में माना जाता था और वर्तमान में इसे हन्वा साल्यूशंस कारपोरेशन के रूप में जाना जाता है।

- vii. माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 6 अगस्त, 2020 के पत्र के मध्यम से नाम में परिवर्तन के बारे में कुछ स्पष्टीकरण और दस्तावेज मांगे थे।
- viii. तदनुसार हन्वा साल्यूशंस कारपोरेशन ने नाम में परिवर्तन के संबंध में सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ दिनांक 27 अगस्त, 2020 को एक विस्तृत उत्तर उपलब्ध कराया।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा का अनुरोध

38. घरेलू उद्योग ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों के उत्तर में निम्नानुसार अनुरोध किया है:
- i. इस दावे के संबंध में कि 19 जांच की हैं, यह अनुरोध किया गया था कि पाटनरोधी शुल्क प्राधिकारी के समक्ष स्थापित तथ्यों के आधार पर लगाया गया है।
 - ii. प्रयोक्ता उद्योग बड़ी हुई लागतों का हवाला देते हुए पाटित आयातों के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि अनुचित कीमत पर आयातों के कारण बाजार में अनुचित प्रतिस्पर्धा होती है।
 - iii. उत्तर देने वाले प्रयोक्ता, वेदांता लिमिटेड को साक्ष्य के साथ शुल्क के प्रतिकूल प्रभाव को प्रमाणित नहीं किया गया है जबकि कुछ अन्य प्रयोक्ताओं ने शुल्कों को जारी रखने पर आपत्ति नहीं की है।
 - iv. इन्वर्टेड शुल्क ढांचा से संबंधित मुद्दों को उपयुक्त मंच के समक्ष और न कि प्राधिकारी के समक्ष प्रयोक्ता द्वारा उठाया जाना चाहिए।
 - v. प्रयोक्ता ने इसी साक्ष्य के माध्यम से संबद्ध वस्तुओं की स्थानीय स्तर पर आपूर्ति करने के अपने दावे किए गए प्रयासों को सिद्ध नहीं किया है। यह उस जटिलता को दर्शाता है कि प्रयोक्ता की पाटित कीमतों पर उपलब्ध आयातों में रुचि है।
 - vi. अन्य कारकों के कारण प्रयोक्ताओं द्वारा सामना की गई कठिनाईयां वर्तमान जांचों के लिए संगत नहीं हैं। एल्युमिनियम उत्पादों से संबंधित की जा रही अनेक जांच ऐसे उत्पादों के पाटन को सूचित करते हैं जिससे प्रयोक्ताओं को कठिनाई हो रही है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

39. संबद्ध वस्तुओं के आयातों संबंध में अनेक जांचों और लगाए गए शुल्कों की लंबी अवधि के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य क्षतिकारक पाटन के विरुद्ध घरेलू उद्योग को केवल समान अवसर तथा राहत देना है। वर्तमान जांच की शुरुआत शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना की जांच करने के लिए की गई है। यदि प्राधिकारी यह पाते हैं कि पाटन और क्षति शुल्कों के न रहने की स्थिति में जारी रहेगा अथवा फिर से होगा, अनेक जांचों अथवा शुल्कों को लगाने की अवधि के बावजूद पाटनरोधी शुल्क का समय विस्तार किया जाएगा। प्राधिकरण यह भी नोट करता है कि प्रभावी पाटनरोधी शुल्क के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग द्वारा एकाधिकार मूल्य निर्धारण का कोई सबूत नहीं है। वास्तव में, देश में उत्पाद के घरेलू उत्पादक बड़ी संख्या में हैं।
40. हन्वा केमिकल कारपोरेशन का नाम बदलकर हन्वा साल्यूशंस कारपोरेशन करने से संबंधित मुद्दों के बारे में, यह नोट किया जाता है कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गई है।
41. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सहयोगी निर्यातक अर्थात् हन्वा केमिकल कारपोरेशन ने 6 जनवरी, 2020 से नाम बदला है और यह हन्वा केमिकल कारपोरेशन के साथ दो कंपनियों के विलय (जो हन्वा ग्रुप का एक हिस्सा था) के कारण हन्वा साल्यूशंस कारपोरेशन हो गया है। यह नोट किया जाता है कि अन्य दो कंपनियां विचाराधीन उत्पाद के निर्माण, वितरण, आयात अथवा निर्यात में शामिल नहीं थी। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि नाम में परिवर्तन कोरिया में लागू कानूनों के अनुसरण में किया जाता है।
42. हन्वा साल्यूशंस कारपोरेशन द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी सहायक दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के बाद, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि इस विलय के परिणामस्वरूप पूर्व कंपनी के स्वामित्व में परिवर्तन नहीं हुआ है और विचाराधीन उत्पाद से संबंधित प्रचालनों पर इसका कोई ठोस प्रभाव नहीं पड़ा है। तदनुसार, हन्वा केमिकल कारपोरेशन से हन्वा साल्यूशंस कारपोरेशन तक नाम में परिवर्तन अंतिम जांच परिणामों में दर्शाया गया है।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन और पाटन मार्जिन का निर्धारण**छ.1 घरेलू उद्योग का अनुरोध**

43. घरेलू उद्योग द्वारा, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का सतत पाटन हुआ है और निर्यातकों का पाटन का इतिहास है।
- ii. चूंकि चीन जन.गण. से उत्पादकों ने यह नहीं दर्शाया है कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की शर्तों के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के आधार पर किया जाना चाहिए।
- iii. निर्यात कीमतों का निर्धारण मूल्य चयन की शर्त को पूरा करने के अध्यक्षीय सहयोगी निर्यातकों को उत्तरों के आधार पर किया जा सकता है। हालांकि, चूंकि चीन जन.गण. के उत्तर देने वाले उत्पादक आयात आंकड़ों में एक आपूर्तिकर्ता के रूप में सूचीबद्ध ही नहीं हैं, यह मूल्य चयन की शर्त को पूरा करने पर संदेह उत्पन्न करता है।
- iv. जांच के अधीन देश होने के कारण कोरिया गणराज्य को एक उपयुक्त सरोगेट देश के रूप में नहीं माना जा सकता है।
- v. कोरिया के उत्पादक के आंकड़ों की उपलब्धता इन आंकड़ों की स्वीकार्यता को सूचित नहीं करता है और अतः प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे अनुबंध-1 के पैरा 7 के अंतर्गत शर्तों तथा सरोगेट देश के निर्धारण के लिए शर्तों का मूल्यांकन करें।
- vi. प्रतिवादियों ने इस तथ्य का साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि कोरिया गणराज्य और चीन जन.गण. आर्थिक और उत्पाद विकास के समान स्तर पर हैं। इस प्रकार से, कोरिया गणराज्य की बिक्री कीमत को चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, कोरिया गणराज्य से भारत को पाटित किए जा रहे निर्यातों का भी उपयोग चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु नहीं किया जा सकता है।
- vii. चीनी ताइपेई में संबद्ध वस्तुओं की कीमत आईएचएस बाजार रिपोर्ट के आधार पर उपलब्ध कराया गया है जो बाजार में प्रचलित कीमतों का एक व्यापक दृष्टिकोण देता है।
- viii. चूंकि मूल जांच में भी हन्वा सॉल्युशंस कारपोरेशन का पाटन मार्जिन नकारात्मक है अतः याचिकाकर्ता यह मानते हैं कि वर्तमान जांच में इसके निर्यातों के विरुद्ध कोई शुल्क नहीं लगाया जा सकता है।
- ix. कोरिया गणराज्य से शेष उत्पादकों/निर्यातकों के लिए शुल्क का निर्धारण इस याचिका में उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर किया जाना चाहिए।

छ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों का अनुरोध

44. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किया गया उत्तर दर्शाता है कि सहयोगी निर्यातों द्वारा कोई पाटन नहीं किया गया है।
- ii. निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तरों पर विचार सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटित मार्जिन के निर्धारण के उद्देश्य से किया जाना चाहिए।
- iii. चूंकि वर्तमान मामले में, कोरिया गणराज्य में उत्पादन की लागत तथा घरेलू और तृतीय देश की बिक्री के संबंध में आंकड़े प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध हैं, अतः कोरिया गणराज्य को एक उपयुक्त सरोगेट देश के रूप में माना जाना चाहिए। यह अनुबंध-1 के प्रावधानों, एसओपी का मैन्युअल और शेनयांग मस्तुशिता

एस. बैट्री कं. लिम. बनाम एक्साइड कंपनी लि. में उच्चतम न्यायालय के फैसले और पूर्व के मामलों में प्राधिकारी की कार्य-पद्धति के अनुसार है।

- iv. कोरिया गणराज्य उपयुक्त सरोगेट देश है क्योंकि दोनों देश आर्थिक विकास और समान उत्पाद विकास के एक ही स्तर पर हैं। इसके अलावा, दोनों देशों में कास्टिक सोडा के लिए बाजार भारत में उसी सीमा शुल्क के अधीन समान क्षमताओं तथा बिल्कुल करीब से तुलनीय आयात मात्राओं के साथ समान उत्पादन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विकास के एक ही स्तर पर हैं।
- v. चूंकि याचिकाकर्ताओं ने यह स्वीकार किया है कि चीनी टाईपेई में बिक्री कीमत का प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि यह चीन से तुलनीय है, चीनी टाईपेई का चयन एक उपयुक्त सरोगेट देश के रूप में करने का कोई आधार नहीं है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

45. धारा 9क(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र से किसी उपयुक्त तीसरे देश को किया गया हो; अथवा

(ख) उपधारा- (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत;

बशर्ते कि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

46. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावलियां भेजी जिसमें उन्हें निर्धारित रूप में और तरीके से सूचना उपलब्ध कराने की सलाह दी गई है। संबद्ध देशों से निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:

- क. बोहाई केमिकल (एचके) लिमिटेड, चीन जन.गण. (चीन मूल की वस्तुओं का निर्यातक)
- ख. तायनजिन बोहाई केमिकल इंडस्ट्रीज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कार्पो. चीन जन.गण (निर्यातक)
- ग. तियानजिन डागु इंटरनेशनल कं. लि. चीन जन.गण(उत्पादक)
- घ. हन्वा साल्यूशंस कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य (उत्पादक)
- ड. मित्सुबिशि कारपोरेशन, जापान (कोरिया मूल की वस्तुओं का निर्यातक)
- च. ट्राइकॉन एनर्जी लि. यूएसए (कोरिया और चीन मूल की वस्तुओं का निर्यातक)

यह नोट किया जाता है कि ट्राइकॉन एनर्जी लिमिटेड के माध्यम से निर्यातों के लिए हन्वा साल्यूशंस कारपोरेशन (हान्वा) के लिए पाटन मार्जिन मूल जांच में न्यूनतम स्तर पर पाया गया था।

छ.3.1 सामान्य मूल्य का निर्धारण

चीन जन.गण. के लिए बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा

47. चाइनीज एसेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

- (क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद- VI और पाटनरोधी करार के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:
- (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
- (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।
- (ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताने समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।
- (ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।
- (घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क) (II) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

48. यह नोट किया जाता है कि जबकि अनुच्छेद 15 (क) (II) में निहित प्रावधान 11-12-2016 को समाप्त हो गया है, प्रवेश नवाचार के 15 (क) (I) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित विश्व व्यापार संगठन के पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान में बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जा का दावा करने के लिए पूरक प्रश्नावली में दिए जाने हेतु सूचना/आंकड़ों के माध्यम से संतुष्ट किए जाने के लिए भारत की नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड अपेक्षित हैं। यह नोट किया जाता है कि चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने पूरक प्रश्नावली नहीं प्रस्तुत की है। तदनुसार, सामान्य मूल्य की गणना इस नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है। संबद्ध देश के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण नीचे दिए गए अनुसार किया गया है।

चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य

49. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने इस नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में यथा उल्लिखित पूर्व मान्यताओं का खंडन करने के लिए पूरक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। उन परिस्थितियों में, प्राधिकारी को इस संबंध में निमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार कार्यवाही करनी है।
50. जबकि घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि चीनी ताइपेई को उपयुक्त सरोगेट देश के रूप में दावा किया जाना चाहिए, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि कोरिया गणराज्य पर इस उद्देश्य से विचार किया जाना चाहिए। हालांकि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकारों ने यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त सूचना नहीं दी है कि चीनी ताइपेई अथवा कोरिया गणराज्य को देश के विकास के उसी स्तर अथवा उत्पाद के विकास के स्तर दोनों के संबंध में अनुबंध-1 के पैरा 7 के अंतर्गत निर्धारित आवश्यकताओं के संबंध में सरोगेट देश के रूप में माना जा सकता है। इस संबंध में किसी साक्ष्य के नहीं होने पर प्राधिकारी ने अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार, उत्पादों के लिए भारत में भुगतान की गई अथवा भुगतान योग्य कीमत के आधार पर चीन जन.गण. के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।
51. उपर्युक्त को देखते हुए चीन जन.गण. से भारत में आयात किए गए विचाराधीन उत्पाद के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक खर्च और लाभ मार्जिन के लिए उचित योग के साथ घरेलू उद्योग के लिए यथा आदर्शतम बनाए गए उत्पादन की लागत के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तदनुसार, सामान्य मूल्य की संरचना पाटन मार्जिन तालिका में दिए गए अनुसार जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए चीन जन.गण. के सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए बनाई गई है।

कोरिया गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

हन्वा सॉल्यूशंस कारपोरेशन, त्रिकॉन एनर्जी लिमिटेड और मित्सुबिशी कारपोरेशन

सामान्य मूल्य

52. जांच की अवधि के दौरान, हन्वा सॉल्यूशंस कारपोरेशन (संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक) ने सीधे घरेलू बाजार में ग्राहकों को विचाराधीन उत्पाद की बिक्री की। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हन्वा ने संबंधित और असंबंधित दोनों ग्राहकों को घरेलू बिक्री की। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि संबंधित ग्राहकों को कीमत असंबंधित ग्राहकों की कीमत से मामूली रूप से अधिक है। तदनुसार, सभी घरेलू बिक्री पर विचार सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से किया गया है। यह भी नोट किया जाता है कि हन्वा सॉल्यूशंस कारपोरेशन की बिक्री घरेलू बाजार में व्याप्त मात्रा में हुई है।
53. सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संबंध में लाभ अर्जित करने वाली घरेलू बिक्री का लेन-देन का निर्धारण करने के लिए व्यापार जांच की सामान्य प्रक्रिया आयोजित की है। यदि लाभ अर्जित करने वाली लेन-देन 80 प्रतिशत से अधिक हो तब प्राधिकारी सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में सभी लेन-देन पर विचार करते हैं। जहां लाभप्रद लेन-देन 80 प्रतिशत से कम है, वहां केवल लाभप्रद घरेलू बिक्री पर विचार सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए किया जाता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि **** प्रतिशत घरेलू बिक्री को लाभप्रद पाया गया है। इस कारण से, सभी बिक्रियों पर विचार सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से किया गया है। इस प्रकार से निर्धारित सामान्य मूल्य का उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

छ.3.2 निर्यात कीमत का निर्धारण

चीन जन गण. से सबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

तायनजिन डागु केमिकल कं., लि., तायनजिन बोहाई केमिकल इंडस्ट्रीज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कारपोरेशन, और बोहाई केमिकल (एचके) लिमिटेड और ट्रायकॉन एनर्जी लिमिटेड

54. जांच की अवधि के दौरान, विचाराधीन उत्पाद के लिए तायनजिन डागु केमिकल कं., लि., द्वारा भारत को सभी बिक्री तायनजिन बोहाई केमिकल इंडस्ट्रीज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कारपोरेशन, बोहाई केमिकल (एचके) लिमिटेड और ट्रायकॉन एनर्जी लिमिटेड के माध्यम से किया गया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि व्यापार माध्यम में

शामिल सभी निर्यातकों ने अपनी अलग-अलग प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं तायनजिन डागु केमिकल कं., लि. से जांच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद का *** मी.टन निर्यात किया है।

55. प्राधिकारी ने सभी तीन सहयोगी ट्रेडिंग कंपनियों नामतः तायनजिन बोहाई केमिकल इंडस्ट्रीज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कारपोरेशन, बोहाई केमिकल (एचके) लिमिटेड और ट्रायकॉन एनर्जी लिमिटेड की लाभप्रदता जांच की है। प्राधिकारी ने सर्वेयर की लागत और व्यापारी का लाभ/हानि (जहां भी लागू हो) पर विचार करने के बाद व्यापारी की निर्यात कीमत के आधार पर कारखानागत निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। इसके अलावा, कीमत समायोजनों की अनुमति समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय भाड़ा, पोर्ट और अन्य संबंधित खर्च के आधार पर दी गई है। इन समायोजनों के बाद निवल निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

चीन जन.गण के अन्य उत्पादक और निर्यातक

56. चीन जन.गण. से अन्य असहयोगी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों और सहयोगी निर्यातकों की प्रश्नावली के उत्तर पर विचार करते हुए उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों के अनुसार किया गया है और उसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

कोरिया गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

57. हन्वा साल्यूशंस कारपोरेशन ("हान्वा") ने अपनी असंबंधित ट्रेडिंग कंपनियों नामतः ट्राइकान एनर्जी लिमिटेड ("ट्राइकान") और मित्सुबिशि कारपोरेशन ("मित्सुबिशि") के साथ प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हन्वा ने जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का ***मी.टन निर्यात किया है।
58. प्राधिकारी ने सभी सहयोगी ट्रेडिंग कंपनियों नामतः ट्राइकान और मित्सुबिशि की लाभप्रदता जांच की है। भारत को निर्यात के सभी व्यापार चैनलों को लाभप्रद पाया गया है और इस कारण से प्राधिकारी ने कारखानागत निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए हान्वा की कीमतों पर विचार किया है। इसके अलावा, उत्पादक ने सर्वेयर लागत, हैंडलिंग शुल्क, क्रेडिट लागत, बैंक शुल्क और घरेलू ब्रोकरेज का दावा भारत को निर्यात करने के लिए कारखाना के बाद के खर्च के रूप में किया है, जिसे प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इन समायोजनों के बाद निवल निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

कोरिया गणराज्य से अन्य उत्पादक और निर्यातक

59. कोरिया गणराज्य से अन्य असहयोगी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों और सहयोगी निर्यातकों की प्रश्नावली के उत्तर पर विचार करते हुए उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों के अनुसार किया गया है और उसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

छ.3.3 पाटन मार्जिन

60. जैसा कि ऊपर में निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर, चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किया गया है और उसे नीचे तालिका में दिया गया है:

देश	उत्पादक	सामान्य मूल्य यूएसडालर/मी.टन	निर्यात कीमत यूएसडालर/मी.टन	पाटन मार्जिन (यूएस डालर/ मी.टन)	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन % रेंज
कोरिया गणराज्य	हन्वा सॉल्यूशंस कारपोरेशन	***	***	***	***	(0-10)
कोरिया गणराज्य	कोई भी	***	***	***	***	0-10
चीन जन.गण.	तायनजिन डागु केमिकल कं. लि.	***	***	***	***	0-10
चीन जन.गण.	अन्य	***	***	***	***	10-20

61. यह नोट किया जाता है कि हान्वा साल्यूशन के मामले में पाटन मार्जिन नकारात्मक है।

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध

ज.1 घरेलू उद्योग का अनुरोध

62. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति, संभावना और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किया गया है:

- i. संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का सतत पाटन हुआ है और निर्यातकों का पाटन का इतिहास है।
- ii. 18 से अधिक वर्षों से संबद्ध वस्तुओं का सतत पाटन दर्शाता है कि शुल्क की मात्रा पाटन से बचने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- iii. विचाराधीन उत्पाद के निर्यातकों ने भी संबद्ध वस्तुओं को तीसरे देशों में स्थापित किया है।
- iv. शुल्कों के लागू रहने के बावजूद, क्षति की अवधि के दौरान पाटन आयातों की मात्रा में 108 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आयातों की मात्रा क्षति की अवधि के दौरान की मात्रा से तुलना किए जाने पर जांच की वर्तमान अवधि में उच्चतम है।
- v. आयातों में वृद्धि की दर मांग में वृद्धि से अधिक दर से हुई है।
- vi. इन आयातों में अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन तथा ऐसे अनिवार्य प्रमाणन की आवश्यकताओं के द्वारा प्रभावित अवधि को बाहर रखने के बावजूद भी हुआ है। अतः यह बिना किसी आधार के है कि बीआईएस मानदंडों के फलस्वरूप आयातों में गिरावट आई है।
- vii. पाटन आयातों में भी उत्पादन और खपत की तुलना में वृद्धि हुई है।
- viii. इसके अलावा, संबद्ध आयातों की कीमत में बहुत तेजी से गिरावट आई है यद्यपि घरेलू उद्योग की लागत में कोई गिरावट नहीं हुई है।
- ix. न केवल भारत की कीमत में कमी आई है बल्कि संबद्ध देशों से तीसरे देशों तक निर्यातों की कीमत में गिरावट हुई है।
- x. जबकि औसत आधार पर कीमत में कटौती नकारात्मक है, यह क्षेत्रवार आधार पर सकारात्मक है।
- xi. जबकि घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में 2018-19 तक सुधार हुआ, यह जांच की अवधि में गिरावट को दर्शाता है क्योंकि आयातों में वृद्धि हुई। यह दर्शाता है कि ये आयात संबद्ध आयातों के द्वारा प्रभावित होना जारी हैं।
- xii. संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं की न केवल अतिरिक्त क्षमताएं हैं बल्कि निर्यातक अपनी क्षमताओं में आगे और विस्तार भी कर रहे हैं। केवल चीन जन.गण. के पास 94.5 लाख मी.टन की अतिरिक्त क्षमताएं हैं जबकि इसकी तुलना में भारत में मांग केवल 26 लाख मी.टन हैं।
- xiii. जबकि अत्यधिक क्षमताएं निर्यातों के लिए सृजित की गई हैं, संबद्ध देशों से कुल निर्यातों में गिरावट आई है जबकि भारत को निर्यातों में वृद्धि हुई है। इस प्रकार से, शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में भारत संभवतः इन निर्यातों को खपाने के लिए एक वैकल्पिक बाजार के रूप में कार्य करेगा।
- xiv. निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए उत्तर यह भी दर्शाते हैं कि जबकि भारत को उनके निर्यातों में वृद्धि हुई है फिर भी उनकी कुल बिक्री को धक्का लगा है।
- xv. पाटनरोधी शुल्क के लागू रहने के बावजूद, भारत संबद्ध देशों में निर्यातकों के लिए एक प्रमुख बाजार रहना जारी है। इस प्रकार से शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में निर्यातक संभवतः इस बाजार पर अपना ध्यान केन्द्रित करेंगे।
- xvi. इसके अलावा भारत संबद्ध देशों में निर्यातकों के लिए एक कीमत आकर्षक बाजार है। इस प्रकार शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में, तीसरे देशों को वर्तमान में किए गए निर्यातों को संभवतः भारत की ओर परिवर्तित किया जाएगा।

- xvii. यदि अन्य देशों से कमतर कीमत पर आयातों को भारत की ओर परिवर्तित किया जाता है तब घरेलू उद्योग की मात्राओं अथवा कीमतों अथवा दोनों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ने की संभावना है।
- xviii. चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा है अतः संभावित पाटन और संभावित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है जैसाकि मेक्सिको से ओसीटीजी पर पाटनरोधी उपायों-संयुक्त राज्य में अपीलीय निकाय द्वारा टिप्पणी की गई है।
- xix. घरेलू उद्योग को किसी अन्य कारक के कारण संभवतः हानि नहीं होगी।
- xx. यदि घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को बनाए रखने का प्रयास करते हैं तब आयात संभवतः इसके बाजार हिस्से को ले जाएगा जिसके फलस्वरूप इसके उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में गिरावट होगी। हालांकि, यदि घरेलू उद्योग अपने ग्राहकों को बनाए रखने का प्रयास करते हैं तब इसकी लाभप्रदता में काफी हद तक नुकसान होने की संभावना है और संभवतः इसे हानि और निवेश पर नकारात्मक प्रभाव का सामना करना पड़ेगा।
- xxi. प्रतिवादियों के अनुरोधों के प्रतिकूल, क्षति की जांच परिभाषित घरेलू उद्योग के लिए न कि समग्र रूप में उद्योग के लिए इसी-ब्रेड लिनन में पैनल की रिपोर्ट और नियम 11(2) के अनुसार किया जाना अपेक्षित है। यूएस-हॉट-रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स में अपीलीय निकाय ने भी यह नोट किया है कि क्षति संबंधी विश्लेषण परिभाषित घरेलू उद्योग के लिए किया जाना है।
- xxii. इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि घरेलू उद्योग को निर्णायक समीक्षा में क्षति हुई भी होगी और प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना की जांच करें।
- xxiii. भारत को निर्यात में वृद्धि हुई है जबकि अन्य देशों को निर्यात में गिरावट आई है, इसका अर्थ यह है कि आयात सार्वजनिक खरीद और बीआईएस प्रमाणन की आवश्यकताओं के बावजूद भविष्य में बढ़ने की संभावना है।
- xxiv. बीआईएस लाइसेंसिंग गुणवत्ता कार्य-विधि का मानकीकरण है और न कि अवरोध। इसके अलावा, निर्यातकों को इसे आवश्यक किए जाने के पूर्व इस प्रकार के लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए चार महीने की अवधि दी गई थी।
- xxv. बीआईएस लाइसेंसिंग प्राधिकारी ने विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों को 18 लाइसेंस जारी किए हैं। निर्यातक की इन वर्षों के बाद भी लाइसेंस प्राप्त करने की असफलता लाइसेंस की शर्तों को पूरा करने में उनकी असमर्थता के कारण और न कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा किसी विलंब के कारण हुई है।
- xxvi. प्रतिवादियों के तर्कों के प्रतिकूल, बीआईएस लाइसेंस को प्रारंभ में दो वर्षों की अवधि के लिए जारी किया गया था लेकिन उसका नवीकरण एक सामान्य और एक लघु प्रक्रिया के माध्यम से पांच वर्षों तक किया जा सकता है जिससे कि निर्यात बिना किसी कठिनाई के लाइसेंस नवीकरण कर सकें।
- xxvii. बीआईएस लाइसेंस को जारी करने में विलंब के संबंध में शिकायतें उपयुक्त मंच के समक्ष और न कि प्राधिकारी के समक्ष उठाया जाना चाहिए।
- xxviii. केवल कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए लागू घरेलू खरीद की आवश्यकता बाजार की गतिशीलता को नहीं बदल सकता है क्योंकि निजी क्षेत्र से प्रमुख प्रयोक्ता विदेशी वस्तुओं की खरीद करने के लिए स्वतंत्र हैं। किसी भी स्थिति में नालको ने वैश्विक निविदा जारी करना जारी रखा है।
- xxix. प्रतिवादी वास्तविक आंकड़ों के साथ अपने दावे को स्थापित करने में असफल रहे हैं कि आयातों में सार्वजनिक खरीद आदेश के बाद गिरावट आई है।
- xxx. याचिकाकर्ता ने दिनांक 16 अक्तूबर, 2020 के अनुरोध के माध्यम से जनवरी से जून, 2020 की अवधि के लिए जांच की अवधि की बाद की अवधि के आंकड़े दिए हैं।

- xxxi. आयातों के बाजार हिस्से में आंशिक रूप से वृद्धि नहीं हुई है बल्कि प्रतिवादियों के तर्कों के विपरीत क्षति की अवधि में वह दुगुना हो गया है।
- xxxii. इस तर्क का उत्तर देते हुए कि आयातों में वृद्धि हुई क्योंकि अन्य देशों में उत्पादकों के पास बीआईएस लाइसेंस नहीं था, यह अनुरोध किया गया था कि देश में मांग को पूरा करने के लिए देश में पर्याप्त क्षमता थी और इस प्रकार प्रयोक्ताओं द्वारा इन वस्तुओं की पूर्ति घरेलू स्तर पर की जा सकती थी।
- xxxiii. इस तर्क के संबंध में कि पाटित आयातों में वृद्धि को दर्शाया जाना अपेक्षित है, यह अनुरोध किया गया था कि याचिकाकर्ता ने सकारात्मक पाटन मार्जिन दर्शाया है और दोनों देशों से पाटित आयातों में वृद्धि को दर्शाया है।
- xxxiv. याचिकाकर्ता ने वेदांता के लिए किए गए आयातों को प्रमुख रूप से दर्शाया है और विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग कीमतों के कारण तदनुसार एक तुलना की जानी चाहिए। नियम 11(3) और नियम 2(ख) के परंतुक का संदर्भ अपेक्षित नहीं है।
- xxxv. संबद्ध वस्तुओं की कीमतों में समुचित अवधि के लिए ही वृद्धि हुई और उसमें 2017-18 के बाद तेजी से गिरावट आई है।
- xxxvi. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है।
- xxxvii. कार्य-निष्पादन में सुधार जैसाकि कि ग्रासिम और जीएसीएल की वार्षिक रिपोर्ट में सूचित किया गया है, जांच की अवधि से संबंधित नहीं है। कार्य-निष्पादन में गिरावट जांच की अवधि में हुई है और बाद की अवधि में वित्तीय हानि हुई है।
- xxxviii. संभावना का विश्लेषण संबद्ध देशों के लिए संपूर्ण रूप में और न कि अलग-अलग निर्यातकों के लिए किया जाना अपेक्षित है। यह तथ्य कि अलग अलग निर्यातक शुल्क की शून्य दर का सामना कर रहे हैं, इस प्रकार के विश्लेषण के लिए संगत नहीं है।
- xxxix. घरेलू उद्योग प्रतिवादियों के दावे कि 85-90 प्रतिशत क्षमता उपयोग आदर्शतम है, के विपरीत 2015-16 में 93 प्रतिशत क्षमता उपयोग प्राप्त करने में सक्षम था। हालांकि, यदि 85-90 प्रतिशत को भी आदर्शतम उपयोग के रूप में माना जाता है तब चीन जन.गण. में क्षमता का उपयोग 80 प्रतिशत से कम था जिसका आशय यह हुआ कि बहुत अधिक मात्रा में उपयोग न की गई क्षमताएं थीं।
- xxxx. उत्पादकों के पास अतिरिक्त क्षमताओं, भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता को सिद्ध करने के बाद याचिकाकर्ता को पृथक् रूप से सिद्ध किए जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यदि उत्पादक अन्य बाजारों को आगे मात्राओं का निर्यात करने में सक्षम होते तब वे अपनी निर्धारित लागत को शामिल करने के उद्देश्य से अपनी क्षमताओं का पूर्ण रूप से उपयोग किए होते।
- xxxxi. चूंकि निर्यातकों ने उच्चतर कीमतों पर तीसरे बाजारों में बाजार नहीं पाया है और अपनी कीमतों को कम करने के लिए बाध्य हुआ है, वे थोड़ा अधिक कीमत पर भी भारत को ऐसे निर्यात विपठित करने के लिए इच्छुक होंगे। तीसरे देशों को निर्यातों की कीमत न्यूनतम कीमत को दर्शाता है जिस पर निर्यातक भारतीय बाजार को निर्यात करना चाहेंगे।
- xxxxii. रिकॉर्ड पर आकड़ा दर्शाता है कि भारत कोरिया गणराज्य में निर्यातकों के लिए आस्ट्रेलिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। इसके अलावा, प्रतिवादियों की अपनी स्वीकार्योक्ति के अनुसार, आस्ट्रेलिया को निर्यातों की कीमत की तुलना में भारत को निर्यात की कीमत कम होने का यह आशय है कि भारतीय बाजार निर्यातकों के लिए अधिक आकर्षक है।
- xxxxiii. विदेशी उत्पादकों की मालसूची के संबंध में सूचना गोपनीय प्रकृति का है और घरेलू उद्योग के पास वहां तक पहुंच नहीं है। इसके अलावा, चूंकि इस प्रकार के आधार पर कोई संभावना का दावा नहीं किया गया है अतः यह सूचना वर्तमान मामले में संगत नहीं है।

ज.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों का अनुरोध

63. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति, संभावना और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. समर्थकों से संगत सूचना प्राप्त न होने के कारण सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के नियम 4(1)(ग)(II), धारा 9ख और यूएस-हॉट रोलड स्टील में अपीलीय निकाय के फैसले के अनुसार समग्र रूप में घरेलू उद्योग का प्रभावी विश्लेषण संभव नहीं है। प्राधिकारी को अन्य उत्पादकों से भी सूचना मंगानी चाहिए।
- ii. याचिकाकर्ता ने क्षति के बाद की अवधि से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं जो संभावना के विश्लेषण के लिए आवश्यक है। यदि याचिकाकर्ता को ऐसे विलंबित चरण में आंकड़े प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है तब उपयुक्त समय निर्यातकों को टिप्पणियां देने और अपने आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए दिया जाना चाहिए।
- iii. घरेलू उद्योग ने स्वयं इस बात को माना है कि इसे क्षति नहीं हुई है। उद्योग को क्षति न होने का आशय यह है कि पाटनरोधी शुल्कों ने इस उद्देश्य को पूरा किया है और उसे समाप्त होने दिया जाना चाहिए।
- iv. याचिकाकर्ता ने यह दावा करने के लिए मेक्सिको से यूएस-ओसीटीजी में अपीलीय निकाय के फैसले पर विश्वास किया है कि कारणात्मक संबंध को दर्शाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि, यह पाटन और क्षति की संभावना को दर्शाने में असफल रहा है जो उपर्युक्त निर्णय के अंतर्गत पूर्व-अपेक्षा है।
- v. याचिकाकर्ता ने 7703 प्रतिशत की वृद्धि का दावा किया है जो भ्रमित करने वाला है क्योंकि अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन के कारण 2018-19 में आयात कमतर थे। आधार वर्ष की तुलना में, आयातों के बाजार हिस्से में मामूली रूप से वृद्धि ही हुई है।
- vi. संबद्ध देशों से आयातों के हिस्से में अन्य देशों के उत्पादकों के द्वारा बीआईएस प्रमाणन के न होने के कारण वृद्धि हुई है और यह दीर्घ अवधि प्रवृत्ति नहीं है।
- vii. याचिकाकर्ता से यह अपेक्षित नहीं है कि वे बड़े हुए आयातों को दर्शाएं बल्कि पाटित आयातों में वृद्धि को दर्शाएं। हालांकि, वर्तमान मामले में निर्यातक पाटन में शामिल नहीं हुए हैं।
- viii. क्षेत्रीय विश्लेषण के आधार पर कीमत में कटौती से संबंधित आंकड़ों को गोपनीय के रूप में दावा किया गया है।
- ix. पूर्वी भारत में कीमतों पर आधारित कीमत में कटौती उपयुक्त नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता ने यह सिद्ध नहीं किया है कि नियम 11(3) और नियम 2(ख) के परंतुक में अलग बाजार के संबंध में दी गई शर्तें पूरी की गई हैं। याचिकाकर्ता से यह अपेक्षित था कि वे यह दर्शाएं कि (क) पूर्वी भारत एक अलग बाजार के रूप में कार्य करता है (ख) याचिकाकर्ता केवल पूर्वी भारत में अपने सभी अथवा लगभग सभी उत्पादन की बिक्री करता है (ग) पूर्वी भारत में मांग को भारत के किसी अन्य भाग में उत्पादकों द्वारा पूरा नहीं किया जाता है। हालांकि, सभी याचिकाकर्ताओं में से केवल एक संयंत्र पूर्वी भारत में स्थित है जिसके फलस्वरूप एक अलग बाजार का सृजन हो सकता था। इसके अलावा, पूर्वी भारत एक अपरिभाषित प्रक्षेत्र है और इस संबंध में बहुत अधिक अपारदर्शिता है कि क्या इस क्षेत्र को बनाता है।
- x. घरेलू उद्योग के लाभ और नकद लाभ में बीआईएस प्रमाणन के बाद आयातों के फिर से शुरू होने के बाद तथा कुछ क्षेत्रों में सकारात्मक कटौती के बावजूद भी वृद्धि हुई है।
- xi. ग्रासिम की वार्षिक रिपोर्ट (2017-18) यह दर्शाता है कि कास्टिक सोडा की कीमतों में (i) यूएस में मौसम से संबंधित रुकावट (ii) यूरोप में मरकरी आधारित प्रौद्योगिकी को चरणबद्ध रूप में समाप्त करना और (iii) पर्यावरणीय चिंताओं के कारण चीन में क्षमता शटडाउन के कारण से वृद्धि हुई है।
- xii. घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है।
- xiii. ग्रासिम की वार्षिक रिपोर्ट (2017-18) और जीएसएल (2017-18) की रिपोर्ट भी यह दर्शाती है कि उनके कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ है।

- xiv. याचिकाकर्ता ने आयातों में वृद्धि की बहुत अधिक दर, स्वतंत्र रूप से पर्याप्त बिक्री योग्य क्षमताओं, क्षमताओं में आसन्न वृद्धि, भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता अथवा बहुत अधिक मालसूची के रूप में पाटन अथवा क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना को दर्शाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है।
- xv. चूंकि निर्यातकों को पहले से ही शुल्क की शून्य दर का सामना करना पड़ रहा है अतः शुल्क को समाप्त करने का कोई प्रभाव आयातों की मात्रा पर नहीं पड़ेगा।
- xvi. बीआईएस प्रमाणन जैसे गैर-टैरिफ अवरोधों से संभवतः आयात कम होगा और इस प्रकार इन आयातों से संभवतः शुल्कों को लगाए जाने के फलस्वरूप वृद्धि नहीं होगी। बीआईएस प्रमाणन को जारी रखने के फलस्वरूप अत्यधिक तकनीकी प्रक्रियागत और समय लगने वाली आवश्यकताओं तथा प्रमाणन प्राप्त करने की संबद्ध लागतों के कारण आयातों में बहुत अधिक गिरावट नहीं आएगी। विदेशी उत्पादकों से यह अपेक्षित है कि वे अत्यधिक प्रशासनिक और आवेदन लागतों का वहन करते हुए तीसरे वर्ष और उसके बाद के प्रत्येक वैकल्पिक वर्ष में लाइसेंस लेने के लिए एक नवीकरण प्रक्रिया से गुजरना अपेक्षित है।
- xvii. इस प्रमाणन के साथ जुड़ी चुनौतियों के कारण, प्रमुख उत्पादकों ने बीआईएस प्रमाणन के लिए आवेदन नहीं करने का विकल्प चुना है और पांच प्रतिशत से कम वैश्विक कास्टिक सोडा उत्पादकों को लाइसेंस मिला है।
- xviii. विदेशी निर्माताओं को बीआईएस लाइसेंस देने की अब इस प्रकार से समीक्षा की जा रही है कि कोई भी विदेशी निर्माताओं को आगे ऐसे लाइसेंस मंजूर नहीं किए जाएंगे अथवा मौजूदा लाइसेंस का समय विस्तार नहीं दिया जाएगा। निर्माताओं को लाइसेंस आवेदन के एक वर्ष बाद भी तथा सभी संबंधित कारखाने की जांच के पूरा होने से करीब एक वर्ष तक लंबित रहा है।
- xix. डीपीआईआईटी ने विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से सार्वजनिक खरीद पर सीमा लगाई है जो आगे यह दर्शाता है कि आयातों में संभवतः शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में वृद्धि होने की संभावना नहीं है विशेषकर क्योंकि नालको जैसे प्रमुख उपभोक्ताओं को अब विदेशी खरीद से रोक दिया गया है।
- xx. याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई क्षमता का विस्तार अन्य कंपनियों के प्रेस रिलीज पर आधारित है और सहयोगी निर्यातकों के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है।
- xxi. 85-90 प्रतिशत के क्षमता उपयोग को अक्सर अधिकांश रसायन उद्योगों में आदर्शतम माना गया है। घरेलू उद्योग की आदर्शतम क्षमता उपयोग भी 2018-19 में अपने उच्चतम कार्य-निष्पादन पर 89 प्रतिशत था और वह पिछले दस वर्षों के लिए 85-90 प्रतिशत के बीच रहा है।
- xxii. कास्टिक सोडा के आयातों की निर्णायक समीक्षा जांच में, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह नोट किया कि केवल अतिरिक्त क्षमता संभावना को दर्शाने के लिए पर्याप्त नहीं है और इसके अलावा यह दर्शाने के लिए साक्ष्य अपेक्षित है कि क्षति होगी।
- xxiii. चूंकि सहयोगी निर्यातकों ने पिछले पांच वर्षों में अथवा पूर्व में की गई समीक्षा के दौरान पाटन नहीं किया है, अतः पाटन के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना का कोई प्रश्न नहीं है।
- xxiv. यदि संबद्ध देशों में अतिरिक्त क्षमताएं भी हैं तब याचिकाकर्ता से दर्शाना अपेक्षित है कि भारत एक कीमत आकर्षक बाजार है।
- xxv. याचिकाकर्ता ने भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता को नहीं दर्शाया है। बल्कि इसने घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से कम कीमत पर निर्यातों का हवाला दिया है।
- xxvi. यदि तीसरे देशों को निर्यात भार की ओर परिवर्तित होता तब वे याचिकाकर्ता के दावे के विपरीत उसी कीमत पर भारत को परिवर्तित नहीं किए होते।
- xxvii. चूंकि सहयोगी निर्यातकों के पास कोई शुल्क नहीं है अतः उनके पास शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में भारत को निर्यात परिवर्तित करने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता।

- xxviii. बहुत अधिक मात्राओं में आयात जापान, ईरान और कतर से किया जा रहा है।
- xxix. सहयोगी निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए अन्य देशों को संपूर्ण रूप में कोरिया गणराज्य से निर्यातों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि आस्ट्रेलिया द्वारा लाई के लिए बहुत अधिक मात्रा में निर्यात किया जाता है। यद्यपि ऐसे आयातों की कीमत भारत को निर्यात की कीमत से कमतर है, वे बहुत अधिक मात्रा में उच्चतर मात्राओं में अंशदान करते हैं। लाई के लिए अन्य प्रमुख बाजार यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स माइनर आउटलाइन आइलैंड, मलेशिया और जापान हैं। इसके अलावा, फ्लेक्स के लिए प्रमुख बाजार विएतनाम, इंडोनेशिया, यूएसए, थाईलैंड और बांग्लादेश हैं जबकि भारतीय बाजार के पास इसके लिए बहुत अधिक मांग नहीं है।
- xxx. याचिकाकर्ता ने संबद्ध वस्तुओं की मालसूचियों का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। दायर किए गए उत्तर यह दर्शाते हैं कि सहयोगी निर्यातकों के पास बहुत अधिक मात्रा में मालसूची नहीं है।

ज.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

64. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रति-तर्कों को नोट किया है। प्राधिकारी द्वारा यहां नीचे दिए गए क्षति संबंधी विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान करते हैं।
65. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ..." घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी
66. इस नियमावली के नियम 23 में प्रावधान है कि नियम 6,7,8,9,10,11,16,18,19 और 20 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित समीक्षा के मामले में लागू होंगे। यदि घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन यह दर्शाता हो कि इसे क्षति की वर्तमान अवधि के दौरान क्षति नहीं हुई है तब प्राधिकारी इस तथ्य का निर्धारण करेंगे कि क्या वर्तमान शुल्क को समाप्त किए जाने के कारण घरेलू उद्योग को क्षति संभवतः फिर से होगी।
67. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से आयातों के कारण पाटन और क्षति की संभावना के पहलुओं की जांच करने के लिए आगे की कार्यवाही करने के पूर्व घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति, यदि कोई हो, की जांच की है। यह जांच की गई है कि क्या आयातों में स्वतंत्र रूप में अथवा उत्पादन अथवा खपत की तुलना में वृद्धि हुई। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करने में इस तथ्य की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव के कारण अन्यथा कीमतों पर बहुत अधिक हद तक दबाव पड़ेगा अथवा कीमत में वृद्धि रुक जाएगी जो अन्य प्रकार से काफी हद तक हुई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच के लिए उद्योग की स्थिति जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, भंडार, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन का परिमाण और मार्जिन आदि जैसे सूचकांकों पर इस नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों तथा लागू कानूनों पर विचार करते हुए उसका विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण यहां नीचे इन पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का वास्तव में समाधान करता है।
68. समर्थकों के संबंध में सूचना के न होने के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्क के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस नियमावली के नियम 11(2) के अनुसार, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे "घरेलू उद्योग को क्षति, घरेलू उद्योग को क्षति के खतरे, घरेलू उद्योग की स्थापना के लिए वास्तविक मंदी का निर्धारण करें" अतः क्षति का मूल्यांकन परिभाषित घरेलू उद्योग तक सीमित किया जाना अपेक्षित है और अन्य उत्पादकों का कार्य-निष्पादन महत्वपूर्ण नहीं है। चूंकि घरेलू उद्योग को क्षति का निर्धारण करने के लिए आवश्यक सभी सूचना भाग लेने वाले उत्पादकों द्वारा उपलब्ध कराई गई है अतः समर्थन करने वाले उत्पादकों के कार्य-निष्पादन के बारे में सूचना ऐसे विश्लेषण के लिए संगत नहीं है।

I. मांग/स्पष्ट खपत का आकलन

69. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में भारत में संबंधित उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत को परिभाषित किया है। इस प्रकार से आकलित मांग नीचे तालिका में दी गई है:

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
कैप्टिव सहित						
घरेलू उद्योग	मी.टन	13,77,694	13,81,792	15,52,722	11,47,602	15,30,136
अन्य उत्पादक	मी.टन	15,00,689	16,50,367	17,70,249	13,44,626	17,92,835
संबद्ध आयात	मी.टन	55,210	61,030	1,542	86,056	1,14,741
अन्य आयात	मी.टन	3,69,378	3,59,549	2,04,909	1,46,086	1,94,782
मांग	मी.टन	33,02,971	34,52,738	35,29,422	27,24,370	36,32,494
कैप्टिव को छोड़कर						
घरेलू उद्योग	मी.टन	10,06,750	10,24,376	11,58,389	8,11,538	10,82,051
अन्य उत्पादक	मी.टन	15,00,689	16,50,367	17,70,249	13,44,626	17,92,835
संबद्ध आयात	मी.टन	55,210	61,030	1,542	86,056	1,14,741
अन्य आयात	मी.टन	3,69,378	3,59,549	2,04,909	1,46,086	1,94,782
मांग	मी.टन	29,32,027	30,95,322	31,35,089	23,88,306	31,84,408

70. यह देखा जाता है कि संबद्ध वस्तुओं की मांग क्षति की पूरी अवधि के दौरान धीरे-धीरे बढ़ती रही है और इसमें इस अवधि में 10 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।

II. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

71. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस पर विचार करें कि क्या या तो स्वतंत्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पाटित आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। क्षति के विश्लेषण के उद्देश्य से, प्राधिकारी डीजीसीआईएंडएस से लिए गए लेन-देनवार आयात संबंधी आंकड़ों पर विश्वास किया है। क्षति की जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं की आयात मात्रा और पाटित आयातों का हिस्सा नीचे दिया गया है:

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
संबद्ध आयात	मी.टन	55,210	61,030	1,542	86,056	1,14,741
चीन	मी.टन	40,326	42,357	1,542	43,957	58,609
कोरिया गणराज्य	मी.टन	14,884	18,673	-	42,099	56,132
अन्य आयात	मी.टन	3,69,378	3,59,549	2,04,909	1,46,086	1,94,782
कुल आयात	मी.टन	4,24,588	4,20,579	2,06,451	2,32,142	3,09,523
निम्नलिखित की तुलना में आयात						
भारतीय उत्पादन	%	2%	2%	0%	3%	3%
चीन जन.गण	%	1%	1%	0%	2%	2%
कोरिया गणराज्य	%	1%	1%	0%	2%	2%
खपत	%	2%	2%	0%	3%	3%

चीन जन.गण.	%	1%	1%	0%	2%	2%
कोरिया गणराज्य	%	0%	1%	0%	2%	2%
कुल आयात	%	13%	15%	1%	37%	37%
चीन जन.गण.	%	9%	10%	1%	19%	19%
कोरिया गणराज्य	%	4%	4%	0%	18%	18%

72. यह देखा जाता है कि:

- संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में 2017-18 तक वृद्धि हुई लेकिन 2018-19 में तेजी से गिरावट आई। यह गिरावट स्पष्ट रूप से बीआईएस मानदंडों का अनुपालन करने के लिए अनिवार्य आवश्यकता के कारण हुई थी। हालांकि, ऐसी गिरावट के बाद, आयातों में जांच की अवधि में तेजी से वृद्धि हुई है।
- क्षति की अवधि के आरंभ अर्थात् बीआईएस के लागू होने के पूर्व तुलना किए जाने पर भी, आयातों में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि दर्शाई है।
- हालांकि आयातों में क्षति की अवधि के दौरान उत्पादन और खपत की तुलना में बहुत मामली रूप से वृद्धि हुई है।
- हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया कि बीआईएस मानकों की अनिवार्य आवश्यकताओं के फलस्वरूप आयातों में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि यह केवल लघु अवधि के लिए थी कि किसी भी विदेशी उत्पादकों के पास लाइसेंस नहीं था और यह समयबद्ध रूप में लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रयासों में उनकी अपनी कमी के कारण थी। प्राधिकारी से वर्ष 2018-19 की उपेक्षा करने के लिए उपयुक्त मानते हैं जहां तक इसका संबंध स्वतंत्र रूप में तथा भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में आयातों की मात्रा से है।

III. पाटित आयातों पर कीमत संबंधी प्रभाव

73. इस नियमावली के अनुबंध II (ii) के संदर्भ में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस पर विचार करें कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव के कारण अन्यथा कीमतों पर बहुत अधिक हद तक प्रभाव पड़ेगा अथवा कीमत में वृद्धि रुक जाएगी जो अन्य प्रकार से बहुत अधिक हद तक हुई होती। इस संबंध में संबद्ध वस्तुओं के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत के बीच तुलना की गई है।

क. कीमत में कटौती

74. कीमत में कटौती का निर्धारण करने के लिए, घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत और इस उत्पाद का पहुंच मूल्य जिसमें व्यापार के उसी स्तर पर सभी छूट और करों की निवल राशि शामिल है, के बीच तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की कीमतों का निर्धारण कारखानागत स्तर पर किया गया था।

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
चीन जन.गण					
बिक्री कीमत	रु./मी.टन	***	***	***	***
पहुंच कीमत	रु./मी.टन	27,178	34,476	39,317	34,985
कीमत में कटौती	रु./मी.टन	***	***	***	***
कीमत में कटौती	%	***	***	***	***
कीमत में कटौती	% रेंज	0-10	0-10	नकारात्मक	नकारात्मक
कोरिया गणराज्य					
बिक्री कीमत	रु./मी.टन	***	***	***	***

पहुंच कीमत	रु./मी.टन	27,702	37,604	-	33,200
कीमत में कटौती	रु./मी.टन	***	***	***	***
कीमत में कटौती	%	***	***	***	***
कीमत में कटौती	% रेंज	0-10	नकारात्मक	-	नकारात्मक
संबद्ध देश					
बिक्री कीमत	रु./मी.टन	***	***	***	***
पहुंच कीमत	रु./मी.टन	27,319	35,433	39,317	34,112
कीमत में कटौती	रु./मी.टन	***	***	***	***
कीमत में कटौती	%	***	***	***	***
कीमत में कटौती	% रेंज	0-10	0-10	नकारात्मक	नकारात्मक

75. यह नोट किया जाता है कि आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती नहीं हो रही थी। घरेलू उद्योग की बिक्री आयातों की पहुंच कीमत से ऊपर थी। घरेलू उद्योग ने दावा किया कि यह घरेलू उद्योग की भारित औसत बिक्री कीमत पर विचार करने के कारण थी जब आयात केवल एक क्षेत्र तक सीमित था। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत विभिन्न क्षेत्रों में भाड़े की लागतों में अंतर के कारण काफी हद तक अलग-अलग थी। ये आयात पूर्व में इच्छित वेदांता लिमिटेड द्वारा किया गया है। तदनुसार यदि पूर्वी भारत में घरेलू उद्योग की कीमत की तुलना आयातों की पहुंच कीमत से की जाती है तब कीमत में कटौती सकारात्मक है। हालांकि प्राधिकारी कीमत में कटौती के निर्धारण के लिए घरेलू उद्योग की निवल कारखानागत बिक्री कीमत पर विचार करते हैं और इस संबंध में सतत कार्य-पद्धति का अनुपालन करने के लिए इसे उपयुक्त मानते हैं। इस प्रकार, यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान कीमत में कटौती सभी संबद्ध देशों से नकारात्मक है।

ख. कीमत हास/न्यूनीकरण

76. इस तथ्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से कि क्या आयातों के प्रभाव से कीमतों पर बहुत अधिक हद तक दबाव पड़ेगा अथवा कीमत में वृद्धि रुक जाएगी जो अन्यथा हुई होती, घरेलू उद्योग द्वारा क्षति की अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तनों के लिए दी गई सूचना की तुलना पहुंच मूल्य के साथ की गई है ताकि अभीष्ट प्रभाव देखा जा सके:

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
बिक्री की लागत	रु./मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	112	113
बिक्री कीमत	रु./मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	126	130	112
पहुंच कीमत	रु./मी.टन	27,319	35,433	39,317	34,112
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	130	144	125

77. यह देखा जाता है कि आयातों की पहुंच कीमत, घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और बिक्री कीमत में 2018-19 तक वृद्धि हुई। हालांकि, जबकि बिक्री की लागत जांच की अवधि में उसी क्षेत्र में रही, घरेलू उद्योग की आयात कीमत और बिक्री कीमत में जांच की अवधि में बहुत अधिक हद तक गिरावट आई। हालांकि, पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और बिक्री कीमत से ऊपर थी।

IV. घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों पर प्रभाव

78. इस नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव का वस्तुपरक जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों

के परिणामी प्रभाव के संबंध में, इस नियमावली में आगे यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों जिनका घरेलू उद्योग की हालत पर प्रभाव पड़ता हो, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; वे कारक जो घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा पर प्रभाव डालते हों; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव का वस्तुपरक मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर यहां नीचे चर्चा की गई है।

क. उत्पादन, क्षमता, क्षमता का उपयोग और बिक्री की मात्रा

79. उत्पादन, घरेलू मर्चेन्ट बिक्री, कैप्टिव खपत, क्षमता और क्षमता की उपयोगिता के संबंध में घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन नीचे दिए गए अनुसार है:

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
क्षमता	मी.टन	15,31,160	15,55,261	17,42,350	13,08,013	17,44,017
उत्पादन	मी.टन	13,82,905	14,06,481	15,45,924	11,67,738	15,56,984
क्षमता का उपयोग	%	90%	90%	89%	89%	89%
घरेलू बिक्री	मी.टन	12,77,886	12,62,893	14,30,185	10,28,833	13,71,778
कैप्टिव बिक्री	मी.टन	***	***	***	***	***

80. यह देखा जाता है कि यद्यपि घरेलू उद्योग की क्षमता में इन वर्षों में वृद्धि हुई, घरेलू उद्योग अपने उत्पादन में वृद्धि करने और अपनी क्षमता का उपयोग को वृहत रूप से बनाए रखने में सक्षम था।

ख. मांग में बाजार हिस्सा

81. कथित पाटित आयातों और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से की जांच नीचे दिए गए अनुसार की गई है:

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
मांग में हिस्सा (कैप्टिव सहित)					
घरेलू उद्योग	%	42%	40%	44%	42%
अन्य उत्पादक	%	45%	48%	50%	49%
संबद्ध आयात	%	2%	2%	0%	3%
अन्य आयात	%	11%	10%	6%	5%
मांग में हिस्सा (कैप्टिव को छोड़कर)					
घरेलू उद्योग	%	34%	33%	37%	34%
अन्य उत्पादक	%	51%	53%	56%	56%
संबद्ध आयात	%	2%	2%	0%	4%
अन्य आयात	%	13%	12%	7%	6%

82. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 2018-19 तक सुधार हुआ था परंतु जांच की अवधि के दौरान इसमें गिरावट आई है क्योंकि आयातों में वृद्धि हुई और इसने बाजार हिस्से को प्राप्त किया। कुल मिलाकर क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में कोई गिरावट नहीं हुई है जबकि आयातों के बाजार हिस्से में मामूली वृद्धि दर्शाई है।

ग. मालसूची

83. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
औसत माल सूची	मी.टन	13,791	18,593	20,351	19,522
	सूचीबद्ध	100	135	148	142

84. यह देखा जाता है कि औसत मालसूची में 2018-19 की तुलना में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है।

घ. लाभ, नकद लाभ और लगाई गई पूंजी पर लाभ

85. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग के लाभ, निवेश पर लाभ और नकद लाभ नीचे तालिका में दिया गया है:

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
बिक्री की लागत	रु./मी.टन	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	111	112	113	113
बिक्री कीमत	रु./मी.टन	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	126	130	112	112
लाभ / हानि	रु./मी.टन	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	183	199	106	106
लाभ / हानि	लाख रु.	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	181	222	113	113
नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	168	205	118	118
लगाई गई पूंजी पर लाभ	%	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	152	190	102	102

86. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित लाभ और नकद लाभ वर्ष 2018-19 तक वृद्धि को दर्शाता है। हालांकि, 2018-19 के बाद, उद्योग की लाभप्रदता में जांच की अवधि में तेजी से कमी आई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग का कार्यनिष्पादन 2018-19 की उपेक्षा करने के बाद भी गिरावट को दर्शाता है। हालांकि घरेलू उद्योग का प्रचालन संबंधी कार्य-निष्पादन आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हुआ है यद्यपि इसमें पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में बहुत अधिक हद तक गिरावट आई है।

ड. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

87. प्राधिकारी ने रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में सूचना की जांच की है जिसे नीचे दिया गया है:

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
कर्मचारियों की संख्या	रु./मी.टन	4,728	4,899	5,440	5,329	5,329
मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	108	121	91	122
प्रति दिन उत्पादकता	मी.टन/दिन	3,841	3,907	4,294	4,325	4,325

88. यह देखा जाता है कि कर्मचारियों की संख्या में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप कुल मजदूरी में वृद्धि हुई। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की उत्पादकता में भी इस अवधि में सुधार हुआ है।

च. वृद्धि

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
					पिछले वर्ष पर विचार करते हुए	2017-18 पर विचार करते हुए
उत्पादन	%	-	2	10	1	11
घरेलू बिक्री	%	-	(1)	13	(5)	9
लाभ/हानि	%	-	81	42	(109)	(67)
नकद लाभ	%	-	68	37	(87)	(50)
लगाई गई पूंजी पर लाभ	%	-	52	38	(87)	(50)

89. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन ने मात्रा और लाभप्रदता दोनों मानदंडों में 2018-19 तक वृद्धि दर्शाई है। हालांकि जांच की अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग ने अपनी बिक्री और अपनी लाभप्रदता के मानदंडों में नकारात्मक वृद्धि देखी है। 2018-19 में बीआईएस लाइसेंस की आवश्यकताओं पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने 2017-18 में मानदंडों पर विचार करते हुए वृद्धि का भी निर्धारण किया और यह पाया कि जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की वृद्धि कीमत मानदंडों के संबंध में 2017-18 की तुलना में नकारात्मक थी जबकि वही मात्रा मानदंडों के संबंध में सकारात्मक थी।

छ. पूंजीगत निवेश जुटाने की क्षमता

90. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जबकि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लगाई गई पूंजी पर लाभ और लाभ में गिरावट आई, यह उचित लाभ अर्जित करने में सक्षम रहा है। इस प्रकार, यह नहीं माना जा सकता है कि आयातों के कारण पूंजी निवेश जुटाने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता पर प्रभाव पड़ा है।

ज. पाटन का परिमाण

91. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं को भारत में पाटित किया जा रहा है और पाटन मार्जिन की चीन जन.गण. के लिए सकारात्मक और बहुत अधिक है जबकि कोरिया के लिए इसे असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए बहुत अधिक माना गया है।

झ. क्षति मार्जिन का परिमाण

92. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद की क्षति रहित कीमत का निर्धारण जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर किया गया है। क्षति रहित कीमत को क्षति के मार्जिन की गणना करने के लिए संबद्ध देश के पहुंच कीमत की तुलना करने के लिए माना गया है। क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने के लिए, क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह बर्ताव यूटिलिटी के साथ किया गया है। क्षति की अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई असाधारण अथवा गैर-आवर्ती सचों को उत्पादन की लागत में नहीं जोड़ा गया था। विचाराधीन उत्पाद के लिए लगाई गई औसत पूंजी (अर्थात् औसत निवल निर्धारित परिसंपत्ति तथा औसत कार्यशील पूंजी) पर उचित लाभ (22 प्रतिशत की दर से कर-पूर्व) की अनुमति कर-पूर्व लाभ के रूप में दी गई थी ताकि इस नियमावली के अनुबंध-III में यथा-निर्धारित और अपनाई जा रही क्षति रहित कीमत तय की जा सके।

93. उपर्युक्त निर्धारित पहुंच कीमत और क्षति रहित कीमत के आधार पर, उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किया गया है और वह नीचे तालिका में दिया गया है। यह नोट किया जाता है कि क्षति मार्जिन कोरिया और चीन जन.गण. के सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों दोनों के लिए नकारात्मक हैं जबकि वह दोनों संबद्ध देशों से अन्य उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सकारात्मक है।

क्षति मार्जिन तालिका

देश	उत्पादक	एनआईपी (यूएसडा./मी.टन)	पहुंच मूल्य (यूएसडा./मी.टन)	क्षति मार्जिन (यूएसडा./मी.टन)	क्षति मार्जिन %	क्षति मार्जिन %रेंज
कोरिया गणराज्य	हन्वा साल्यूशंस	***	***	***	***	(10-20)
कोरिया गणराज्य	अन्य	***	***	***	***	10-20
चीन जन.गण.	तायनजिन डागु केमिकल क.लि.	***	***	***	***	(20-30)
चीन जन.गण.	अन्य	***	***	***	***	50-60

घ. कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण विश्लेषण

94. इस नियमावली के अनुसार प्राधिकारी से अन्य बातों के साथ-साथ यह अपेक्षित है कि वे पाटित आयातों के अलावा किसी ज्ञात कारकों जो एक ही समय में घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं, की जांच करें ताकि इन अन्य कारकों के कारण हुई क्षति का आरोप पाटित आयातों पर नहीं लगाया जा सके। ये कारक जो इस संबंध में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, में अन्य बातों के साथ-साथ पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में संकुचन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों की व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य-पद्धतियां और उनके बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी का विकास और निर्यात कार्य-निष्पादन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल है। नीचे यह भी जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों के अलावा कारकों का घरेलू उद्योग को क्षति में योगदान हुआ होगा।

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमतें

95. यह देखा जाना है कि अन्य देशों जैसे जापान, ईरान, ओमान और कतर से बहुत अधिक मात्रा में आयात हुए हैं। हालांकि ऐसे आयातों के कारण क्षति की वर्तमान अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

ख. मांग में संकुचन

96. यह देखा जाना है कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है। इस कारण से मांग में संकुचन को घरेलू उद्योग को संभावित क्षति के लिए एक कारण के रूप में नहीं माना जा सकता है।

ग. प्रौद्योगिकी का विकास

97. यह नोट किया जाता है कि उत्पादन करने वाले संबद्ध वस्तुओं के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और इस कारण से घरेलू उद्योग का क्षति होने की संभावना नहीं है।

घ. प्रतिस्पर्धा की शर्तें और व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य-पद्धतियां

98. इस जांच ने यह दर्शाया है कि प्रतिस्पर्धा की शर्तें और व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य-पद्धतियों की फलस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

ड. घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य-निष्पादन

99. इसमें ऊपर जांच की गई क्षति संबंधी सूचना का संबंध इसके घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के केवल कार्य-निष्पादन से है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को संभावित क्षति के लिए इसके निर्यात कार्य-निष्पादन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

च. उत्पादकता

100. घरेलू उद्योग की उत्पादकता में इस अवधि में सुधार हुआ है और इस प्रकार घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में संभावित गिरावट का कारण उत्पादकता में गिरावट नहीं हो सकता है।

ज.1 क्षति और कारणात्मक संबंध के जारी रहने के संबंध में निष्कर्ष

101. संबद्ध देश से आयातों की जांच और घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन यह दर्शाता है कि पाटनरोधी शुल्कों के लागू रहने के बावजूद, संबद्ध देश से आयात बहुत अधिक रहे हैं और स्वतंत्र रूप में उसमें वृद्धि हुई है और इसके साथ ही भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की बिक्री और बाजार हिस्से में उत्पादन और मांग में वृद्धि के बावजूद पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई। ये आयात जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती नहीं कर रहे थे। जबकि, घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ और निवेश पर लाभ में 2018-19 तक सुधार हुआ, पिछले वर्ष अर्थात् 2017-18 तथा आधार वर्ष की तुलना में इनमें जांच की अवधि में गिरावट आई। कुल मिलाकर क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग पर कोई अधिक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। इस प्रकार क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

ट. पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना

102. प्राधिकारी यह देखते हैं कि यह निर्णायक समीक्षा जांच है अतः इस जांच का केन्द्र बिंदु उस स्थिति में सतत पाटन और परिणामी क्षति के संभावित परिदृश्य की जांच करना है जब पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त होने दिया जाता है, यदि कोई वर्तमान क्षति नहीं हो। इसके लिए इस तथ्य पर विचार करना भी अपेक्षित है कि क्या लगाए गए शुल्क से क्षतिकारक पाटन को समाप्त करने का अभीष्ट उद्देश्य पूरा हो रहा है।
103. प्राधिकारी के ध्यान में लाए गए सभी कारकों की जांच इस तथ्य का निर्धारण करने के लिए किया गया है कि क्या शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन अथवा क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है। प्राधिकारी ने पाटन अथवा क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से घरेलू उद्योग द्वारा यथा उपलब्ध कराए गए विभिन्न सूचनाओं पर विचार किया है।
104. इस प्रकार की संभावना का विश्लेषण करने के लिए कोई विशिष्ट पद्धतियां उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि इस नियमावली के अनुबंध-II की शर्त (viii) में अन्य बातों के साथ-साथ उन कारकों के लिए प्रवधान है जिन पर विचार किया जाना अपेक्षित है:
- वास्तविक रूप से बढ़े हुए आयात की संभावना को दर्शाते हुए भारत में पाटित आयातों की वृद्धि की बहुत अधिक दर;
 - किसी अतिरिक्त निर्यातों को खपाने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजारों का वास्तविक रूप से बढ़े हुए पाटित निर्यातों की संभावना को दर्शाते हुए निर्यातक की स्वतंत्र रूप से पर्याप्त बिक्री योग्य अथवा आसन्न, वास्तविक क्षमता वृद्धि;
 - क्या आयात उन कीमतों पर हो रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर बहुत अधिक न्यूनकारी अथवा ह्रासकारी प्रभाव पड़ेगा और आगे आयातों के लिए मांग में संभावित रूप से वृद्धि होगी; और
 - जांच की जा रही वस्तु की मालसूची।
105. इसके अलावा, प्राधिकारी ने अन्य संगत कारकों की भी जांच की है जिसका घरेलू उद्योग को पाटन के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने तथा परिणामी क्षति की संभावना पर पड़ता हो। संभावना के मानदंडों की जांच नीचे दिए गए अनुसार की गई है।

106. जहां तक सहयोगी विदेशी उत्पादकों के अपनी क्षमताओं और निर्यातों के संबंध में तर्क का प्रश्न है, यह नोट किया जाता है कि संभावना का विश्लेषण संबद्ध देशों के लिए और न कि उन देशों में अलग-अलग उत्पादकों के लिए की जानी चाहिए। इस कारण से, उत्तर देने वाले निर्यातक के द्वारा दी गई सूचना के अलावा, प्राधिकारी ने सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए संचयी रूप से निर्यातक देश हेतु सूचना पर भी विचार किया है।

क. संबद्ध वस्तुओं का लगातार पाटन

107. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि शुल्कों के लागू रहने के बावजूद संबद्ध वस्तुओं का पाटन चीन जन.गण से होना जारी है। चीन जन.गण. के सहयोगी उत्पादक के लिए, पाटन मार्जिन सकारात्मक है जबकि क्षति मार्जिन नकारात्मक है। चीन जन.गण. से गैर-सहयोगी उत्पादकों के लिए, पाटन और क्षति मार्जिन सकारात्मक है। इस प्रकार, शुल्कों की अनुपस्थिति में संबद्ध वस्तुओं का पाटन जारी रहने की संभावना है और वे संभवतः भारत में घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाएंगे। हालांकि, जहां तक कोरिया गणराज्य का प्रश्न है, एकमात्र उत्पादक जिनकी वस्तुओं का निर्यात भारत को जांच की अवधि के दौरान किया गया था अपाटित कीमतों पर पाया गया था जबकि कोरिया से गैर-सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन और क्षति मार्जिन सकारात्मक है। हालांकि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अन्य कोरियाई उत्पादक भी हैं जिन्होंने वर्तमान जांच में सहयोग नहीं किया है। इसके अलावा, यह भी देखा जाता है कि कोरिया के असहयोगी उत्पादकों के लिए सकारात्मक पाटन और क्षति मार्जिन रहा है। यद्यपि जांच की अवधि के दौरान क्षति जारी नहीं रही है फिर भी कोरिया से क्षतिकारक कीमत पर सतत पाटन शुल्कों को समाप्त किए जाने की स्थिति में कोरिया गणराज्य से असहयोगी उत्पादकों से पाटित आयातों के सघन रूप में होने की बहुत अधिक संभावना उत्पन्न करता है।

ख. पाटनरोधी शुल्को की उपस्थिति में आयातों की मात्रा और आयातों में वृद्धि

108. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान अवधि में संबद्ध देशों से स्वतंत्र रूप में बहुत अधिक आयात हुए थे। यह भी नोट किया जाता है कि यद्यपि आयातों की समग्र मात्रा आधार वर्ष से जांच की अवधि के दौरान नीचे आई है अतः संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में पिछले वर्ष से बहुत हद तक वृद्धि हुई है। इस प्रकार, यह तथ्य कि आयातों में शुल्कों के लागू रहने के बावजूद वृद्धि हुई है, यह दर्शाता है कि इन आयातों में शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन आयातों में संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक तेज गति से वृद्धि हुई है और उससे यह दृष्टिगत होता है कि आयातों का शुल्कों की अनुपस्थिति में बाजार में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ने की संभावना है।

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
संबद्ध आयात	मी.टन	55,210	61,030	1,542	86,056	1,14,741
आधार वर्ष से वृद्धि	%	-	11	(97)	108	108
चीन जन.गण.	मी.टन	40,326	42,357	1,542	43,957	58,609
आधार वर्ष से वृद्धि	%	-	5	(96)	45	45
कोरिया गणराज्य	मी.टन	14,884	18,673	-	42,099	56,132
आधार वर्ष से वृद्धि	%	-	25	(100)	277	277
मांग	मी.टन	3,302,971	3,452,738	3,529,422	27,24,370	36,32,494
आधार वर्ष से वृद्धि	%	-	5	7	10	10

109. इस तर्क के संबंध में कि इन आयातों में बीआईएस लाइसेंसिंग और सार्वजनिक खरीद की आवश्यकताओं के कारण और अधिक वृद्धि होने की संभावना नहीं है, यह नोट किया जाता है कि रिकॉर्ड पर आंकड़े दर्शाते हैं कि बीआईएस लाइसेंसिंग और सार्वजनिक खरीद की आवश्यकताओं के बावजूद आयातों में वृद्धि हुई है। इस प्रकार, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि शुल्कों को समाप्त किए जाने की स्थिति में इन आयातों में वृद्धि होने की संभावना नहीं है।

ग. संबद्ध देशों के पास मौजूद स्वतंत्र रूप से बिक्री योग्य क्षमताएं

110. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने चीन जन.गण. तथा पूर्वोत्तर एशिया के लिए अतिरिक्त क्षमताओं का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। हालांकि, कोरिया राज्य के लिए कोई पृथक सूचना नहीं दी गई है। प्राधिकारी ने चीन जन.गण. के लिए अतिरिक्त क्षमताओं के संबंध में सूचनाओं की जांच की है जो नीचे दी गई हैं:

विवरण	इकाई	चीन जन.गण
कुल क्षमताएं	लाख मी.टन	450
घरेलू मांग	लाख मी.टन	350
निर्यात योग्य क्षमता	लाख मी.टन	100
क्षमता का उपयोग	%	79%
उपयोग न की गई क्षमता	लाख मी.टन	94.5

111. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. में अत्यधिक निष्क्रिय क्षमताएं हैं विशेषकर जब उसकी तुलना भारत में केवल 36.32 लाख मी.टन की मांग से की गई हो। इसके अलावा, यदि वर्तमान उत्पाद में आदर्शतम क्षमता उपयोग(90 प्रतिशत) के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों का दावा स्वीकार किया जाता हो तब यह देखा जाता है कि उसके बावजूद चीन के उत्पादकों के पास समग्र भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमताएं हैं।

घ. उत्पादन क्षमताओं में आसन्न अत्यधिक विस्तार

112. घरेलू उद्योग ने क्षमताओं के विस्तार के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई है जो यह दर्शाता है कि चीन जन.गण. में क्षमताओं में 2023 तक प्रति वर्ष 16.7 लाख मी.टन तक वृद्धि होने की संभावना है जिसका आशय यह है कि प्रति वर्ष लगभग 4 लाख मी.टन का औसत क्षमता विस्तार होगा। तुलना करने पर भारत में मांग में प्रतिवर्ष लगभग 1 से 1.5 लाख तक की वृद्धि होती है। इसके अलावा, चीन के उत्पादकों के पास पहले से ही अतिरिक्त क्षमताएं हैं। क्षमताओं में इस अत्यधिक वृद्धि के फलस्वरूप उत्पाद की बढ़ी हुई उपलब्धता होने की संभावना है और संभवतः शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन कीमतों पर भारत को निर्यात किया जाना है।

ड. संबद्ध देशों से निर्यातों में गिरावट

113. घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना यह दर्शाती है कि संबद्ध देशों से विश्व के शेष देशों में निर्यात में हाल की अवधि में गिरावट आई है। जबकि भारत को निर्यात में वृद्धि हुई, समग्र निर्यात में गिरावट आई।

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि वास्तविक	जांच की अवधि वार्षिकीकृत
कुल निर्यात					
चीन	1,848,968	1,389,656	998,656	951,104	1,268,138
कोरिया	483,751	392,401	427,670	261,319	348,425
संबद्ध देश	2,332,720	1,782,057	1,426,326	1,212,422	1,616,563
भारत					
चीन	77,096	42,346	178	40,504	54,005
कोरिया	14,841	26,304	-	42,100	56,133
संबद्ध देश	91,936	68,650	178	82,604	110,139
विश्व का शेष देश					
चीन	1,771,873	1,347,310	998,478	910,599	1,214,132
कोरिया	468,911	366,097	427,670	219,219	292,292
संबद्ध देश	2,240,783	1,713,407	1,426,148	1,129,818	1,506,424

स्रोत: ट्रेड मैप डाटा

च. भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता

114. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये निर्यातक संबद्ध वस्तुओं की बहुत अधिक मात्रा में निर्यात अन्य देशों को उन कीमतों पर करते आ रहे हैं जो भारत में बिक्री कीमत से कम है जिसका सारांश नीचे तालिका में दिया गया है:

देश	तीसरे देशों को निर्यात(मी.टन)	भारत को कीमत की तुलना में कम कीमतों पर निर्यात(मी.टन)	तीसरे देश के निर्यातों में हिस्सा (%)	भारत में मर्चेन्ट मांग की तुलना में (%)
चीन जन.गण	9,51,103	4,50,250	47%	17%
कोरिया गणराज्य	2,61,319	1,48,393	57%	5%
कुल	12,12,422	5,98,643	49%	22%

115. शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में, देश की कुल तुलनात्मक कीमत प्रतिस्पर्धात्मकता के कारण ऐसे आयातों को भारत की ओर विपथित किए जाने की संभावना है।
116. यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के निर्यात की बहुत अधिक मात्रा उन कीमतों पर की जा रही है जिसके कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और ये क्षति रहित कीमत से कम भी हैं जो घरेलू उद्योग को क्षति के फिर से होने की संभावना को बतलाता है।
117. चीन जन.गण. के सहयोगी उत्पादकों द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को निर्यात तीसरे देशों को निर्यातों की तुलना में अधिक कीमत पर हुआ है। उसको देखते हुए, सहयोगी उत्पादक के लिए भारतीय बाजार कीमत आकर्षक बाजार पाया गया। इसके अलावा, सहयोगी उत्पादक के अलावा कोई बहुत अधिक निर्यात चीन जन.गण. से नहीं किया गया था।

छ. जांच की अवधि के बाद की अवधि के आंकड़ों का विश्लेषण

118. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किया गया जांच के बाद की अवधि का आंकड़ा यह दर्शाता है कि आयातों की मात्रा और कीमत दोनों में बाद की अवधि के दौरान बहुत अधिक हद तक गिरावट आई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग को उत्पादन, बिक्री, क्षमता के उपयोग, लाभ, नकद लाभ और लगाई गई पूंजी पर लाभ में गिरावट के कारण हानि हुई। घरेलू उद्योग को इस अवधि में हानि हुई है।

ठ. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां**ठ.1 घरेलू उद्योग का अनुरोध**

119. घरेलू उद्योग ने अधिकांशतः पूर्व में किए गए अनुरोधों को दोहराया है। विशेषकर, घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित पर बल दिया है:
- क. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का लगातार पाटन हुआ है और इन आयातों में लागू शुल्कों के साथ भी वृद्धि हुई है।
- ख. संबद्ध देशों में बहुत अधिक अतिरिक्त क्षमताएं हैं और तीसरे देशों को निर्यात भी भारतीय बाजार की ओर इसकी कीमत आकर्षकता के कारण किया जाना संभावित है।
- ग. कीमत में कटौती पूर्व में किए जा रहे आयातों के कारण ही नकारात्मक है जबकि घरेलू उद्योग ने पूरे देश में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है। पूर्व में कीमतों पर विचार कीमत में कटौती के निर्धारण के लिए किया जाना चाहिए क्योंकि इस उत्पाद में बहुत अधिक भाड़ा लागत शामिल है।
- घ. क्षति के मार्जिन के निर्धारण की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग ने शुल्क के समय विस्तार की मांग की है। यदि क्षति मार्जिन निर्धारित किया जाता है तब अंतरदेशीय भाड़े की लागत में अंतर का समायोजन किया जाना चाहिए।

ठ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों का अनुरोध

120. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी अपने अनुरोधों को दोहराया है। इसके अलावा हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किया है:
- क. उन मामलों में जैसाकि वर्तमान मामला है जिसमें एएमएआई के अलग-अलग सदस्य चयनित रूप से इन वर्षों में जांच के काम में भाग लेते रहे हैं, व्यापार नोटिस सं. 13/2018 प्राधिकारी के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए दावे का सत्यापन करने के लिए एक महत्वपूर्ण औजार के रूप में कार्य करता है और उसका पालन किया जाना चाहिए।
 - ख. प्राधिकारी ने अत्यधिक गोपनीयता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर उपयुक्त रूप से विचार नहीं किया है।
 - ग. प्राधिकारी ने अनुच्छेद 53 में यह नोट किया है कि घरेलू बिक्री का ***% लाभप्रद पाया गया। उसे गोपनीय और जनता को प्रकट न किया गया माना जाना चाहिए।
 - घ. अनुच्छेद 63(xxix) में, प्राधिकारी ने यह उल्लेख करते हुए कोरिया से सहयोगी निर्यातकों के तर्क को वृष्टिबश रिकॉर्ड किया है कि आस्ट्रेलिया का सहयोगी निर्यातकों के द्वारा लाई के लिए निर्यातों की अत्यधिक मात्रा है। जैसाकि प्रति उत्तर अनुरोधों में स्पष्ट किया गया था, प्रस्तुत किया गया विश्लेषण सहयोगी निर्यातकों के आंकड़ों का संदर्भ नहीं लेता है बल्कि समग्र रूप में कोरिया से निर्यातों का संदर्भ लेता है। इस कारण से उसे अंतिम जांच परिणामों में सही किया जाना चाहिए।
 - ड. **बीआईएस का प्रभाव:** प्राधिकारी ने अनुच्छेद 72 में नोट किया है कि जब क्षति की अवधि के आरंभ से अर्थात् बीआईएस के लागू होने के पूर्व से भी तुलना किया जाए तब आयातों में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि दर्शाई है। जबकि विचाराधीन उत्पाद के समग्र आयातों में आधार वर्ष से वृद्धि हुई है, मांग में संबद्ध देशों से आयातों का बाजार हिस्सा क्षति की पूरी अवधि और जांच की अवधि में कम रहा है। जांच की अवधि में चीन और कोरिया से आयातों का हिस्सा 2018 में बीआईएस प्रमाणन के कार्यान्वयन के पूर्व 1.23 और .54 प्रतिशत की तुलना में क्रमशः 2.26 और 2.16 प्रतिशत मात्रा है। आधार वर्ष की तुलना में भी, दोनों संबद्ध देशों की मांग में बाजार हिस्सा घरेलू उद्योग तथा अन्य देशों के मांग में बाजार हिस्सा से तुलना किए जाने पर मामूली रूप से ही बढ़ा है।
 - च. क्षति और कारणात्मक संबंध: सहयोगी निर्यातकों ने दोहराया है कि वर्तमान जांच में वास्तविक क्षति और कारणात्मक संबंध का अभाव है। जांच की अवधि की बाद की अवधि के दौरान उठाई गई कोई मानी गई क्षति का कारण पाटन को छोड़कर अन्य कारक को माना जा सकता है – इस संबंध में पर्याप्त साक्ष्य पहले ही रिकॉर्ड पर दिया गया है।
 - छ. सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए शून्य शुल्क जारी रखना: कोरिया से सहयोगी निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन वर्तमान समीक्षा सहित मूल जांच तथा सभी बाद की जांचों में नकारात्मक था। उसी प्रकार, चीन से सहयोगी निर्यातक अपने पाटन मार्जिन प्रस्तुत करते हैं और क्षति मार्जिन पूर्व की जांच में नकारात्मक थी और क्षति मार्जिन वर्तमान समीक्षा में भी नकारात्मक बनी हुई है। अतः, सहयोगी निर्यातकों के शून्य मार्जिन को जारी रखा जाना चाहिए।

ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

121. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध अधिकांशतः पुनरावृत्ति की प्रकृति के थे और उनका पहले ही समाधान इस जांच परिणाम में संगत स्थान पर किया जा चुका है। प्राधिकारी ने इसमें नीचे दिए गए शेष अनुरोधों की जांच की है।
122. जहां तक कीमत में कटौती के निर्धारण का प्रश्न है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने क्षेत्र-वार कटौती की आवश्यकता को नहीं दर्शाया है। केवल इस कारण से कि आयात पूर्व में किए गए हैं, क्षेत्र-वार कटौती की आवश्यकता को नहीं दर्शाता है क्योंकि पूर्वी भारत एक अलग बाजार के रूप में कार्य नहीं करता है। यह नहीं दर्शाया गया है कि आयात की गई वस्तुएं अन्य बाजारों में उसी कीमतों पर उपलब्ध नहीं थीं।

123. क्षति के मार्जिन के निर्धारण के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि क्षति रहित कीमत में घरेलू उद्योग के भाड़े को शामिल करना इस संबंध में अपनाई जा रही सतत् कार्य-पद्धति और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के अनुरूप नहीं होगी। तदनुसार, घरेलू उद्योग द्वारा वहन की गई अंतरदेशीय ढुलाई लागत को उनके क्षति-रहित कीमत में शामिल नहीं किया गया है।
124. समर्थन के आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए जाने के मुद्दे पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसने सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपयुक्त साक्ष्यों और यथा लागू प्रपत्रों के साथ अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया था। समर्थकों ने घरेलू उद्योग के सदस्यों को सीमित सहयोग देने का विकल्प चुना है। तदनुसार, प्राधिकारी ने रिकॉर्ड पर प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर अपना निर्धारण किया है।
125. जहां तक गोपनीयता के संबंध में दावे का प्रश्न है, प्राधिकारी दोहराते हैं कि इन्होंने व्यापार नोटिस की आवश्यकताओं के घरेलू उद्योग द्वारा उल्लंघन किए जाने पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए आरोपों का आकलन किया है और गोपनीयता संबंधी घरेलू उद्योग के दावे को व्यापार नोटिस तथा पाटनरोधी नियमावली के अनुरूप गोपनीयता की आवश्यकताओं के अनुरूप पाया है।
126. बीआईएस प्रमाणन के संबंध में स्व-कथनों के बारे में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि बीआईएस की आवश्यकता के मौजूद रहने के बावजूद, आयात की मात्राओं में काफी हद तक बीआईएस के पूर्व के स्तरों तक सामान्यीकरण हुआ है जिसके द्वारा रिकॉर्ड पर दिया गया साक्ष्य और संभावनाओं के मानदंडों पर विचार किया गया है जबकि यह निर्धारण किया गया है कि क्या वर्तमान समीक्षा में शुल्कों को जारी रखा जाना चाहिए या नहीं।
127. इस दावे के संबंध में कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अंतिम निर्धारण पाटन क्षति तथा कारणात्मक संबंध के बारे में रिकॉर्ड पर दी गई सभी सूचना को ध्यान में रखकर किया गया है। यह देखते हुए कि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा है, यह निर्धारण केवल घरेलू उद्योग को क्षति न होने के आधार पर नहीं किया जा सकता है और यदि शुल्कों को समाप्त होने दिया जाता है तब प्राधिकारी ने क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना पर भी विचार किया है।
128. अलग-अलग सहयोगी निर्यातकों के लिए शून्य मार्जिन जारी रखने के लिए अनुरोध के संबंध में, उसका समाधान शुल्क तालिका में किया गया है।

ड. पाटन और क्षति की संभावना के संबंध में निष्कर्ष

129. रिकॉर्ड पर साक्ष्य यह दर्शाता है कि संबद्ध वस्तुओं का पाटन और घरेलू उद्योग के क्षति की संभावना है। आयातों की मात्रा में उस अवधि जब बीआईएस को लागू किया गया था और विदेशी उत्पादकों के पास लाइसेंस नहीं था, को बाहर रखने के बाद ही उत्पादन और खपत की तुलना में तथा स्वतंत्र रूप में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग को वर्तमान जांच अवधि के दौरान क्षति नहीं हुई है। हालांकि रिकॉर्ड पर आंकड़ा दर्शाता है कि संबद्ध देशों में निर्यातकों के पास बहुत अधिक अतिरिक्त क्षमताएं हैं। यह भी नोट किया जाता है कि जबकि तीसरे देशों को उनके निर्यातों में गिरावट आ रही है, भारत को निर्यातों में उसी समय में वृद्धि हुई है। यह भी नोट किया जाता है कि भारत संबद्ध निर्यातकों के लिए एक कीमत आकर्षक बाजार है क्योंकि तीसरे देशों को बहुत अधिक निर्यात उस कीमत पर हुआ है जो निर्यातकों के सामान्य मूल्य से कम और उसके साथ ही घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और क्षति रहित कीमत से कम पर हुई है। भारत को निर्यात पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में बहुत अधिक हद तक बढ़ने की संभावना है और उसके कारण संभवतः भारत में घरेलू उद्योग को क्षति होगी। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में संबद्ध वस्तुओं के पाटन के और अधिक होने की संभावना है और उसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति होगी।

ढ. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

130. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य सामान्य तौर पर पाटन की अनुचित व्यापार कार्य-पद्धतियों के द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर से स्थापित हो सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से संबद्ध देश/प्रक्षेत्र से आयातों पर किसी भी रूप में प्रतिबंध नहीं लगेगा और इस कारण से उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

131. यह मान लिया गया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से संबद्ध वस्तुओं का उपयोग करते हुए निर्मित उत्पाद के कीमत स्तरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और इसके परिणामस्वरूप इस उत्पाद की सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में पाटनरोधी उपाय यदि विशेषकर पाटनरोधी शुल्क लगाना घरेलू उद्योग की क्षति का निवारण करने के लिए आवश्यक राशि तक सीमित हो, के द्वारा कम नहीं होगी। इसके विपरीत पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से पाटन कार्य-पद्धतियों द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ को समाप्त किया जाएगा, घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में गिरावट को रोका जाएगा और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

ण. निष्कर्ष

132. दिए गए तर्कों, उपलब्ध कराई गई सूचना और प्राधिकारी के समक्ष किए गए अनुरोधों और उपलब्ध तथ्यों जिसे उपर्युक्त जांच परिणामों में रिकॉर्ड किया गया है, के संबंध में तथा घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना का उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि:
- क. शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में, विचाराधीन उत्पाद का पाटन बहुत अधिक मात्रा में किए जाने की संभावना है।
 - ख. घरेलू उद्योग को, पाटनरोधी शुल्क को इस चरण में समाप्त होने दिए जाने की स्थिति में क्षति होने की संभावना है।
 - ग. यह दर्शाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है कि इस चरण में पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति फिर से होगी।

त. सिफारिशें

133. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस जांच की शुरुआत की गई थी और इसे सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सूचना देने के लिए समुचित अवसर दिया गया था।
134. इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त होने दिया जाता है तब पाटन और क्षति की संभावना का सकारात्मक साक्ष्य है, प्राधिकारी का यह मत है कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क को आगे जारी रखा जाना अपेक्षित है। जैसाकि इसमें ऊपर सिद्ध किया गया है, इस मामले के मामले तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी इसे उपयुक्त मानते हैं कि उन उत्पादकों जिन्होंने वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में भाग नहीं लिया है, को छोड़कर चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्कों की मौजूदा मात्रा का समय विस्तार करने की सिफारिश की जाए। इस निर्णायक समीक्षा जांच में उन गैर सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों को वर्तमान में यथा लागू शेष शुल्क लगाया गया है। तदनुसार संबद्ध देशों से उत्तर देने वाले उत्पादकों और गैर-सहयोगी उत्पादकों के लिए पाटनरोधी शुल्कों की सिफारिश नीचे शुल्क तालिका के अनुसार की जाती है। इस प्रकार प्राधिकारी इसे आवश्यक मानते हैं कि नीचे शुल्क तालिका में कॉलम 7 के अनुसार संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर यथा संशोधित निश्चात्मक पाटनरोधी शुल्क का आगे पांच वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने की सिफारिश की जाए।

शुल्क तालिका

क्र.स. (1)	उप शीर्ष (2)	वस्तुओं का विवरण (3)	मूल देश (4)	निर्यात का देश (5)	उत्पादक (6)	राशि (7)	माप की इकाई (8)	मुद्रा (9)
1	281511 और 281512	सभी ग्रेडों का कास्टिक सोडा	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य	हन्वा साल्युशंस कारपोरेशन	शून्य	ड्राई मीट्रिक टन	अम.डॉ.
2	-वही-	-वही-	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई भी देश	उपर्युक्त क्र.सं.1 पर दिए गए उत्पादक को छोड़कर कोई भी उत्पादक	21.90	ड्राई मीट्रिक टन	अम.डॉ.
3	-वही-	-वही-	संबद्ध देशों को छोड़कर कोई भी देश	कोरिया गणराज्य	कोई भी	21.90	ड्राई मीट्रिक टन	अम.डॉ.
4	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	तायनजिन डागु केमिकल कं. लि.	शून्य	ड्राई मीट्रिक टन	अम.डॉ.
5	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	उपर्युक्त क्र.सं.4 पर दिए गए उत्पादक को छोड़कर कोई भी उत्पादक	48.39	ड्राई मीट्रिक टन	अम.डॉ.
6	-वही-	-वही-	संबद्ध देशों को छोड़कर कोई भी देश	चीन जन.गण.	कोई भी	48.39	ड्राई मीट्रिक टन	अम.डॉ.

135. इस अधिसूचना के उद्देश्य से आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा यथा-निर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और इसमें समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3, 8ख, 9 और 9क के अंतर्गत शुल्कों को छोड़कर सभी सीमा शुल्क शामिल हैं।

136. इन जांच परिणामों के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध अपील सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा-कर अपीलीय नयायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

बी. बी. स्वेन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2020

FINAL FINDINGS

Case No. (SSR) 01/2020

Subject : Sunset Review of Anti-Dumping Investigation concerning imports of 'Caustic Soda' originating in or exported from China PR and Korea RP.

A. BACKGROUND OF THE CASE

F. No. 7/1/2020-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as "the Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as "the Rules") thereof.

1. The Designated Authority (hereinafter referred to as "Authority") received an application dated 4th January, 2020, through TPM Consultants, from Alkali Manufacturers Association of India (AMAI) (hereinafter also referred to as 'Applicant') requesting initiation of sunset review investigation (SSR) of anti-dumping duty on imports of 'Caustic Soda', (hereinafter also referred to as 'subject goods' or 'product under consideration') originating in or exported from China PR and Korea RP (hereinafter referred to as 'subject countries').
2. The original investigation was initiated on 14th May, 2002 to examine the nature and the extent of dumping and its injurious effect on the domestic industry with respect to Caustic Soda originating in or exported from China PR and Korea RP. The Authority vide its Preliminary Findings No. 14/10/2002-DGAD dated 21st September, 2002 recommended the imposition of provisional duty against the dumped imports of the subject goods from the subject countries, which was imposed vide Customs Notification No. 142/2002 – Customs dated 26th December, 2002. Thereafter, the Authority, vide its Final Findings No. 14/10/2002-DGAD dated 4th August, 2003, recommended imposition of anti-dumping duties, which were given effect vide Customs Notification No. 142/2003-Customs dated 23rd September, 2003 for a period of five years.
3. The Authority initiated a sunset review on 22nd November, 2007. The Authority, vide Final Findings Notification No. 15/11/2007-DGAD dated 21st November, 2008, recommended continued imposition of definitive anti-dumping duties against the imports of subject goods from the subject countries. The findings of the Authority were given effect vide Customs Notification No. 137/2008-Customs dated 26th December, 2008 and the duties were continued for a further period of five years.
4. On the request of the Applicant, the Authority initiated a mid-term review investigation against imports from Korea RP vide Notification No. 15/2/2010-DGAD dated 8th June, 2010. The Authority recommended modification of anti-dumping duties vide Notification No. 15/2/2010-DGAD dated 7th July, 2011 which were given effect vide Customs Notification No. 95/2011-Customs dated 3rd October, 2011.
5. The Authority initiated a second sunset review on 19th December, 2013. The Authority, vide Notification No. 15/23/2013-DGAD dated 18th June, 2015, recommended continued imposition of definitive anti-dumping duties against the imports of subject goods from the subject countries. The findings of the Authority were given effect vide Customs Notification No. 42/2015-Customs (ADD) dated 18th August, 2015.
6. In terms of Section 9A (5) of the Act, anti-dumping duties imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review, whether the expiry of anti-dumping duties is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. Further, Rule 23 (1B) of the Rules provides as follows

"any definitive antidumping duty levied under the Act, shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the designated authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own initiative or upon a duly

substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.”

7. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of anti-dumping duties is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
8. The Applicant filed an application dated 4th January, 2020, requesting initiation of sunset review of anti-dumping duties imposed earlier and seeking continuation of anti-dumping duties against imports of Caustic Soda from China PR and Korea RP. The request was based on the grounds that the expiry of the measure was likely to result in continuation of dumping of the subject goods and consequent injury to the domestic industry.
9. In view of the duly substantiated application with prima facie evidence of likelihood of dumping and injury filed on behalf of the domestic industry and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Rules, the Authority initiated the SSR Investigation vide Notification No. 7/1/2020-DGTR dated 7th February, 2020 to review the need for continued imposition of anti-dumping duties in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of the said anti-dumping duties is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
10. Pending conclusion of the investigation, the anti-dumping duties were extended vide Notification No. 25/2020-Customs (ADD) dated 17th August, 2020.

B. PROCEDURE

11. The scope of the present review covers all aspects of the Final Findings No. 14/10/2002-DGAD dated 4th August, 2003, Final Findings No. 15/11/2007-DGAD dated 21st June, 2008 and Final Findings Notification 15/23/2013-DGAD dated 18th June, 2015, by which imposition and continuation of anti-dumping duties on imports of subject goods originating in or exported from the subject country had been recommended, respectively.
12. The procedure described herein below has been followed:
 - i. The Authority vide Notification No. 7/1/2020-DGTR dated 7th February, 2020 published a public notice in the Gazette of India, Extraordinary, initiating sunset review investigation against imports of the subject goods from the subject countries.
 - ii. A copy of the public notice was forwarded by the Authority to the Embassies of the subject countries in India, known producers and exporters from the subject countries, known importers and other interested parties, to inform them of the initiation of the subject investigation in accordance with Rule 6(2) of the Rules.
 - iii. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters, and to the Government of the subject countries, through their Embassy, and to other interested parties who made a request therefor in writing in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra. A copy of the non- confidential version of the application was also made available in the public file and provided to other interested parties, wherever requested.
 - iv. The Authority forwarded a copy of the public notice initiating SSR investigation to the known producers / exporters in the subject countries, and other interested parties and provided them an opportunity to file response to the questionnaire in the form and manner prescribed within time limit as prescribed in the initiation notification or extended time limit, and make their views known in writing in accordance with the Rule 6(4) of the Rules.
 - v. The Authority forwarded copies of the Notification to the following known producers/exporters:
 - a. Bum Chang Ind. Co. Limited
 - b. DC Chemicals Limited
 - c. Dongying City Longxing Chemical Co.
 - d. Hanwha Solutions Corporation

- e. Hong In Chemical Co. Limited
 - f. Huanghua Tianxin Chemical Industries Limited
 - g. Jinhua Chemical Group Co. Limited
 - h. LG Chem Limited
 - i. Lotte Fine Chemical Co. Limited
 - j. Mudanjian Xiangda Chemicals Corp.
 - k. N.K. Agro Chemical Co. Limited
 - l. OCI Company Limited
 - m. Qindao Hisea Chem Co. Limited
 - n. Samsung Fine Chemicals Co.
 - o. Shanghai Chlor Alkali Chemicals
 - p. SS Pharm. Co, Limited
 - q. Tianjin Bohai Chemical Industries Import and Export Corp.
 - r. Tianjin Dagu International Corp
 - s. Tianjin Tiankai Chemical Industries Import and Export Corporation
 - t. Xilan Chemicals Co. Limited
 - u. Young Jin Chemical Co. Limited
- vi. The Government of the subject countries, through their Embassies in India were also requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the known producers/exporters was also sent to the Embassies of the subject countries along with the names and addresses of the known producers/ exporters from the respective subject countries.
- vii. The following producers/exporters from China PR and Korea RP filed a response to the exporter questionnaire:
- a. Bohai Chemical (HK) Limited
 - b. Hanwha Solutions Corporation
 - c. Mitsubishi Corporation
 - d. Tianjin Bohai Chemical Industries Import and Export Corp.
 - e. Tianjin Dagu Chemical Co., Ltd.,
 - f. Tricon Energy Ltd.
- viii. The Authority forwarded a copy of the Notification to the following known importers/ users of subject goods in India calling for necessary information, in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
- a. Abhay Chemicals Limited
 - b. Adani Exports Limited
 - c. Adani Wilmar Limited
 - d. Albright Wilson Chemicals Limited
 - e. Arvind Mills Limited
 - f. Bilag Industries Pvt Limited
 - g. Birla Cellulose Limited
 - h. C J Shah & Co
 - i. Central Pulp Mills Limited

- j. Cyanides & Chemicals Company Prop. Hindustan Development Cor. Limited
 - k. Daurala Organics Limited
 - l. Deepak Nitrite Limited
 - m. Godrej Soaps Limited
 - n. Gujarat Narmada Fertilizer & Chemicals Limited
 - o. Gujarat State Fertilizer & Chemicals Limited
 - p. Hindustan Lever Limited
 - q. Hindustan Link & Resins Limited
 - r. Hitsu Industries Limited
 - s. Indian Farmer Fertilizer Coop. Limited
 - t. Indian Oil Corporation Limited
 - u. Jaysynth Dyechem Limited
 - v. Libra Foams
 - w. Link Pharma Limited
 - x. Meghmani Organics Limited
 - y. Narmada Chemature Petrochemicals Limited
 - z. National Aluminium Company Limited
 - aa. Nirma Limited
 - bb. Pab Chemicals (P) Limited
 - cc. Products Limited
 - dd. Rama News Prints & Papers Limited
 - ee. Rubamin Limited
 - ff. Sabero Organics Limited
 - gg. Shri Ramchandra Straw
 - hh. Torrent Gujarat Biotech Limited
 - ii. Transpek Silox Industries Limited
 - jj. Vedanta Limited (Aluminium Division)
- ix. The following importer/user has filed a questionnaire response/submission in the present investigation:
- a. Vedanta Limited
 - b. Aluminium Association of India
- x. The request for continuation of anti-dumping duty has been supported by Chemfab Alkalies Limited, Chemplast Sanmar Limited, DCM Shriram Limited, Durgapur Chemicals Limited, Gujarat Fluorochemicals Limited, Lords Chloro Alkali Limited, Meghmani Finechem Limited, Nirma Limited, Orient Paper Mills, Punjab Alkalies & Chemicals Limited, Reliance Industries Limited, Tamilnadu Petroproducts Limited, TATA Chemicals Limited, TGV SRAAC Limited, The Andhra Sugars Limited and The Travancore – Cochin Chemicals Limited.
- xi. The period of investigation (POI) for the purpose of the present investigation is April 2019-December 2019 (9 months). The injury analysis period covers April 2016- March 2017, April 2017- March 2018, April 2018- March 2019 and the POI.

- xii. Transaction-wise imports data for the POI and the preceding three years was procured from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and Directorate General of Systems (DGS). The Authority has, relied upon data of DGCI&S and DGS for calculating the volume and value of imports of the subject goods in India.
- xiii. Further information was sought from the Applicant to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of present investigation.
- xiv. The Authority made available the non-confidential version of the submissions made by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.
- xv. The domestic industry has submitted financial data duly certified by their Chartered/Cost Accountant. The non-injurious price (NIP) based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules has been worked out so as to ascertain whether anti-dumping duties lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- xvi. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 8th October, 2020 through video conferencing. The parties, which presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
- xvii. The submissions made by the interested parties, arguments raised and information provided by various interested parties during the course of investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority in this Disclosure Statement.
- xviii. The Authority, during the course of investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of this Disclosure Statement to the extent possible and verified the data/ documents submitted by the domestic industry to the extent considered relevant, practicable and necessary.
- xix. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xx. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority considered such interested parties as non-cooperative and recorded this Disclosure Statement on the basis of the facts available.
- xxi. In accordance with Rule 16 of Rules Supra, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide disclosure statement dated 26th and 27th October 2020 and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in this final findings. The Authority notes that most of the post-disclosure submissions made by the interested parties are mere reiteration of their earlier submissions. However, the post-disclosure submissions to the extent considered relevant are being examined in these Final Findings.
- xxii. *** in this Final Findings represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.
- xxiii. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US\$1= 71.24.

C. SCOPE OF PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

13. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as follows

“The product under consideration in the present investigation is Sodium Hydroxide (chemical nomenclature of NaOH), commonly known as Caustic Soda originating in or exported from Korea ROK and China PR. Caustic Soda is an inorganic, soapy, strongly alkaline and odourless chemical.

Caustic Soda is classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975 under Customs head 2815.11 and 2815.12. As per ITC 8-digit classification, the product is classified under the Custom Heading 2815.1101, 28151102 and 2815.1200.”

C.1. Submissions of the domestic industry

14. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the scope of product under consideration or like article.
- Since the present investigation is a sunset review investigation for continued imposition of anti-dumping duty, the product under consideration is the same as in the original investigation and earlier conducted sunset review investigation.
 - The goods produced by the domestic industry and that imported into India are like article.

C.2. Submissions of other interested parties

15. No submissions have been made by the other interested parties regarding the scope of product under consideration or like article.

C.3. Examination by the Authority

16. The product under consideration in the present investigation is Caustic Soda of all types. Caustic Soda is chemically known as NaOH or Sodium Hydroxide. It is an inorganic, soapy, strongly alkaline and odourless chemical.
17. The present investigation being an SSR investigation, the scope of the product under consideration remains the same as that in the original and subsequent review investigation. In the earlier investigation, the product under consideration was defined as follows:
- “The product under consideration in the present investigation is Sodium Hydroxide (chemical nomenclature NaOH), commonly known as Caustic Soda originating in or exported from Korea RP and PR China. Caustic Soda is an inorganic, soapy, strongly alkaline and odourless chemical and finds application in various fields like manufacture of pulp and paper, newsprint, viscose yarn, staple fibre, aluminium, cotton, textiles, toilet and laundry soaps, detergent, dyestuffs, drugs and pharmaceuticals, petroleum refining etc.”*
18. The product under consideration is classified under Chapter Heading 28, under the tariff codes 28151110, 28151190 and 28151200. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of product under consideration.
19. Caustic Soda is produced in two forms, that is, lye and solids. Liquid form can be converted into solid and the solid form can be reconverted into liquid with ease and without any change in the chemical properties of the product. The solid form has ease of storage and transportation whereas the liquid form has easy solubility. For end use both the forms are substitutable and interchangeable.
20. Caustic Soda is industrially produced as a 50% solution by variations of the electrolytic chlor-alkali process. This involves the electrolysis of an aqueous solution of sodium chloride. The sodium hydroxide builds up at the cathode, where water is reduced to hydrogen gas and hydroxide ion. To produce the subject goods, it is necessary to prevent reaction of the NaOH with the chlorine. This is typically done in one of three ways, using the mercury cell process, diaphragm cell process or the membrane cell process.
21. On the basis of information on record, the Authority holds that there is no known difference in the subject goods produced by the domestic industry and those imported from the subject country. The two are comparable in terms of physical characteristics, manufacturing process, functions and uses, product specifications, distribution and marketing, and tariff classifications of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers have used and are using the two

interchangeably. The Authority holds that the product manufactured by the Applicants constitutes like article to the subject goods being imported into India from the subject country in terms of Rule 2(d) of the Rules.

D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1. Submissions of the domestic industry

22. The following submissions have been made by the Applicant with regard to the domestic industry and standing:

- i. The application has been filed by the Alkali Manufacturers Association of India (AMAI) on behalf of its members. The Association has 23 domestic producers of the subject goods as its members, which represent the entirety of the Indian industry.
- ii. The following members of the Association have participated in the present investigation.
 - a. DCW Limited,
 - b. Grasim Industries Limited,
 - c. Gujarat Alkalies and Chemicals Limited,
 - d. SIEL Chemical Complex.
- iii. The applicant domestic producers account for 44.61% of the total domestic production.
- iv. The Applicant domestic producers have neither imported nor are related to the exporter or importer of the subject goods in India.
- v. Out of the remaining producers, 16 producers have supported the continuation of the anti-dumping duty.
- vi. Responding to the arguments regarding change in scope of domestic industry, it was submitted that some of the producers, which participated in earlier investigations, have been taken over by Grasim Industries and have provided data in the present investigation as units of Grasim.
- vii. The scope of the domestic industry has been the same in each investigation, over the last four years.
- viii. In response to the submission that support letters are not as per prescribed format, it is submitted that Trade Notice 11/2018 allows parties, which have not filed responses, to participate in the investigation. In any case, the provisions of Rule 5 are not applicable in sunset reviews.
- ix. The request for continuation of anti-dumping duty has been supported by Chemfab Alkalies Limited, Chemplast Sanmar Limited, DCM Shriram Limited, Durgapur Chemicals Limited, Gujarat Fluorochemicals Limited, Lords Chloro Alkali Limited, Meghmani Finechem Limited, Nirma Limited, Orient Paper Mills, Punjab Alkalies & Chemicals Limited, Reliance Industries Limited, Tamilnadu Petroproducts Limited, TATA Chemicals Limited, TGV SRAAC Limited, The Andhra Sugars Limited and The Travancore – Cochin Chemicals Limited.

D.2. Submissions of the other interested parties

23. The following submissions have been made by other interested parties with regard to the domestic industry and standing:

- i. The Applicant association has been selectively using combination of member-producers based on circumstance, injury figures and timing of the investigation. While 13 producers had participated in the first investigation, and 8 in the original investigation, only 4 producers are participating in the present investigation.
- ii. Applicant association must not be permitted to exercise its discretion to select only those producers that show injury.
- iii. Producers included as domestic industry must not be based on their treatment of chlorine as co-product or by-product, which is directly related to the cost of production of such producers.

- iv. The support letters filed by the members of AMAI do not provide information about their performance, which is in violation of Trade Notice No. 13/2018.
- v. The petitioner has refused to follow the requirements of Trade Notice No. 13/2018, claiming that such trade notices do not supersede the law. However, such trade notices not being in conflict with the law, need to be followed for providing relevant information, as per Rule 6(4).

D.3. Examination by the Authority

24. Rule 2(b) of the Rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.

25. The present SSR application has been filed by the Alkali Manufacturers Association of India (AMAI) on behalf of its members. The Association has 23 domestic producers of the subject goods as its members, which represent the entirety of the Indian industry.
26. The following members of the Association have participated in the present investigation:
- a. DCW Limited,
 - b. Grasim Industries Limited,
 - c. Gujarat Alkalies and Chemicals Limited,
 - d. SIEL Chemical Complex.
27. Following plants of Grasim Industries have provided relevant information:
- a. Ganjam
 - b. Karwar
 - c. Nagda
 - d. Rehla
 - e. Renukoot
 - f. Veraval
 - g. Vilayat
28. With the regard to the claim of the producers/exporters that the Applicant association has been selectively using combination of producers based on circumstance, injury figures and timing of the investigation, the Authority notes that the application has been filed by the Applicant association on behalf of its members. Grasim Industries Limited has taken over the plants of some of these producers, such as Bihar Caustic and Chemical Limited, Jayshree Chemicals Limited and Indian Rayon & Industries Limited. These plants have now participated as a part of Grasim. Further, there is no legal obligation on the Authority or the applicant to maintain the same scope of the domestic industry. The Authority is required to ascertain whether the applicant companies production meets the requirement of domestic industry under the law.
29. The Applicant producers collectively account for a major proportion, that is, 44.91% of the total domestic production. It is also noted that the Applicant producers are not related to any exporter or importer of the subject goods and have not imported the product under consideration. The Authority, therefore, holds that the Applicants constitute domestic industry under Rule 2(b) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions of the domestic industry

30. The following submissions have been made by the Applicant with regard to confidentiality:
- i. The exporters have claimed excessive confidentiality and the non-confidential version of responses filed do not allow a reasonable understanding of the information filed.

- ii. The exporters have abused Rule 7 by claiming confidentiality regarding all relevant information, including names of the exporters, which were disclosed at the time of oral hearing. The confidentiality claims of the exporters are not limited to proprietary or sensitive information.
- iii. As much as 70-80% of the responses have been redacted and even publicly available information has been claimed confidential.
- iv. The Authority must not assume confidentiality of information and must examine whether the claim by the party is bona fide and germane to the rights and legitimate interests of the party or not.
- v. The exporters should not be allowed to assert that different standards should be followed for confidentiality claimed by the domestic industry and by the exporters.
- vi. The exporters have claimed almost the entirety of Part II of the questionnaire responses as confidential, which is essential for likelihood analysis.
- vii. The exporters have violated Trade Notice 10/2018 by claiming confidentiality regarding broad stage-wise manufacturing process, the raw materials used and the names of related parties engaged in production and sale of product under consideration.
- viii. The questionnaire responses do not disclose the channel of distribution followed by the exporters, which is essential to ascertain whether all entities forming part of such channel have participated in the investigation or not.
- ix. The domestic industry has justified the confidentiality claimed by it.
- x. The ICIS reports not being proprietary information of the domestic industry, but of the market research agency, are not amenable to disclosure. Further, prices used to determine normal value from such reports are already disclosed in the petition.
- xi. Information regarding trend of export prices has already been disclosed by domestic industry vide letter dated 30th May, 2020.
- xii. Disclosure of actual costs, prices, non-injurious price, interest and profits would adversely impact the petitioning domestic producers in inter-se competition, competition with other producers, and their ability to negotiate prices with their customers. Further, the Authority has also considered such information as confidential in its recent findings.
- xiii. The petitioner has disclosed that it is unaware of the average industry norms for productivity, inventory and return on investment.
- xiv. Information regarding R&D expenses and fund raised being for the company as whole and not attributable to product under consideration, is as per the balance sheet of the petitioner.
- xv. Selling price of the domestic industry in various regions is confidential and cannot be disclosed. However, price undercutting has been disclosed in range.
- xvi. Transaction-wise import data is to be provided only when it is not claimed confidential, as noted by CESTAT in *Exotic Décor v. Designated Authority*. Since the domestic industry has claimed confidentiality and has also submitted an undertaking under Trade Notice 7/2018, such data is not required to be disclosed.

E.2. Submissions by other interested parties

31. The following submissions have been made by other interested parties with regard to confidentiality:
 - i. The petitioner has claimed excessive confidentiality and failed to disclose (i) value of production by other domestic producers, (ii) actual sales value, PBIT, interest and depreciation (iii) Average industry norms for productivity, inventory and return on investment (iv) R&D expenses, funds raised, (v) trend of export price, (vi) non-injurious price as a range, and (vii) Purchase quantity of product under consideration. This is inconsistent with the guidelines laid down under Trade Notice 10/2018.
 - ii. The petitioner has not disclosed ICIS reports, which have been used for construction of normal value.

- iii. The petitioner has failed to provide transaction-wise import data despite repeated requests in the preliminary submissions, oral hearing and communication dated 8th October, 2020. As noted by the CESTAT in *Exotic Décor vs. Designated Authority*, the same was required to be provided in Excel format.

E.3. Examination by the Authority

32. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties through the public file containing non-confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection as per Rule 6(7).
33. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provide as follows:
- “Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*
- (2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.*
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”*
34. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidence submitted by various interested parties in the form of public file. The information related to imports, performance parameters and injury parameters of domestic industry has been made available in the public file. Business sensitive information has been kept confidential as per practice. The Authority notes that any information which is available in the public domain cannot be treated as confidential.
35. The Authority has considered the claims of confidentiality made by the Applicants and the opposing interested parties and on being satisfied about the same, the authority has allowed the claim on confidentiality. The Authority made available to all interested parties the public file containing non-confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection, upon request as per Rule 6(7).
36. With regard to the claim of non-disclosure of the ICIS reports (which constitutes underline evidence used to support the figures of normal value adopted), it is noted that the applicant has not disclosed the same on the grounds that it is third party information, and the prices used for determination of normal value (which constitutes information) have already been disclosed to the interested parties. The Authority therefore considers that non-disclosure of ICIS-LOR copy is justified. Insofar as DGCI&S data is concerned, the Authority notes that the same has also been disclosed to the interested party in so far as volume & value of imports from each of the country exporting to India is concerned. Further, the applicant has made available a complete list of transaction wise import data relied upon by the applicant to quantify volume and value of imports from individual countries. The interested parties have not established how these disclosures are insufficient for them to defend their interests in the present case. It is also noted that the Korean producer participating in the present investigation has reported volume of imports largely corroborating with the volume of imports reported in the DGCI&S. Further, it is noted that any interested party can obtain data independently

from the DGCI&S and lodge its own counter claim with regard to volume and value of imports. Above all, the Authority has not adopted the information provided by the applicant. The Authority has independently called information from the DGCI&S and DG Systems, corroborated the same with various information filed by various interested parties and thereafter adopted its own information in the present final findings.

F. MISCELLANEOUS ISSUES

F.1. Submissions by other interested parties

37. The following submissions have been made by the other interested parties:

- i. The Authority has conducted 19 separate investigations on imports of subject goods from various countries, which indicates abuse of the trade remedial mechanisms.
- ii. Continued protection to the domestic industry has been detrimental for the user industry that face increased in costs of products as well as for the domestic industry itself, which has failed to make improvements in their capacities, efficiencies or technologies.
- iii. Caustic soda contributes 20% of the cost of alumina, and thus, the continuation of duties has an adverse impact. Downstream industry like Alumina is already at disadvantage due to inverted duty structure on raw material.
- iv. The user industry has made sincere efforts to source significant volume of subject goods from the domestic industry. However, the domestic industry is reluctant to enter into long term contracts with the users at reasonable prices, which are being provided to them by the foreign producers, and has instead demanded huge premiums for such commitments.
- v. The downstream alumina industry is already suffering price crunch since 2018 and with continuation of duties, the industry is unlikely to compete in the market.
- vi. Restrictions on imports would result in monopoly pricing by the domestic producers, as happened in 2018-19.

Other issues

- vii. Hanwha Solutions Corporation, through a separate name change application had intimated the Hon'ble Designated Authority that there had been a name change with effect from 06 January 2020 whereby it was previously known as Hanwha Chemical Corporation and is currently known as Hanwha Solutions Corporation.
- viii. The Hon'ble Designated Authority vide communication dated 06 August 2020 had sought certain clarifications and documents with respect to the change in name.
- ix. Hanwha Solutions Corporation accordingly provided a detailed response dated 27 August 2020 along with all necessary documentation relating to the change in name.

F.2. Submissions of the domestic industry

38. The domestic industry has submitted as under, in response to contentions raised by the other interested parties:

- i. Regarding the claim that 19 investigations have been conducted, it was submitted that anti-dumping duty has been imposed based on facts established before the Authority.
- ii. The user industry cannot claim right to dumped imports citing increased costs, since unfair priced imports create an unfair competition in the market.
- iii. The responding user, Vedanta Limited, has not been substantiated adverse impact of duty with evidence, while other users have not objected to continuation of duties.
- iv. Issues pertaining to inverted duty structure should be raised by the user before appropriate forum, and not the Authority.
- v. The user has not established its claimed efforts to locally source subject goods though any evidence. It furthers the implication that the user has interest in imports available at dumped prices.

- vi. Difficulties faced by users due to other factors are irrelevant to present investigations. Numerous investigations being conducted relating to aluminum products imply dumping of such products causing hardships to the users.

F.3. Examination by the Authority

39. With regard to the contention of the other interested parties regarding the multiple investigations on imports of subject goods and long duration of the duties imposed, the Authority notes that the purpose of anti-dumping duty is only to create a level playing field and to provide relief to domestic industry against injurious dumping. The present investigation has been initiated to examine the likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury, in the event of expiry of duty. Should the Authority find that dumping and injury are likely to continue or recur, in the absence of duties, the anti-dumping duties shall be extended, notwithstanding the period of imposition of duties or the number of investigations. The Authority also notes that there is no evidence of monopoly pricing by the domestic industry as a result of anti-dumping duties in force. In fact, there are a large number of domestic producers of the product in the Country.
40. With regard to issues relating to change in the name of Hanwha Chemical Corporation to Hanwha Solutions Corporation, it is noted that no comments have been filed by any other interested parties.
41. The Authority notes that a cooperating exporter, i.e. Hanwha Chemical Corporation has undergone a change in name with effect from 06 January 2020, to Hanwha Solutions Corporation on account of merger of two entities (that were a part of the Hanwha Group) with Hanwha Chemical Corporation. It is noted that the other two entities were not engaged in manufacture, distribution import or export of the product under consideration. The Authority further notes that the name change is conducted pursuant to the applicable laws in Korea.
42. Having carefully perused all the supporting documentation submitted by Hanwha Solutions Corporation, the Authority also notes that this merger has not resulted in a change of the ownership of the erstwhile company and there is no material impact on the operations relating to the product under consideration. Accordingly, the change in name from Hanwha Chemical Corporation to Hanwha Solutions Corporation is reflected in the final findings.

G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING AND DUMPING MARGIN

G.1. Submissions of the domestic industry

43. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to normal value, export price and dumping margin:
 - i. There is continued dumping of the product under consideration from the subject countries and the exporters have a history of dumping.
 - ii. Since the producers from China PR have not demonstrated that they are operating under market economy conditions, the normal value should be determined on the basis of provisions of para 7 of Annexure – I.
 - iii. Export prices may be determined based on the responses of co-operating exporters, subject to fulfilment of value chain condition. However, since the responding producer from China PR is not even listed as a supplier in import data, it casts a doubt over fulfilment of value chain condition.
 - iv. Korea RP being a country under investigation, cannot be considered as an appropriate surrogate country.
 - v. Availability of data of Korean producer does not imply acceptance of the data and as such, the Authority is required to evaluate conditions under Para 7 of Annexure-I as well as the conditions for determination of surrogate country.
 - vi. The respondents have not provided evidence to the fact that Korea RP and China PR are at same level of economic and product development. Thus, selling price of Korea RP cannot be considered as normal value for China PR. Further, exports to India from Korea RP being dumped, cannot also be used for determination of normal value for China PR.

- vii. Price of subject goods in Chinese Taipei have been provided based on the IHS Market report which gives a macro-view of the prices prevailing in the market
- viii. The dumping margin of Hanwha Solutions Corporation being negative in the original investigation itself, the petitioner accedes that no duty can be levied against its exports in the present investigation.
- ix. The duty for the remaining producers/exporters from Korea RP should be determined based on the information made available in the petition.

G.2 Submissions of other interested parties

44. The following submissions have been made by other interested parties with regard to normal value, export price and dumping margin:
- i. The responses filed by the exporters show that there is no dumping by the cooperative exporters.
 - ii. The responses filed by the exporters should be considered for the purpose of determination of normal value, export price and dumping margin.
 - iii. Since in the present case, the data regarding domestic and third country sales as well as cost of production in Korea RP is available before the Authority, Korea RP should be considered as an appropriate surrogate country. This is consistent with the provisions of Annexure – I, the Manual of SOP and the decision of the Supreme Court in Shenyang Matsushita S. Battery Co. Ltd. v. Excide Co. Ltd and as per practice of the Authority in previous cases.
 - iv. Korea RP is the appropriate surrogate country as both the countries are at same level of economic development and similar product development. Further, the market for caustic soda in both countries is at the same level of development, using similar production technologies, with similar capacities as well as closely comparable import volumes subject to the same customs duty in India.
 - v. Since petitioners have admitted that direct evidence of selling price in Chinese Taipei is not available and there is no evidence to show that it is comparable to China, there is no basis for selection of Chinese Taipei as an appropriate surrogate country.

G.3. Examination by the Authority

45. As per section 9A(1)(c) of the Act, the normal value in relation to an article means:
- (i) *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when destined for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - (ii) *when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either -*
 - (a) *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - (b) *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*
- Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.*
46. The Authority sent questionnaires to the known exporters/producers from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed. The following producers/exporters from subject countries have filed exporter's questionnaire response:
- a. Bohai Chemical (HK) Limited, China PR (Exporter of Chinese origin goods)
 - b. Tianjin Bohai Chemical Industries Import and Export Corp., China PR (Exporter)

- c. Tianjin Dagu Chemical Co., Ltd., China PR (Producer)
- d. Hanwha Solutions Corporation, Korea RP (Producer)
- e. Mitsubishi Corporation, Japan (Exporter of Korean origin goods)
- f. Tricon Energy Limited, USA (Exporter of Korean and Chinese origin goods)

It is noted that the dumping margin for Hanwha Solutions Corporation (Hanwha), for exports through Tricon Energy Limited, was found de-minimis in the original investigation.

G.3.1. Determination of Normal Value

Market economy status for China PR

47. Article 15 of China's Accession Protocol provides as follows:

“(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector.”

48. It is noted that while, the provision contained in Article 15 (a) (ii) have expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO Anti-Dumping Agreement read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the Indian Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire for claiming the market economy status. It is noted that no producer/exporter from China PR has claimed market economy status in the present sunset review investigation. Accordingly, the normal value computation is required to be done as per provisions of para 7 of Annexure I of the Rules. The normal value and export price for all the producers/exporters from the China PR have been determined as below.

Normal value for China PR

49. The Authority notes that none of the producers / exporters from China PR have filed the supplementary questionnaire response to rebut the presumptions as mentioned in para 8 of Annexure I of the Rules. Under these circumstances, the Authority has to proceed in accordance with Para 7 of Annexure I to the Rules in this regard.
50. While the domestic industry has claimed that Chinese Taipei should be claimed as the appropriate surrogate country, other interested parties have submitted that Korea RP should be considered for this purpose. However, the Authority notes that the none of the interested parties have provided sufficient information to establish that Chinese Taipei or Korea RP can be considered as surrogate country, having regard to the requirements laid down under para-7 of Annexure-I, both with regard to the same level of development of the country, or level of development of product. In the absence of any evidence in this regard, the Authority has determined normal value for producers/exporters from China PR on the basis of price paid or payable in India for like products as per Para 7 of Annexure I.
51. In view of the above, the normal value for the product under consideration imported from China PR into India is determined based on cost of production, as optimized for the domestic industry, with reasonable additions for selling, general & administrative expenses and profit margin. Accordingly, the normal value has been constructed for all producers and exporters in China PR for the product under consideration during the period of investigation as given in the dumping margin table.

Normal Value for producers/exporters of subject goods from Korea RP**Hanwha Solutions Corporation, Tricon Energy Limited and Mitsubishi Corporation****Normal Value**

52. During the POI, Hanwha Solutions Corporation (producer of the subject goods) sold the PUC directly to customers in the domestic market. The Authority notes that Hanwha made domestic sales to both related and unrelated customers. The Authority further notes that the price to related customers is marginally higher than that from unrelated customers. Accordingly, all the domestic sales have been considered for the purpose of determining normal value. It is also noted that sales of Hanwha Solutions Corporation are in sufficient quantity in the domestic market.
53. In order to determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production of subject goods. In case profit making transactions are more than 80% then the Authority considers all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value. Where the profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of normal value. The Authority notes that ***% of the domestic sales found to be profitable. Therefore, all the sales have been considered for the purpose of determining normal value. The Normal value determined on is mentioned in the dumping margin table. .

G.3.2. Determination of Export Price**Export price for producers/exporters of subject goods from China PR****Tianjin Dagu Chemical Co., Ltd., Tianjin Bohai Chemical Industries Import & Export Corporation, and Bohai Chemical (HK) Limited and Tricon Energy Limited**

54. During the POI, all sales by Tianjin Dagu Chemical Co., Ltd to India for the PUC were made through Tianjin Bohai Chemical Industries Import & Export Corporation, Bohai Chemical (HK) Ltd and Tricon Energy Limited. The Authority notes that all the exporters involved in the trade channel have filed their separate questionnaire response. The Authority notes that for sales from Tianjin Dagu Chemical Co. Ltd. has exported ***MT of the PUC to India during period of investigation.
55. The Authority has conducted the profitability test of the all the cooperating trading companies namely Tianjin Bohai Chemical Industries Import & Export Corporation, Bohai Chemical (HK) Ltd and Tricon Energy Limited. The Authority has determined the ex-factory export price based on the export price of trader after taking into consideration the surveyor cost, and profit / loss of the trader(s) (wherever applicable). Further, price adjustments have been allowed on account of ocean freight, insurance, inland freight, port and other related expenses. The net export price after these adjustments is given in the dumping margin table.

Other producers and exporters from China PR

56. The export price for other non-cooperating exporters from China PR has been determined as per best facts available taking into account the data of the DGCI&S data and questionnaire response of the co-operating exporters and the same is mentioned in the dumping margin table.

Export price for producers/exporters of subject goods from Korea RP**Hanwha Solutions Corporation, Tricon Energy Limited and Mitsubishi Corporation**

57. Hanwha Solutions Corporation (“Hanwha”) has filed questionnaire response along with its unrelated trading companies, namely, Tricon Energy Limited (“Tricon”) and Mitsubishi Corporation (“Mitsubishi”). The Authority notes that Hanwha has exported ***MT of the PUC during period of investigation.
58. The Authority has conducted the profitability test of the all the cooperating trading companies namely Tricon and Mitsubishi. All the trade channels of exports to India are found to be profitable, therefore, the Authority has considered the prices of Hanwha to determine the ex-factory export price. Further, the producer has claimed Surveyor Cost, Handling Charges, Credit Cost, Bank Charges and Domestic Brokerage as post factory expenses for making exports to India which has been accepted by the Authority. The net export price after these adjustments is given in the dumping margin table.

Other producers and exporters from Korea RP

59. The export price for other non-cooperating exporters from Korea RP has been determined as per best facts available taking into account the data of the DGCI&S data and questionnaire response of the co-operating exporters and the same is mentioned in the dumping margin table.

G.3.3. Dumping Margin

60. Based on normal value and export price determined as above, the dumping margin for producers/exporters from China PR and Korea RP has been determined by the Authority and the same is provided in the table below:

Country	Producers	Normal Value USD/MT	Export Price USD/MT	Dumping Margin (USD/MT)	Dumping Margin %	Dumping Margin % Range
Korea RP	Hanwha Solutions Corporation	***	***	***	***	(0-10)
Korea RP	Others	***	***	***	***	0-10
China PR	Tianjin Dagu Chemical Co Ltd	***	***	***	***	0-10
China PR	Others	***	***	***	***	10-20

61. It is noted that the dumping margin in case of Hanwha Solutions Corporation is negative.

H. INJURY AND CAUSAL LINK**H.1. Submissions of the domestic industry**

62. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to injury, likelihood and causal link:
- There is continued dumping of the product under consideration from the subject countries and the exporters have a history of dumping.
 - Continued dumping of subject goods for more than 18 years shows that quantum of duties is insufficient to dissuade dumping.
 - The exporters of the product under consideration have also dumped the subject goods in third countries.

- iv. Despite duties in force, there is an increase of 108% in volume of dumped imports over the injury period. The volume of imports is the highest in the present period of investigation, when compared over the injury period.
- v. The rate of increase in imports has outpaced the growth in demand.
- vi. The imports have increased despite mandatory BIS certification, and even excluding the period affected by such mandatory certification requirements. It is therefore without any basis that the BIS standards have led to a decline in imports.
- vii. The dumped imports have also increased in relation to production and consumption.
- viii. Further, the price of the subject imports has declined very steeply, even though there has been no decline in the cost of the domestic industry.
- ix. Not only has the price to India reduced, but also, there is a decline in price of exports from the subject countries to third countries.
- x. While the price undercutting on an average basis is negative, it is positive on a region-wise basis.
- xi. While the performance of the domestic industry improved till 2018-19, it shows a decline in the period of investigation, as the imports increased. This shows that the imports continue to be impacted by the subject imports.
- xii. Not only are there surplus capacities of the subject goods in the subject countries, the exporters are also expanding capacities further. China PR alone has surplus capacities of about 94.5 lakhs MT, as against a demand in India is only 36 lakhs MT.
- xiii. While significant capacities have been created for exports, the total exports from the subject countries have suffered a decline whereas exports to India have increased. Thus, in the event of expiry of duty, India is likely to serve as an alternate market to absorb these exports.
- xiv. The responses filed by the exporters also show that while their exports to India have increased, their total sales have suffered a setback.
- xv. Despite anti-dumping duties in force, India continues to be a major market for the exporters in the subject countries. Thus, in the event of expiry of duty, the exporters are likely to focus on this market.
- xvi. Further, India is a price attractive market for the exporters in the subject countries. Thus, in the event of cessation of duty, exports presently made to third countries are likely to be diverted to India.
- xvii. If the lower priced imports from other countries are diverted to India, there is likely to be a significant impact on the volumes or prices, or both of the domestic industry.
- xviii. The present investigation being a sunset review, there is no requirement to establish a causal link between the likely dumping and likely injury as observed by the Appellate Body in United States – Anti-dumping measures on OCTG from Mexico.
- xix. The domestic industry is not likely to suffer injury due to any other factor.
- xx. If the domestic industry seeks to maintain its prices, the imports are likely to take away its market share, leading to a decline in its production, sales and capacity utilization. However, if the domestic industry seeks to retain its customers, its profitability is likely to suffer significantly and it is likely to face losses and negative return on investment.
- xxi. Contrary to the submissions of the respondents, injury examination is required to be conducted for defined domestic industry and not for industry as whole as per Rule 11(2) and Panel report in EC – Bed Linen. Even the Appellate Body in US – Hot-Rolled Steel Products has also noted that the injury analysis has to be undertaken for the defined domestic industry.
- xxii. There is no requirement that the domestic industry must have suffered injury in a sunset review, and the Authority is required to examine the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in event of cessation of duty.

- xxiii. Exports to India have increased while exports to other countries have declined, implying imports are likely to increase in future, despite requirements of public procurement and BIS certification.
- xxiv. BIS licensing is a standardization of quality procedure and not a barrier. Further, exporters were given a period of 4 months to obtain such license before it was made mandatory.
- xxv. BIS licensing authority has issued 18 licenses to foreign producers/exporters. Failure of the exporter to obtain license even after 3 years is due to their inability to satisfy conditions of license and not due to any delay by the licensing authority.
- xxvi. Contrary to the contentions of the respondents, BIS licenses were initially issue for a period of 2 years but are renewable for upto 5 years through a simple and shorter procedure, enabling the exporters to renew license without any difficulty.
- xxvii. Grievances regarding the delay in issuance of BIS license should be raised before the appropriate forum and not before the Authority.
- xxviii. Domestic procurement requirement applicable to only a few public sector consumers, cannot alter market dynamics since major users from the private sector are free to procure foreign goods. In any case, NALCO has continued to float global tenders.
- xxix. Respondents have failed to establish their claim, with actual data, that imports have declined subsequent to the public procurement order.
- xxx. Petitioner has provided post POI data, for the period January to June 2020, vide submissions dated 16th October 2020.
- xxxi. The market share of imports has not increased marginally but has doubled over the injury period, contrary to the contentions of the respondents.
- xxxii. Responding to the contention that imports increased as producers in other countries did not have BIS licenses, it was submitted that there was sufficient capacity in the country to meet the demand in the country and thus, the goods could have been sourced domestically by users.
- xxxiii. As regard contention that increase in dumped imports is required to be shown, it was submitted that the petitioner has demonstrated positive dumping margin and increase in dumped imports from both countries.
- xxxiv. Petitioner has highlighted the imports made for Vedanta and due to varied prices in different regions, a comparison should be made accordingly. Reference to Rule 11(3) and proviso to Rule 2(b) is not required.
- xxxv. Prices of the subject goods increased only for a brief period and have steeply declined post 2017-18.
- xxxvi. The domestic sales of the domestic industry have declined during the period of investigation.
- xxxvii. Improvement in performance, as reported in annual report of Grasim and GACL does not relate to the period of investigation. The performance has deteriorated in the period of investigation and there have been financial losses in the subsequent period.
- xxxviii. Likelihood analysis is required to be done for subject countries as whole and not individual exporters. The fact that individual exporters are facing nil rate of duty is irrelevant for such analysis.
- xxxix. Domestic industry was able to achieve capacity utilization of 93% in 2015-16, contrary to the claim of the respondents that 85-90% capacity utilization is optimum. However, even if 85-90% is considered as the optimum utilization, the capacity utilization in China PR was less than 80%, implying significant unutilized capacities.
- xl. The petitioner having established surplus capacities with producers, price attractiveness of Indian market need not be separately established since had the producers been capable to export further quantities to other markets, they would have fully utilized their capacities, in order to cover their fixed costs.

- xli. Since the exporters have not found a market in third countries at higher prices and have been forced to lower their prices, they would be willing to divert such exports to India even at a slightly higher price. The price of exports to third countries demonstrates the minimum price, at which the exporters would be willing to export to the Indian market.
- xlii. Data on record demonstrates that India is second largest market following Australia for exporters in Korea RP. Further, as per respondents' own admission, price of exports to India being lower than price of exports to Australia, implies that the Indian market is more lucrative for the exporters.
- xliii. Information regarding inventories of the foreign producers is confidential in nature, and the domestic industry does not have access to the same. Further, since no likelihood has been claimed on such ground, the information is irrelevant in present case.

H.2. Submissions of other interested parties

63. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to injury, likelihood and causal link.
- i. In the absence of relevant information from supporters, an effective analysis of the industry as whole, as per Rule 4(1)(c)(ii), Section 9B of the Customs Tariff Act and ruling of the Appellate Body in US – Hot Rolled Steel, is not possible. The Authority should call for information from other producers as well.
 - ii. The petitioner has not provided post-period of investigation data, which is necessary for the likelihood analysis. If the petitioner is allowed to file data at such belated stage, appropriate time ought to be allowed to exporters to make comments and file their own data.
 - iii. The domestic industry has itself acknowledged that it has not suffered injury. Absence of injury to the industry implies that the anti-dumping duties have served the purpose and must be allowed to expire.
 - iv. The petitioner has relied on the ruling of the Appellate Body in US – OCTG from Mexico, to claim that there is no requirement to show causal link. However, it has failed to show likelihood of dumping or injury, which is the prerequisite under the aforesaid ruling.
 - v. The petitioner has claimed an increase of 7703%, which is misleading as the imports were lower in 2018-19 due mandatory BIS certification. As compared to the base year, the market share of imports has increased only marginally.
 - vi. The share of imports from subject countries has increased due to lack of BIS certification by producers of other countries and is not a long-term trend.
 - vii. The petitioner is not required to show increased imports, but increase in dumped imports. However, in the present case, the exporters have not engaged in dumping.
 - viii. The data relating to price undercutting on the basis of regional analysis has been claimed confidential.
 - ix. Price undercutting based on prices in East India is not appropriate as the petitioner has not established that the conditions provided under Rule 11(3) and proviso to Rule 2(b), regarding isolated market, have been satisfied. The petitioner was required to show that (a) East India operates as an isolated market (b) the petitioners sell all or nearly all their production only in East India (c) the demand in East India is not met by producers in any other part of India. However, of all petitioners, only one plant is located in East India, which could not have led to creation of an isolated market. Further, East India is an undefined territory and there is significant ambiguity on what constitutes this region.
 - x. The profits and cash profits of the domestic industry have increased, even after resumption of imports post BIS certification and despite positive undercutting in certain regions.
 - xi. The annual report of Grasim (2017-18) shows that prices of caustic soda have increased due to (i) weather related disruption in US; (ii) phasing out of mercury-based technology in Europe, and (iii) capacity shutdown in China due to environmental concerns.
 - xii. The production and sales of the domestic industry have increased.

- xiii. The annual report of Grasim (2018-19) and for GACL (2017-18) also show that their performance has improved.
- xiv. The petitioner has not provided sufficient evidence to demonstrate likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury in the form of significant rate of increase of imports, sufficient freely disposable capacities, imminent increase in capacities, price attractiveness of Indian market or significant inventories.
- xv. Since the exporters are already facing nil rate of duty, cessation of duty will have no impact on volume of imports.
- xvi. Non-tariff barriers like BIS certification are likely to discourage imports and thus, the imports are not likely to increase as a result of imposition of duties. Continuation of BIS certification would result in a substantial decline in the imports due to the highly technical procedural and time-consuming requirements and associated costs of obtaining certification. Foreign producers are required to undergo a renewal process for licensing in the 3rd year and every alternate year thereafter, bearing significant administrative and application costs.
- xvii. Owing to challenges associated with the certification, major producers have elected not to apply for BIS certification and less than 5% of the global caustic soda producers have received licenses.
- xviii. Grant of BIS licenses to foreign manufacturers is now being reviewed in a manner such that no foreign manufacturers will be granted such further licenses or provided extensions of existing licenses. Licenses to manufacturers have remained pending even after one year of the application, and close to a year since completion of all related factory inspections.
- xix. The DPIIT has imposed limitations on public procurement from foreign suppliers, which further indicates that imports are not likely to increase in the event of cessation of duty, particularly since major consumers like NALCO are now prohibited from foreign procurement.
- xx. Expansion of capacity claimed by the petitioner is based on press releases of other companies and no evidence has been provided for cooperative exporters.
- xxi. Capacity utilization of 85-90% is often considered optimal in most chemical industries. Even the optimal capacity utilization of the domestic industry was 89% at its peak performance in 2018-19, and has remained between 85-90% for the last 10 years.
- xxii. In the sunset review investigation into imports of caustic soda, the Designated Authority noted that mere surplus capacity is not sufficient to show likelihood and further evidence is required to show that injury would occur.
- xxiii. Since the cooperative exporters have not practiced dumping in last five years or during earlier review, there is no question of likelihood of continuation or recurrence of dumping.
- xxiv. Even if there are surplus capacities in the subject countries, the petitioner is required to show that India is a price attractive market.
- xxv. The petitioner has not demonstrated price attractiveness of the Indian market. Rather, it has referred to exports priced below the non-injurious price of the domestic industry.
- xxvi. Even if the exports to third countries were to shift to India, they would not shift to India at the same price, contrary to the claims of the petitioner.
- xxvii. Since the cooperative exporters do not have any duties, they would have no incentive to shift exports to India, in the event of expiry of duty.
- xxviii. Significant volumes are being imported from Japan, Iran and Qatar.
- xxix. An analysis of exports from Korea RP as a whole to other countries filed by the cooperating exporters shows that Australia accounts for significant volumes of exports for lye. Though the price of such exports is lower than price of exports to India, they contribute significantly higher volumes. Other major markets for lye are USA, United States Minor Outlying Islands, Malaysia and Japan. Further, major markets for flakes are Vietnam, Indonesia, USA, Thailand and Bangladesh, while the Indian market does not have much demand for it.
- xxx. The petitioner has not provided any evidence of inventories of the subject goods. The responses filed show that the cooperative exporters are not maintaining significant inventories.

H.3. Examination by Authority

64. The Authority has taken note of the arguments and counter-arguments of the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The injury analysis by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.
65. Rule 11 of the Rules read with its Annexure-II thereto provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles."
66. Rule 23 of the Rules provides that the provisions of Rule 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, and 20 shall apply mutatis mutandis in case of a review. In case the performance of the Domestic industry shows that it has not suffered injury during the current injury period, the Authority shall determine whether cessation of the present duty is likely to lead to recurrence of injury to the Domestic industry.
67. The Authority has examined current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject country. It has been examined as to whether there is an increase in imports, in absolute terms or in relation to production or consumption. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure-II of the Rules. The Authority has taken note of various submissions of the domestic industry and other interested parties, and has analyzed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the parties.
68. With regard to the contention of the other interested parties regarding lack of information regarding supporters, the Authority notes that as per Rule 11(2) of the Rules, Authority is required to "*determine the injury to domestic industry, threat of injury to domestic industry, material retardation to establishment of domestic industry*". Therefore, the evaluation of injury is required to be restricted to the defined domestic industry, and the performance of other producers is irrelevant. Since all the information essential for the determination of injury to the domestic industry is made available by the participating producers, the information about performance of supporting producers is irrelevant for such analysis.

I. Assessment of Demand / Apparent Consumption

69. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product concerned in India as the sum of domestic sales of the domestic industry and other Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annualised(Annl)
Including captive						
Domestic industry	MT	13,77,694	13,81,792	15,52,722	11,47,602	15,30,136
Other producers	MT	15,00,689	16,50,367	17,70,249	13,44,626	17,92,835
Subject imports	MT	55,210	61,030	1,542	86,056	1,14,741
Other imports	MT	3,69,378	3,59,549	2,04,909	1,46,086	1,94,782
Demand	MT	33,02,971	34,52,738	35,29,422	27,24,370	36,32,494

Excluding captive						
Domestic industry	MT	10,06,750	10,24,376	11,58,389	8,11,538	10,82,051
Other producers	MT	15,00,689	16,50,367	17,70,249	13,44,626	17,92,835
Subject imports	MT	55,210	61,030	1,542	86,056	1,14,741
Other imports	MT	3,69,378	3,59,549	2,04,909	1,46,086	1,94,782
Demand	MT	29,32,027	30,95,322	31,35,089	23,88,306	31,84,408

70. It is seen that the demand for the subject goods has been steadily increasing throughout the injury period and has increased by 10% over the period.

II. Volume Effects of Dumped Imports

71. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction wise import data procured from DGCI&S. The import volumes of the subject goods from subject country and share of the dumped import during the injury investigation period are as follows:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annl.
Subject imports	MT	55,210	61,030	1,542	86,056	1,14,741
China	MT	40,326	42,357	1,542	43,957	58,609
Korea RP	MT	14,884	18,673	-	42,099	56,132
Other imports	MT	3,69,378	3,59,549	2,04,909	1,46,086	1,94,782
Total Imports	MT	4,24,588	4,20,579	2,06,451	2,32,142	3,09,523
Imports in relation to						
Indian production	%	2%	2%	0%	3%	3%
China PR	%	1%	1%	0%	2%	2%
Korea RP	%	1%	1%	0%	2%	2%
Consumption	%	2%	2%	0%	3%	3%
China PR	%	1%	1%	0%	2%	2%
Korea RP	%	0%	1%	0%	2%	2%
Total imports	%	13%	15%	1%	37%	37%
China PR	%	9%	10%	1%	19%	19%
Korea RP	%	4%	4%	0%	18%	18%

72. It is seen that:
- Volume of imports from subject countries increased till 2017-2018 but declined steeply in 2018-19. This decline was apparently due to the mandatory requirement to comply with BIS standards. However, post such decline, the imports have increased steeply in the period of investigation.
 - Even when compared to the beginning of the injury period, that is, pre-introduction of BIS, the imports have shown an increase during the period of investigation.
 - However, imports have increased very marginally in relation to production and consumption over the injury period.
 - The interested parties contended that mandatory requirements of BIS standards led to decline in imports. The domestic industry contended that it was only for a short period that none of the foreign producers had licence and it was also their own lack of efforts to obtain licences in a timely manner. The Authority considers it appropriate to ignore the year 2018-19 in so far as it concerns volume of imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India.

III. Price Effect of Dumped Imports

73. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. In this regard, a comparison has been made between the landed price of imports from the subject country with the net sales realization of domestic industry for the subject goods.

a. Price Undercutting

74. To determine price undercutting, a comparison has been made between the landed value of the product and average selling price of the domestic industry, net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at the ex-factory level.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
China PR					
Selling price	Rs/MT	***	***	***	***
Landed price	Rs/MT	27,178	34,476	39,317	34,985
Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	% Range	0-10	0-10	Negative	Negative
Korea RP					
Selling price	Rs/MT	***	***	***	***
Landed price	Rs/MT	27,702	37,604	-	33,200
Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	% Range	0-10	Negative	-	Negative
Subject countries					
Selling price	Rs/MT	***	***	***	***
Landed price	Rs/MT	27,319	35,433	39,317	34,112
Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	% Range	0-10	0-10	Negative	Negative

75. It is noted that the imports were not undercutting the prices of the domestic industry. The selling price of the domestic industry was above the landed price of imports. The domestic industry claimed that this was due to consideration of weighted average selling price of the domestic industry, when imports were limited only in one region. The selling price of the domestic industry in different regions varied significantly, due to difference in freight costs. The imports have been made by Vedanta Limited located in the East. Accordingly, if the price of domestic industry in East India is compared to the landed price of imports, the price undercutting is positive. However, the Authority considers net ex-factory selling price of the domestic industry for determination of price undercutting and considers it appropriate to follow the consistent practice in this regard. Thus, it is noted that price undercutting during the POI is negative from all subject countries.

b. Price Suppression / Depression

76. In order to determine whether the effect of imports is to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred, the information given by the domestic industry for the changes in the costs and prices over the injury period has been compared with the landed value to see the desired effect.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Cost of sales	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	111	112	113
Selling price	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	126	130	112
Landed price	Rs/MT	27,319	35,433	39,317	34,112
Trend	Indexed	100	130	144	125

77. It is seen that the landed price of imports, cost of sales and selling price of the domestic industry increased till 2018-19. However, while the cost of sales remained in similar region in the POI, the import price and selling price of the domestic industry declined significantly in the POI. However, the landed price was above the cost of sales and selling price of the domestic industry.

IV. Impact on Economic Parameters of the Domestic Industry

78. Annexure II to the Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

a. **Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales Volumes**

79. The performance of the domestic industry with regard to production, domestic merchant sales, captive consumption, capacity and capacity utilization is as follows:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annl.
Capacity	MT	15,31,160	15,55,261	17,42,350	13,08,013	17,44,017
Production	MT	13,82,905	14,06,481	15,45,924	11,67,738	15,56,984
Capacity utilization	%	90%	90%	89%	89%	89%
Domestic sales	MT	12,77,886	12,62,893	14,30,185	10,28,833	13,71,778
Captive sales	MT	***	***	***	***	***

80. It is seen though the capacity of the domestic industry increased over the years. The domestic industry was able to increase its production, and largely maintain its capacity utilization.

b. **Market Share in Demand**

81. Market share of alleged dumped imports and domestic industry have been examined as below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Share in demand (including captive)					
Domestic industry	%	42%	40%	44%	42%
Other producers	%	45%	48%	50%	49%
Subject imports	%	2%	2%	0%	3%
Other imports	%	11%	10%	6%	5%

Share in demand (excluding captive)					
Domestic industry	%	34%	33%	37%	34%
Other producers	%	51%	53%	56%	56%
Subject imports	%	2%	2%	0%	4%
Other imports	%	13%	12%	7%	6%

82. It is seen that the market share of the domestic industry had improved till 2018-19 but has declined during the period of investigation, as the imports increased and gained market share. Overall, there is no decline in the market share of the domestic industry during the injury period while market share of the imports have shown a marginal increase.

c. Inventories

83. Inventory position of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Average inventory	MT	13,791	18,593	20,351	19,522
	Indexed	100	135	148	142

84. It is seen that the average inventory has increased over the injury period except in comparison to 2018-19.

d. Profits, Cash Profits and Return on Capital Employed

85. Profits, return on investment and cash profits of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annul
Cost of sales	Rs/MT	***	***	***	***	***
	Indexed	100	111	112	113	113
Selling price	Rs/MT	***	***	***	***	***
	Indexed	100	126	130	112	112
Profit / loss	Rs/MT	***	***	***	***	***
	Indexed	100	183	199	106	106
Profit / loss	Rs Lakhs	***	***	***	***	***
	Indexed	100	181	222	113	113
Cash profits	Rs Lakhs	***	***	***	***	***
	Indexed	100	168	205	118	118
Return on capital employed	%	***	***	***	***	***
	Indexed	100	152	190	102	102

86. It is seen that profits and cash profits earned by the domestic industry show an increase upto the year 2018-29. However, post 2018-29, the profitability of the industry has reduced sharply in the period of investigation. Further, the performance of the domestic industry shows deterioration even after ignoring 2018-19. However, the operating performance of the domestic industry has not been adversely affected during the POI as compared to base year though it has declined significantly in the POI as compared to the preceding year.

e. Employment, Wages and Productivity

87. The Authority has examined the information relating to employment, wages and productivity, as given below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annl.
No. of employees	Rs/MT	4,728	4,899	5,440	5,329	5,329
Wages	Rs Lakhs	***	***	***	***	***
	Indexed	100	108	121	91	122
Productivity per day	MT/Day	3,841	3,907	4,294	4,325	4,325

88. It is seen that the number of employees has increased over the injury period, leading to an increase in total wages. Further, the productivity of the domestic industry has also improved over the period.

f. Growth

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Considering previous year	Considering 2017-18
Production	%	-	2	10	1	11
Domestic Sales	%	-	(1)	13	(5)	9
Profit/Loss	%	-	81	42	(109)	(67)
Cash Profit	%	-	68	37	(87)	(50)
Return on capital employed	%	-	52	38	(87)	(50)

89. It is seen that the performance of the domestic industry in both volume and profitability parameters has shown growth upto 2018-19. However, during the period of investigation, the domestic industry has witnessed negative growth in its sales, and its profitability parameters. Considering the BIS licence requirements in 2018-19, the Authority also determined growth considering the parameters in 2017-18 and found that the growth of the domestic industry in the POI was negative as compared to 2017-18 in respect of price parameters, while the same was positive in respect of volume parameters.

g. Ability to Raise Capital Investment

90. The Authority notes that while the profits and return on capital employed of the domestic industry declined during the period of investigation, it has been able to earn a reasonable return. Thus, it cannot be considered that the imports have impacted the ability of the domestic industry to raise capital investment.

h. Magnitude of Dumping

91. It is noted that the subject goods are being dumped into India and the dumping margin is positive and significant for China PR, while for Korea, it is considered significant for non-cooperating producers and exporters.

I. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

92. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The Non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. It

is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed.

93. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below. It is noted that injury margin is negative for both the cooperating producers and exporters from Korea and China PR, while the same is positive for other producers and exporters from both the subject countries.

Injury Margin Table

Country	Producers	NIP (USD/MT)	Landed value (USD/MT)	Injury Margin (USD/MT)	Injury Margin %	Injury Margin % Range
Korea RP	Hanwha Solutions Corporation	***	***	***	***	(10-20)
Korea RP	Others	***	***	***	***	10-20
China PR	Tianjin Dagu Chemical Co Ltd	***	***	***	***	(20-30)
China PR	Others	***	***	***	***	50-60

J. CAUSAL LINK AND NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

94. As per the Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the domestic industry:

a. Volume and Prices of Imports from Third Countries

95. It is to be seen that there are significant imports from other countries such as Japan, Iran, Oman and Qatar. However, such imports have not caused any injury to the domestic industry during the present injury period.

b. Contraction in Demand

96. It is to be seen that the demand for the subject goods has increased over the injury period. Therefore, contraction in demand cannot be considered as a reason for the likely injury to the domestic industry.

c. Developments in Technology

97. It is noted that the technology for producing subject goods has not undergone any change and therefore, is not likely to cause injury to the domestic industry.

d. Conditions of Competition and Trade Restrictive Practices

98. The investigation has not shown that conditions of competition or trade restrictive practices may result in injury to the domestic industry.

e. Export Performance of the Domestic Industry

99. The injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market. Thus, the likely injury to the domestic industry cannot be attributed to its export performance.

f. Productivity

100. The productivity of the domestic industry has improved over the period, and thus, the likely deterioration in performance of domestic industry cannot be attributed to a decline in productivity.

J.1. Conclusion on continuation of injury and causal link

101. Examination of the imports from the subject country and performance of domestic industry shows that despite anti-dumping duties in force, the imports from the subject country have remained significant, and have increased in absolute terms, and also increased in relation to production and consumption in India. The sales and market share of the domestic industry have declined during the period of investigation as compared to previous year, despite an increase in production and demand. The imports were not undercutting the prices of the domestic industry during the POI. While the profits, cash profits and return on investment of the domestic industry improved till 2018-19, these declined in the POI, as compared to preceding year, 2017-18 and base year. Overall, there is no significant adverse impact on the domestic industry during the injury period. Thus, there is no injury to the domestic industry during the injury period.

K. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

102. The Authority observes that this is a sunset review investigation, the focus of this investigation is to examine the likely scenario of continued dumping and consequent injury if anti-dumping duties is to be allowed to expire even if there is no current injury. This also requires a consideration of whether the duty imposed is serving the intended purpose of eliminating injurious dumping.
103. All factors brought to the notice of the Authority have been examined to determine as to whether there is a likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury in the event of cessation of the duty. The Authority has considered various information, as made available by the domestic industry, in order to evaluate the likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury.
104. There are no specific methodologies available to conduct such a likelihood analysis. However, Clause (vii) of Annexure II of the Rules provides, inter alia for factors which are required to be taken into consideration viz.:
- i. A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation;
 - ii. Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;
 - iii. Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and
 - iv. Inventories of the article being investigated.
105. Further, the Authority has also examined other relevant factors having a bearing on the likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry. The examination of the parameters of likelihood is as follows.
106. Insofar as the arguments of the cooperative foreign producers regarding their own capacities and exports are concerned, it is noted that the likelihood analysis must be conducted for the subject countries, and not for individual producers in those countries. Therefore, in addition to the information given by the responding exporter, the Authority has also considered information for exporting country cumulatively for all producers/exporters.

a. Continued dumping of the subject goods

107. The Authority notes that the dumping of the subject goods has continued from China PR, in spite of the duties in force. For the cooperative producer from China PR, the dumping margin is positive while the injury margin is negative. For non-cooperating producers from China PR, the dumping and injury margins are positive. Thus, in the absence of duties, the dumping of the subject goods is likely to continue, and they are likely to injure the domestic industry in India. However, insofar as Korea RP is concerned, the only producer whose goods were exported to India during the period of investigation were found at un dumped prices while the dumping and injury margins for non-

cooperating producers/exporters from Korea is positive. However, the Authority notes that there are other Korean producers who have not cooperated in the present investigation. Further, it is also seen that there has been positive dumping and injury margins for the non-cooperative producers from Korea. Although there is no continuation of injury during the POI, continued dumping at an injurious price from Korea creates a significant likelihood for an intensification of dumped imports from non-cooperating producers from Korea RP if duties are discontinued.

b. Volume of imports and increase in imports in presence of anti-dumping duties

108. The Authority notes that there were significant imports from subject countries in absolute terms in present period. It is also noted that though the overall volume of imports have come down during the POI from the base year, the volume of imports from subject countries have increased significantly from the preceding year. Thus, the fact that the imports have increased despite duties in force indicates that the imports are likely to increase further in the event of cessation of duties. Further, the Authority notes that the imports have increased at a faster pace than the increase in demand for the subject goods, thereby indicating that the imports are likely to adversely impact the market share of the domestic industry in the market, in the absence of duties.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annl.
Subject imports	MT	55,210	61,030	1,542	86,056	1,14,741
Increase from base year	%	-	11	(97)	108	108
China PR	MT	40,326	42,357	1,542	43,957	58,609
Increase from base year	%	-	5	(96)	45	45
Korea RP	MT	14,884	18,673	-	42,099	56,132
Increase from base year	%	-	25	(100)	277	277
Demand	MT	3,302,971	3,452,738	3,529,422	27,24,370	36,32,494
Increase from base year	%	-	5	7	10	10

109. Regarding the contention that the imports are not likely to increase further, due to BIS licensing and public procurement requirements, it is noted that the data on record shows that the imports have increased, despite BIS licensing and public procurement requirements. Thus, it cannot be concluded that the imports are not likely to increase, in the event of cessation of duties.

c. Freely disposable capacities present with subject countries

110. The Authority notes that the domestic industry has adduced evidence of surplus capacities for China PR as well as North East Asia. However, no separate information for Korea RP has been provided. The Authority has examined the information with regard to surplus capacities for China PR as below.

Particulars	Unit	China PR
Total capacities	Lakh MT	450
Domestic demand	Lakh MT	350
Exportable capacity	Lakh MT	100
Capacity utilization	%	79%
Unutilized capacity	Lakh MT	94.5

111. The Authority notes that there are significant idle capacities in China PR, especially when compared to the demand of only 36.32 lakh MT in India. Further, even if the claim of the interested parties with regard to the optimum capacity utilization in the present product (90%) is accepted, it is seen that the Chinese producers nevertheless hold capacities significant enough to meet the entire Indian demand.

d. Imminent significant expansion in production capacities

112. The domestic industry has provided information regarding expansion of capacities, which shows that the capacities in China PR are likely to increase by 16.7 lakh MT per annum by 2023, implying an average capacity expansion of about 4 lakh MT per annum. In comparison, the demand in India increases only by about 1 to 1.5 lakh per annum. Further, the Chinese producers are already holding surplus capacities. This significant increase in capacities is likely to result in increased availability of the product and is likely to be exported to India at dumping prices, in the event of cessation of duty.

e. Decline in exports from the subject countries

113. The information provided by the domestic industry shows that the exports from the subject countries to rest of the world have declined over the recent period. While exports to India increased, the overall exports declined.

Particulars	2016-17	2017-18	2018-19	POI Actuals	POI Annualized
Total Exports					
China	1,848,968	1,389,656	998,656	951,104	1,268,138
Korea	483,751	392,401	427,670	261,319	348,425
Subject Countries	2,332,720	1,782,057	1,426,326	1,212,422	1,616,563
India					
China	77,096	42,346	178	40,504	54,005
Korea	14,841	26,304	-	42,100	56,133
Subject Countries	91,936	68,650	178	82,604	110,139
Rest of world					
China	1,771,873	1,347,310	998,478	910,599	1,214,132
Korea	468,911	366,097	427,670	219,219	292,292
Subject Countries	2,240,783	1,713,407	1,426,148	1,129,818	1,506,424
Source: Trade map data					

f. Price attractiveness of the Indian market

114. The Authority notes that the exporters have been exporting significant volumes of subject goods to other countries at prices lower than the selling price in India, as summarized in the table below.

Country	Exports to third countries (MT)	Exports at prices lower than price to India (MT)	Share in third country exports (%)	In relation to merchant demand in India (%)
China PR	9,51,103	4,50,250	47%	17%
Korea RP	2,61,319	1,48,393	57%	5%
Total	12,12,422	5,98,643	49%	22%

115. In the event of cessation of duties, such exports are likely to be diverted to India due to the comparative price attractiveness of the country.
116. It is also noted that a significant volume of exports of subject goods from subject countries are being made at prices which are undercutting the domestic industry prices, and also are lower than NIP suggesting likelihood of recurrence of injury to the domestic industry.
117. Based on the data provided by the cooperating producers China PR, the Authority notes that exports to India are priced higher than exports to third countries. In view of the same, Indian market for the cooperating producer found to be price attractive market. Further, besides the cooperating producer, no significant exports were made from China PR.

g. Analysis of Post-POI Data

118. The post-POI data submitted by the domestic industry shows that both the volume and the price of imports has declined significantly during the subsequent period. Further, the domestic industry has suffered a decline in production, sales, capacity utilization, profits, cash profits and return on capital employed. The domestic industry has incurred losses in this period.

L. POST-DISCLOSURE COMMENTS**L.1. Submissions of the domestic industry**

119. The domestic industry largely reiterated the submissions made earlier. In particular, the domestic industry emphasized the following.
- There is continued dumping of the subject goods from the subject countries, and the imports have increased even with the duties in force.
 - There are significant surplus capacities in subject countries, and exports to third countries are also likely to be diverted to the Indian market, owing to its price attractiveness.
 - The price undercutting is negative only because of the imports being made in the East, whereas the domestic industry has sold the subject goods throughout the country. The prices in the East should be considered for determination of price undercutting, as the product entails significant freight cost.
 - There is no need for determination of injury margin as the domestic industry has sought extension of duty. If the injury margin is determined, difference in inland freight cost should be adjusted.

L.2. Submissions of other interested parties

120. Other interested parties have also reiterated their submissions. In addition, the interested parties have submitted as under.
- In cases such as the present one, wherein different members of the AMAI have been selectively participating in a series of investigations over the years, Trade notice no.13/2018 serves as an important tool for the Authority to verify the claims made by the Petitioners and the same should be followed.
 - The Authority has not appropriately considered the claims made by the interested parties relating to excessive confidentiality.
 - The Authority has noted at paragraph 53 that ***% of the domestic sales found to be profitable. The same ought to be considered confidential and not disclosed to the public.
 - At paragraph 63 (xxix) the Authority has erroneously recorded the argument of the cooperating exporters from Korea as stating that Australia accounts for significant volumes of exports for lye by the cooperating exporters. As was clarified in the rejoinder submissions, the analysis presented does not refer to the data of the cooperating exporters but to exports from Korea as a whole. The same should therefore be rectified in the final findings.
 - Impact of BIS:** The Authority has noted at paragraph 72 that even when compared to the beginning of the injury period, that is, pre-introduction of BIS, the imports have shown an increase during the period of investigation. While the overall imports of the PUC have increased since the base year, the market share of imports from the subject countries in demand has remained low throughout the injury period and POI. The share of imports from China and Korea in the POI is a mere 2.26 and 2.16 percent respectively as against 1.23 and .54 percent before the implementation of BIS certification in 2018. Compared to the base year as well, the market share in demand of both subject countries has gone up only marginally when compared to the market share in demand of the Domestic Industry as well as other countries.
 - Injury and Causal Link:** The cooperating exporters have reiterated that there is a lack of material injury and causal link in the present investigation. Any perceived injury suffered during the post-POI period is attributable to factors other than dumping – significant evidence in this regard has already been placed on record.

- g. Continuation of NIL Duty for Cooperating Producers and Exporters: The dumping margin and injury margin for the cooperating exporters from Korea were negative in the original finding as well as in all subsequent investigations, including the present review. Similarly, the cooperating exporters from China submit their dumping margin and injury margin were negative in previous investigation, and the injury margin continues to be negative in the present review as well. Therefore, the cooperating Exporters' NIL margin ought to be continued.

L.3. Examination by the Authority

121. The submissions by the interested parties were mostly repetitive in nature, and have already been addressed at the relevant place in the finding. The Authority has examined the remaining submissions herein below.
122. As regards the determination of price undercutting is concerned, the Authority notes that the domestic industry has not demonstrated the need for region-wise undercutting. Merely because the imports have been made in East does not indicate the need for a region-wise undercutting, as East India does not operate as an isolated market. It has not been demonstrated that the imported goods were not available at same prices in other markets.
123. As regards the determination of injury margin, it is noted that inclusion of freight of the domestic industry in non-injurious price will not be in line with the consistent practice followed in this regard and Annexure – III of the Anti-Dumping Rules. Accordingly, the inland transport cost incurred by DI has not been included in their NIP.
124. On the issue of the supporter's data not being filed the Authority notes that it had invited all interested parties to file their claims with appropriate evidences and formats as applicable. The supporters have chosen to provide limited support to the domestic industry members. Accordingly, the Authority has made its determination based on the information filed on record.
125. As regards the claim on confidentiality, the Authority reiterates that it has assessed the allegations presented by the interested parties on the domestic industry's violations of the trade notice requirements, and has found the domestic industry's claims on confidentiality to be in line with the trade notice and the confidentiality requirements under the Anti-dumping Rules.
126. With regard to the averments regarding BIS certification, the Authority notes that despite the existence of the BIS requirement, the import volumes have largely normalized to pre-BIS levels whereby the parameters of likelihood and evidence placed on record have been considered while determining whether or not duties should be continued in the present review.
127. With regard to the claim that there is no injury to the domestic industry, the Authority notes that the final determination has been made keeping in mind all the information placed on record concerning dumping injury as well as causal link. Given that the present investigation is a sunset review, the determination cannot solely be based on the absence of injury to the domestic industry, and the Authority has also take into consideration the likelihood of continuation or recurrence of injury in case duties are allowed to expire.
128. With regard to the request for continuation of NIL margins for individual cooperating exporters, the same are addressed in the duty table.

M. CONCLUSION ON LIKELIHOOD OF DUMPING AND INJURY

129. The evidence on record shows that there is likelihood of dumping of the subject goods and injury to the domestic industry. The volume of imports has increased in absolute terms, and in relation to production and consumption, even after excluding the period when BIS was introduced, and the foreign producers did not have licenses. The domestic industry has not suffered injury during the present injury period. However, the data on record shows that the exporters in the subject countries have significant surplus capacities. It is also noted that while their exports to third countries are declining, exports to India have increased at the same time. It is also noted that India is a price attractive market for the subject exporters as significant exports to third countries are at a price below normal value of the exporters, and also below the selling price and non-injurious price of the domestic industry. Exports to India are likely to increase significantly in the event of cessation of antidumping duty and the same is likely to cause injury to the domestic industry in India. Thus, in the event of cessation of anti-dumping duty, dumping of the subject goods is likely to intensify, causing injury to the domestic industry.

N. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

130. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty, in general is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country/territory in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.
131. It is recognized that the imposition of anti-dumping duty might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measure, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measure would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

O. CONCLUSION

132. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority, as recorded in the above findings, and on the basis of the above analysis of the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, the Authority concludes that
- In the event of expiry of duty, the product under consideration is likely to be dumped in significant volumes.
 - The domestic industry is likely to suffer injury in case the anti-dumping duty in force is allowed to cease at this stage.
 - There is sufficient evidence to indicate that cessation of anti-dumping duty at this stage will lead to recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

P. RECOMMENDATIONS

133. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and the causal link.
134. Having concluded that there is positive evidence of likelihood of dumping and injury if the existing anti-dumping duties are allowed to cease, the Authority is of the view that the anti-dumping duty in force on imports of the product under consideration from the subject countries is required to be continued further. Considering the facts and circumstances of the case, as established hereinabove, the Designated Authority considers it appropriate to recommend extension of the existing quantum of anti-dumping duties on imports of subject goods from China PR and Korea RP, except in respect of those producers who have not participated in the current sunset review investigation. Those non-cooperating producers and exporters in this sunset review investigation have been accorded residual duty as applicable at present. Accordingly, the anti-dumping duties for responding producers and non-cooperative producers from subject countries are recommended as per the duty table below. The Authority, thus, considers it necessary to recommend continuation of definitive anti-dumping duty as modified, on all imports of the subject goods from the subject countries as per column 7 in the duty table below, for a further period of five years.

Duty Table

S. No (1)	Sub-heading (2)	Description of goods (3)	Country of origin (4)	Country of export (5)	Producer (6)	Amount (7)	Unit of Measurement (8)	Currency (9)
1	281511 and 281512	Caustic soda, of all grades	Korea RP	Korea RP	Hanwha Solutions Corporation	Nil	Dry Metric Ton	USD
2	- do -	- do -	Korea RP	Any country, including Korea RP	Any producer, other than S. No. 1 above	21.90	Dry Metric Ton	USD
3	- do -	- do -	Any country other than subject countries	Korea RP	Any	21.90	Dry Metric Ton	USD
4	- do -	- do -	China PR	China PR	Tianjin Dagu Chemical Co., Limited	Nil	Dry Metric Ton	USD
5	- do -	- do -	China PR	Any country, including China PR	Any producer, other than S. No. 4 above	48.39	Dry Metric Ton	USD
6	- do -	- do -	Any country other than subject countries	China PR	Any	48.39	Dry Metric Ton	USD

135. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time.

136. An appeal against the order of the Central Government arising out of these findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

B. B. SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority